चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 06 जून- 12 जून 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

विनाश की तरफ

पानी के पदचिह्न

शशि शेखर

देश की 33 फीसदी आबादी पानी के अभाव से त्रस्त है. अकेले महाराष्ट्र के करीब 20 हजार गांव सूखे की चपेट में हैं. बुंदेलखंड से लोगों का पलायन सिर्फ पानी की वजह से हो रहा है. देश के कई हिस्सों में बंदूकधारी पानी पर पहरा दे रहे हैं. मानसून के कमजोर होने से देश के 91 प्रमुख जलाशयों में महज 25 फीसदी पानी ही शेष रह गया है. ऐसे में, देश में पानी पर सिवाए मन की बात के और कोई चर्चा होती नहीं दिख रही है. मन की बात भी ऐसी जिसमें किसी मुक्कमल उपाय पर चर्चा की जगह पानी बचाने की सनातन नसीहत सुनने को मिली. अभी तक भारत समेत पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर काफी बहस होती रही है. प्रदूषण को कम करने के लिए कार्बन फुटप्रिंट की भी बात होती है. हर एक उत्पाद, हर एक कंपनी की जांच होती है कि वह कितना कार्बन उत्सर्जित करती है. वैश्विक प्रयासों की वजह से इस दिशा में प्रगति होती दिखी भी है. लेकिन, अब दुनिया के सामने एक नई समस्या है, पानी की कमी. अगर, हम सिर्फ भारत की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में ही यह देखने को मिला है कि देश के 13 राज्य भीषण सूखे की चपेट में हैं. लातूर से लेकर बुंदेलखंड और गुजरात से लेकर तेलंगाना तक में इंसान तो इंसान, जानवर भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं. ऐसे में, पानी को लेकर तमाम तरह के तर्क-कुतर्क दिए जा रहे हैं. कुछ लोग इस गंभीर समस्या को मानसून से जोड़कर देखते हैं, कुछ इसे भौगोलिक और पर्यावरणीय समस्या मानते हैं. मानवीय कारण पर चर्चा के मामले में सिर्फ इतना सुनने को मिलता है कि आम आदमी को पानी कम खर्च करना चाहिए, हिसाब से खर्च करना चाहिए. लेकिन, कोई यह नहीं बताता कि पानी के खर्च को कम कैसे करें? कोई यह नहीं बताता कि एक किलो कपास या गन्ना उगाने में कितना पानी खर्च हो रहा है? कोई यह भी नहीं बताता कि कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियां या बोतलबंद पानी बेचने वाली कंपनियां नदियों और ज़मीन का कितना पानी सोख रही हैं. कोई यह भी नहीं पूछता कि पिछले 25 सालों में विभिन्न राज्य सरकारों ने वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए कितने तलाब, कुएं, नहरें आदि खुदवाईं, कितनी योजनाएं बनाईं?

सबसे पहले हम एक डाटा देखते हैं. दो आकड़े हैं एक 1951 का और दूसरा 2001 का. भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता जहां 1951 में 14,180 लीटर थी, वह अब 5,120 लीटर हो गई है. यह भूमिगत जल का हिसाब है. ऐसा माना जा रहा है कि अगले दस सालों के बाद यानी साल 2025 तक यह उपलब्धता और घटकर करीब 3 हजार लीटर रह जाएगी, तो यह सवाल है कि फिर क्या होगा? और, 2025 या 2050 की बात भी रहने दें तो मौजूदा समय में ही देश के 13 राज्यों में पानी की जो हालत है, वह क्या कहानी कहती है, इसे हम सब देख और समझ रहे हैं. लेकिन, इस सब के लिए अगर हम सिर्फ मानसून को जिम्मेदार मानते हुए आंखें मूंदे रहें तो, फिर हमारी हालत भी उस शुतुरमुर्ग जैसी ही होगी जो शिकारी को सामने देखकर अपना सिर ज़मीन में घुसा लेता है और यह सोचता है कि शिकारी उसे नहीं देख रहा है. इसलिए, यह जरूरी हो जाता है कि सरकार और नागरिक समाज ईमानदारी से पानी संकट पर एक राष्ट्रीय बहस करें और पानी की कमी से बचने के रास्ते तलाशें. इसी कड़ी में हम इस कवर स्टोरी में दो मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं. पहला वाटर फुटप्रिंट और दूसरा कोल्ड ड्रिंक्स समेत बोतलबन्द पानी के व्यापार पर. हम इस बहस के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा पानी जा कहां रहा है और इस जल संकट के लिए मानवीय हस्तक्षेप कितना जिम्मेदार है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है.

दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा क्या है, इसकी जानकारी के लिए दुनियाभर में कार्बन फुटप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह, मानवीय हस्तक्षेप के कारण पानी की खपत कहां और कितनी हो रही है, इसे जानने के लिए आजकल एक नई अवधारणा प्रचलन में है, जिसका नाम है वाटर फुटप्रिंट. वाटर फुटप्रिंट बताता है कि आप अपनी जिन्दगी में हर दिन किन स्रोतों से कितनी मात्रा में पानी की खपत कर रहे हैं. आमतौर पर लोग यह मानते हैं कि पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए जितनी मर्जी हो, खपत कर सकते हैं. लेकिन, ऐसा है नहीं. हालांकि, दुनिया के कुछ हिस्सों में जरूर पानी अधिक है, लेकिन पानी के इस्तेमाल के वक्त यह याद रखना चाहिए कि दुनिया के कई हिस्से ऐसे भी हैं, जहां पानी बिल्कुल ही नहीं या बिल्कुल ही कम है. बहरहाल, इस स्टोरी के जरिए हम पानी से संबंधित उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिनपर या तो चर्चा ही नहीं होती. यदि होती भी है, तो उसकी जानकारी सीमित होती है. हम पानी से संबंधित, सत्य और संभावित खतरे के साथ ही समाधान पर भी बात करेंगे.

सबसे पहले हम कुछ पहलुओं को चिन्हित करते हैं. भारत पिछले कुछ सालों से पानी की भीषण कमी के दौर गुजर रहा है. आखिर, मानसून से संबंधित सवालों से अलग, पानी की इस कमी की वजह और क्या-क्या हैं. इसमें कृषि, बोतलबन्द पानी, पेय पदार्थों समेत पानी के घरेलू इस्तेमाल का कितना योगदान है? हम इस पर भी बात करेंगे कि जब हम सौ ग्राम चावल खाते हैं तो असल में हम उसके साथ कितने पानी का उपभोग करते हैं या फिर जब हम एक जींस पहनते हैं या एक कप कॉफी पीते हैं या एक लीटर बोतलबंद पानी पीते हैं या एक बोतल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तब हम कितने पानी की बर्बादी कर रहे होते हैं और इससे बचने के क्या रास्ते हो सकते हैं? हम इस पर भी बात करेंगे कि हमारी मौजूदा कृषि तकनीक कितनी गैरजिम्मेदारी के साथ भू-जल का दोहन कर रही है और इसमें किस तरह के बदलाव की जरूरत है? इसमें नागरिक समाज के साथ ही सरकारों की क्या भूमिका हो सकती है? और, अंत में यह भी कि कार्बन फुटप्रिंट की तर्ज पर वाटर फुटप्रिंट को अपनाकर कैसे हम इस दुनिया को तीसरे विश्वयुद्ध से बचा सकते हैं.

क्या कहती है राष्ट्रीय जल नीति 2012

कृषि क्षेत्र

- पानी के उपयोग कुशलता (एफिशिएंसी) में सुधार.
- वर्षा जल संचय (वाटर हार्वेस्टिंग) और वाटरशेड प्रबंधन तकनीक का उपयोग.
- ऊर्जा आपूर्ति खासतौर पर पंप वाटर के लिए ऊर्जा सब्सिडी में कटौती.
- डिफरेंशियल प्राइसिंग, पुरस्कार और दंड के प्रावधान को लागू करके भू-जल दोहन पर रोक.
- राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना को लागू करना, जिसका मक़सद 175 खरब लीटर पानी हासिल करने के लिए 30 नदियों और नहरों को जोड़ना है.

औद्योगिक क्षेत्र

- उद्योगों के गंदे पानी की रीसाइक्लिंग और प्रशोधन (ट्रीटमेंट) के लिए क़ानून और सब्सिडी के जरिया प्रोत्साहन.
- वैसी तकनीक का प्रोत्साहन करना जिसमें पानी की खपत कम हो.

घरेलू क्षेत्र

- शहरी क्षेत्र में अनिवार्य रूप से वर्षा जल संचय के लिए नीति बनाना.
- जल के उचित उपयोग के लिए प्रचार-प्रसार करना.
- आम लोगों में जल संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना.

हम न छोड़ें ऐसे निशान...

हर वस्तु के उत्पादन पर आभासी पानी की छाप होती है. इसे विज्ञान की भाषा में वर्चुअल वाटर फुट प्रिंट कहा जाता है. वर्चुअल वाटर वह पानी है जो किसी वस्तु को उगाने में, बनाने और उसके उत्पादन में लगता है. एक टन गेहूं उगाने में करीब एक हजार टन पानी खर्च होता है. आपने कभी सोचा है कि एक कप कॉफी पर कितना पानी खर्च हुआ होता है. आप हैरत करेंगे कि एक कप कॉफी पर 140 लीटर पानी खर्च होता है. किसी भी उत्पाद की खेती से लेकर उसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग तक जो ढेर सारा पानी खर्च होता है, इसे ही वर्चुअल वाटर कहते हैं. मांसाहारी खाद्य पदार्थों की तुलना में शाकाहारी खाद्य पदार्थों पर कम पानी लगता है. अगर आप मांसाहारी हैं तो पांच लीटर पानी खपत करेंगे, अगर शाकाहारी हैं तो सिर्फ ढाई लीटर. एक किलो मांस पैदा करने पर करीब 15,500 लीटर पानी खर्च होता है. इसी तरह औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में भी वर्चुअल वाटर सिद्धांत लागू होता है. वर्चुअल वाटर पर काम करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया है कि एशिया में रह रहा प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में औसतन 1,400 लीटर आभासी पानी का इस्तेमाल करता है, जबकि यूरोप और अमेरिका में 4,000 लीटर.

पिछले कुछ वर्षों में वर्चुअल वाटर एक बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन अब भी कई देशों की सरकारें इस मुद्दे को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं हैं, भारत भी उनमें शामिल है. वर्चुअल वाटर फुट प्रिंट का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य नीति और शोध पर खासा प्रभाव डाल सकता है. भविष्य में यह सिद्धांत दुनियाभर में पानी के प्रबंधन को लेकर छिड़ी बहस को एक नई दिशा दे सकता है. ■

मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक और पानी

सबसे पहले हम बात करते हैं बोतलबन्द पानी की. पिछले बीस सालों में भारत में बोतलबंद पानी के व्यापार में जो तेज़ी और तरक्की आई है, वह आश्चर्यजनक है. क्या आपको पता है कि जब आप एक बोतल पानी खरीदकर पीते हैं, तब आप उस पानी को कितनी कीमत पर खरीदते हैं और इसके साथ ही आप कितना पानी बर्बाद कर देते हैं. शायद, आपको यह डाटा देखकर भरोसा न हो. लेकिन यही सच है और यह सच ऐसा है जो हमें दिनों-दिन पानी के संकट की ओर धकेल रहा है. मसलन, एक लीटर बोतलबंद पानी तैयार करने में पांच लीटर पानी खर्च होता है. एक डाटा के मुताबिक दुनियाभर में साल 2004 में 154 अरब लीटर बोतलबंद पानी के लिए 770 अरब लीटर पानी का उपयोग किया गया था. भारत में भी इस प्रक्रिया के लिए 25.5 अरब लीटर पानी बहाया गया. यह अकारण ही नहीं है कि बनारस से लेकर केरल के गांववाले इन बोतलबंद कंपनियों और कोला कंपनियों के ख़िलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. इन जगहों पर भूमिगत जल का जिस तरह दोहन किया गया है, उससे वहां पर भू-जल स्तर काफी नीचे चला गया है. कैलिफोर्निया के पेसिफिक इंस्टीट्यूट का कहना है कि 2004 में अमेरिका में 26 अरब लीटर पानी की पैकिंग के लिए प्लास्टिक की बोतलों के निर्माण के लिए दो करोड़ बैरल तेल का इस्तेमाल किया गया. प्लास्टिक की बोतलें भी भू-जल को प्रदूषित करती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बनती हैं. कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां भी बेतहाशा पानी का दोहन करती हैं. बोतलबंद पानी और पेय निर्माता कंपनियां एक हजार लीटर भूमिगत जल के बदले महज कुछ रुपये सरकार को देती हैं.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

विनाश की तरफ

पानी के पदचिन्ह

पृष्ठ 1 का शेष

कृषि और पानी

आईए, सबसे पहले कुछ दिलचस्प लेकिन खतरनाक डेटा पर नज़र डालते हैं. कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, जहां कुल पानी का करीब 90 फीसदी से अधिक का इस्तेमाल होता है जबकि घरेलू उपयोग में लगभग 5 फीसदी पानी ही खर्च होता है. इसके अलावा, भारत में एक किलो गेहूं उगाने के लिए करीब 1700 लीटर (देखें बॉक्स) पानी खर्च होता है. यानी, अगर हमारे परिवार में एक दिन एक किलो गेहूं की खपत होती है, तो हम उसके साथ करीब 1,700 लीटर पानी की भी खपत करते हैं. यहां तक कि आप जिस कम्प्यूटर, या कार का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो जींस पैंट पहनते हैं, उसे बनाने में भी हजारों लीटर पानी की खपत होती है या फिर एक कप कॉफी के साथ हम असल में 140 लीटर पानी भी पीते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर. इसे आप आभासी खपत कह सकते हैं लेकिन यह खपत असली है. अब एक और तथ्य पर ध्यान देने की जरूरत है. आज, मिस्र गेहूं का आयात करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और चीन भी अब खाद्य उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है, जबकि दुनियाभर में इसका सामान बिकता है. सवाल यह है कि चीन या मिस्र ऐसा क्यों कर रहे हैं. जवाब बहुत ही साधारण है. इन दोनों देशों ने ऐसी सभी फसलों का उत्पादन बहुत कम कर दिया है, जिसमें पानी की खपत सबसे ज्यादा होती है. ये दोनों देश इस तथ्य

वाटर फुटप्रिंट किसी प्रक्रिया, कंपनी या क्षेत्र द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पानी की खपत और जल प्रदूषण को दर्शाता है. ग्रीन-वाटर फुटप्रिंट मिट्टी की परत में छिपा पानी है, जिसका इस्तेमाल कृषि, हॉर्टीकल्चर या जंगल द्वारा होता है. ब्लू-वाटर फुटप्रिंट ग्राउंड वाटर है. इसका इस्तेमाल कृषि, उद्योग और घरेलू काम में होता है. ग्रे-वाटर फुटप्रिंट ताजा जल (फ्रेश वाटर) की वह मात्रा है जिसकी जरूरत प्रदूषकों को हटाकर जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए होती है.

क्या है वाटर फुटप्रिंट

वाटर फुटप्रिंट शब्द सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि आखिर वाटर फुटप्रिंट है क्या? हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या या उत्पादों में आभासी या छिपा जल शामिल होता है. उदाहरण के लिए, एक कप कॉफी के उत्पादन के लिए आभासी पानी की मात्रा 140 लीटर तक होती है. आपका वाटर फुटप्रिंट केवल आपके द्वारा प्रयोग किए गए प्रत्यक्ष पानी (उदाहरण के लिए नहाने या धुलाई में) को ही नहीं दिखाते, बल्कि आपके द्वारा उपभोग किए गए आभासी पानी की मात्रा को भी दर्शाता है. लोग पीने, खाना पकाने और कपड़े धुलने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, इससे अधिक पानी वे अनाज उपजाने, कपड़े का निर्माण करने, कार बनाने और कम्प्यूटर निर्माण में करते हैं. वाटर फुटप्रिंट ऐसे ही हर एक उत्पाद और सेवा, जिसका हम उपभोग करते हैं, उसमें इस्तेमाल किए गए पानी की गणना करता है. वाटर फुटप्रिंट हमारे सामने कई सारे सवाल उठाता है. जैसे, किसी कंपनी में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी का स्रोत क्या है? इन जल स्रोतों की रक्षा के क्या उपाय हैं? क्या हम वाटर फुटप्रिंट घटाने के लिए कुछ कर सकते हैं? वाटर फुटप्रिंट के तीन घटक हैं. ग्रीन, ब्लू और ग्रे. एक साथ मिलकर ये घटक पानी के इस्तेमाल की असल तस्वीर दिखाते हैं. मसलन, इस्तेमाल किया गया पानी बारिश का पानी है, सतह का पानी है या भू-जल है. वाटर फुटप्रिंट किसी प्रक्रिया, कंपनी या क्षेत्र द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पानी की खपत और जल प्रदूषण को दर्शाता है. ग्रीन-वाटर फुटप्रिंट मिट्टी की परत में छिपा पानी है, जिसका इस्तेमाल कृषि, हॉर्टीकल्चर या जंगल द्वारा होता है. ब्लू-वाटर फुटप्रिंट ग्राउंड वाटर है. इसका इस्तेमाल कृषि, उद्योग और घरेलू काम में होता है. ग्रे-वाटर फुटप्रिंट ताजा जल (फ्रेश वाटर) की वह मात्रा है जिसकी जरूरत प्रदूषकों को हटाकर जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए होती है. वाटर फुटप्रिंट का संबंध फ्रेश वाटर (ताजा जल) पर मानवीय प्रभाव और मानवीय इस्तेमाल से है. फुटप्रिंट के जरिए पानी की कमी और जल प्रदूषण जैसे मुद्दे को भी समझा जा सकता है. पानी का संकट आज वैश्विक अर्थव्यवस्था से भी संबंधित है. कई देशों ने तो अब अपने वाटर फुटप्रिंट को कम करने के लिए ऐसे उत्पादों को दूसरे देश से मंगाना शुरु कर दिया है, जिसके उत्पादन में पानी का ज्यादा इस्तेमाल होता है. ■

भविष्य में पानी का उपयोग

वर्ष	कृषि	उद्योग	घरेलू (अरब लीटर/दिन)	प्रति व्यक्ति (लीटर/दिन)
भारत				
2000	1658	115	93	88.9
2050	1745	441	227	167.0
चीन				
2000	1024	392	105	82.7
2050	1151	822	219	155.4
स.रा.अमेरिका				
2000	542	605	166	582.7
2050	315	665	187	484.6

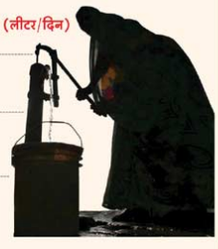

के बावजूद ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनके पास फिलहाल पानी की कोई कमी नहीं है और इनके पास नील और ह्वांगहो जैसी नदियां भी हैं. दरअसल, ऐसा सिर्फ और सिर्फ पानी बचाने के लिए हो रहा है. यदि कोई देश पानी बचाने के लिए फसल ही न उगाए और उसकी जगह अनाज दूसरे देशों से आयात करे, तो इससे समझा जा सकता है कि जल संकट को लेकर दुनियां में क्या चल रहा है? भारत के संदर्भ में देखें तो, इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि साल 2014-15 में भारत ने करीब 37 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया. अब 37 लाख टन बासमती चावल उगानेके लिए 10 ट्रिलियन लीटर पानी खर्च हुआ. इसे अब ऐसे भी बोल सकते हैं कि भारत ने 37 लाख टन बासमती चावल के साथ 10 ट्रिलियन लीटर पानी भी दूसरे देश में भेज दिया, जबकि पैसा सिर्फ चावल का मिला. यानी, जिस देश ने हमसे चावल खरीदा उसे चावल के साथ दस ट्रिलियन लीटर पानी मुफ्त में मिल गया या फिर कहें कि उसका इतना ही पानी बच गया. भारत हर साल विदेशों में अनाज बेच कर भारी मात्रा में पानी का आभासी निर्यात करता है. लब्बोलुबाव यह है कि पानी की स्थिति भयावह है. राज्यवार देखें कैसी स्थिति है. झारखंड में 10 साल में धरती का पानी खत्म हो जाएगा. जब झारखंड राज्य बना था तब वहां 75 हजार कुएं थे. अब सिर्फ 10 हजार कुओं में पानी बचा है. भूगर्भ विभाग ने चेतावनी दे दी है कि महज 10 साल में जमीन के भीतर का पानी खत्म हो जाएगा. मध्यप्रदेश के 51 में से 40 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं. राजस्थान के 15 हजार गांव टैंकरों के सहारे चल रहे हैं. गुजरात में सौराष्ट्र के कई जिलों में सात से 13 दिन बाद पीने का पानी मिल रहा है. सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के लातूर में ट्रेन से पानी पहुंचाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के 27 में से 25 जिले सूखाग्रस्त घोषित हैं. आंध्रप्रदेश में भूजल स्तर दो गुना से ज्यादा नीचे जा चुका है और आंध्र के बाद तेलंगाना में जलसंकट से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं. ■

देवास में पानी की खेती

पहले मध्य प्रदेश के देवास जिले में भू-जल स्तर गिरकर 400 फीट से भी नीचे चला गया था. यहां के गोरवा गांव लोगों को पीने के लिए दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था. फसल की पैदावार प्रभावित हो गई थी. लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया था. इस सूरत में, आईआईटी रूड़की से पासआउट उमाकांत उमराव 2006 में देवास जिले कलेक्टर बनकर आए थे. जिले में पानी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने किसानों को अपने खेत के एक छोटे हिस्से में तालाब बनाने के लिए प्रोत्साहित किया. बैंक और सोसाइटी को उन्होंने किसानों को तालाब बनाने केलिए लोन देने के लिए भी राजी किया. उनके प्रयासों ने गोरवा गांव के 150 से ज्यादा किसानों ने अपने खेत में तालाब बनाए. खेत में तालाब बनाने के काम को पानी की खेती नाम दिया गया. किसानों को यह समझाया कि फसल से उन्हें लाभ होता है, वैसे ही पानी की खेती करने से भी उन्हें लाभ होगा. अब, हालत ये हैं कि यहां का हर किसान साल में दो फसल उगा रहा है. इसके चलते गांव का हर परिवार अब संपन्न है. पंचायत में अभी 170 तालाब हैं और सभी में भरपूर पानी है.

प्रति व्यक्ति जल का उपयोग

महादेश	प्रति व्यक्ति जल उपयोग (घन मीटर/वर्ष)
अफ्रीका	245
एशिया	519
उत्तर एवं मध्य अमेरिका	1,861
दक्षिणी अमेरिका	478
यूरोप	1,280
सोवियत संघ (पूर्व)	713

जल का मौजूदा उपयोग

उपयोग (%)	विश्व	यूरोप	अफ्रीका	भारत
कृषि	69	33	88	83
उद्योग	23	54	5	12
घरेलू	8	13	7	5

कृषि में पानी का उपयोग (प्रति किलो उपज के लिए आवश्यक पानी (लीटर में)

फसल	भारत	विश्व
गेहूं	1,654	1,334
धान (चावल)	2,850	2,291
गन्ना	159	175
कपास	18,694	8,242
दूध	1,369	990
अंडे	7,531	3,340
चिकेन	7,736	3,918

भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता

वर्ष	जनसंख्या (करोड़ में)	प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता (घन मीटर/वर्ष)
1951	36.1	5,177
1955	39.5	4,732
1991	84.6	2,209
2001	102.7	1,820
2025	139.4	1,341
2050	164.0	1,140

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 14
06 जून- 12 जून 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

असम की जीत अहम

मनीष कुमार

बिहार चुनाव में पराजित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का हौसला पस्त हो चुका था. इसके बाद जिन पांच राज्यों में चुनाव होने थे, उनमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति चिंताजनक थी. ये ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा की सरकार बनना तो दूर की बात थी, इन राज्यों में उसकी उपस्थिति भी नहीं थी. केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में पार्टी ने कभी कोई सीट नहीं जीती थी. पश्चिम बंगाल में बीजेपी की उपस्थिति तो है लेकिन वहां व किसी दूसरी पार्टी को चुनौती देने योग्य नहीं थी. असम में भी बीजेपी का वही हाल था लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में पार्टी को यहां आशा की किरण नजर आई. राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली और बिहार में लगातार मिली शर्मनाक हार के बाद उसके लिए असम में जीत दर्ज करना जरूरी था. वहीं, कांग्रेस पार्टी 2014 के चुनाव के बाद लगातार चुनाव हार रही थी. लोकसभा चुनाव के बाद जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वहां लोगों ने उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया. बिहार चुनाव में कांग्रेस लालू यादव और नीतीश कुमार के कंधों पर सवार होकर अच्छा प्रदर्शन करने में जरूर कामयाब हुई लेकिन वह असम और केरल में सरकार गंवाने का जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं थी. मतलब यह कि 2016 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए महत्वपूर्ण थे. राजनीति में हार और जीत का फैसला सही फैसलों से ज्यादा गलत फैसलों से तय होता है यानी आपकी गलतियां ही नतीजे तय करती हैं. चुनावी रणनीति में जिस पार्टी से ज्यादा गलती होती है वह पार्टी हार जाती है और जो पार्टी गलतियां नहीं करती या कम गलतियां करती है वह चुनाव जीत जाती है. असम के चुनाव में भी यही हुआ है. कांग्रेस पार्टी ने सही फैसले लेने से ज्यादा गलतियां की हैं.

भाजपा ने बिहार चुनाव की गलतियां नहीं दोहराईं

चुनावी हार से जो पार्टी सबक लेती है वही पार्टी नई चुनौतियों का सामना करने में सफल हो सकती है. कांग्रेस पार्टी अपनी हार से सीखना नहीं चाहती लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव में मिली हार से बहुत कुछ सीखा और उन सभी गलतियों को असम में सुधार लिया. पहला सबक जो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में सीखा वह यह था कि चुनावी रणनीति और प्रचार-प्रसार का काम दिल्ली से आए केंद्रीय नेताओं के हाथ में देने के बजाय स्थानीय (लोकल) नेताओं को दिया जाए. बिहार की तरह असम में दिल्ली से आए नेताओं का जत्था कैंपेन का संचालन नहीं कर रहा था. यहां के स्थानीय नेताओं ने ही चुनाव-प्रचार का संचालन किया. टिकट बंटवारे से लेकर पोलिंग एजेंट की नियुक्ति तक का फैसला असम के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लिया. अपनी दूसरी गलती जो भारतीय जनता पार्टी ने सुधारी, वह यह कि चुनाव का चेहरा स्थानीय नेता ही हो. यही वजह है कि असम में भारतीय जनता पार्टी ने सर्बानंदा सोनोवाल और हेमंत बिस्वा सरमा को आगे किया. असम में बिहार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफानी दौरा नहीं किया. यहां नोट करने वाली बात यह है कि चुनाव-प्रचार के दौरान सर्बानंदा सोनोवाल और हेमंत बिस्वा सरमा ने असम के दूर-दराज के इलाकों में रैलियां कीं और उनमें प्रधानमंत्री की रैलियों से ज्यादा भीड़ उमड़ रही थी. तीसरी लेकिन भाजपा की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति यह रही कि उसने बिहार की तरह असम में कोई महागठबंधन बनने की स्थिति पैदा नहीं होने दी. बल्कि इसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के साथ मिलकर एक अजेय गठबंधन बनाने में कामयाब रही. और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सुखद बात यह रही कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से चुनाव के दौरान कोई अटपटा सा बयान नहीं आया.

चुनाव से पहले ज्यादातर विश्लेषक यह मान रहे थे कि भाजपा का प्रदर्शन अच्छा होगा लेकिन वह दो तिहाई सीट जीतकर सरकार बनाएगी यह किसी ने नहीं आंका था. भाजपा के रणनीतिकारों के लिए भी यह नतीजा हैरत करने वाला रहा होगा. इसकी वजह यह है कि असम में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं थी. 2011 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 126 में से 120 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सिर्फ 5 सीट ही जीत पाई थी. लेकिन असम में भारतीय जनता पार्टी का हौसला 2014 के लोकसभा चुनाव में बुलंद हुआ जब वह 14 में से 7 सीट जीतने में कामयाब रही. भारतीय जनता पार्टी को असम में दूसरी सफलता 2015 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में मिली. दूसरी तरफ असम गण परिषद लगातार अपने विरोधाभास की वजह से असम की राजनीति के हाशिए पर जा चुकी थी. पिछले कई चुनाव के नतीजे इस बात के गवाह हैं कि असम गण परिषद नेतृत्व और संगठन के तौर पर लोगों का विश्वास जीतने में विफल रही. 2014 का लोकसभा चुनाव भी पार्टी के लिए बड़ा झटका था. वह एक भी सीट नहीं जीत पाई थी. मतलब यह कि असम में किसी तीसरी पार्टी के लिए स्पेस बन चुका था. जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अब भर दिया. भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पिछले दो दशक से पूर्वोत्तर में ज़मीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर काम कर रही थी. जिसका फायदा अब चुनाव नतीजों में साफ दिखने लगा था. 2014 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी न केवल असम में बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही थी.

लोकसभा चुनाव की जीत से असम के स्थानीय भाजपा संगठन का हौसला तो बढ़ा था लेकिन उसे विधानसभा चुनाव में लोकसभा की तरह नतीजे आएंगे यह भरोसा नहीं था. भारतीय जनता पार्टी ने पहले स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत किया और दूसरा युवाओं को पार्टी का चेहरा बनाया. भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा न देकर गलती की थी. यह गलती बीजेपी ने असम में दोहराई. उन्होंने चुनाव से पहले सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जिसका फायदा पार्टी को हुआ. इसके अलावा कांग्रेस को छोड़कर आए हेमंत बिस्वा सरमा से पार्टी को काफी फायदा हुआ.

सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा युवा नेता हैं. दोनों ही ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के प्रभावी चेहरा रहे हैं जो असम में बाहरी यानि बांग्लादेशियों के खिलाफ आंदोलन करते आए हैं. सर्बानंद की छवि अच्छी है. इसके साथ ही उनकी गिनती एक अच्छे वक्ता में होती है. हेमंत बिस्वा सरमा की छवि एक चतुर रणनीतिकार की है. बिस्वा एक लोकप्रिय नेता हैं और कामयाब मिनिस्टर के रूप में भी जाने जाते हैं. इन दोनों की छवि धरती पुत्रों की है. भारतीय जनता पार्टी ने असम में युवा नेताओं को आगे बढ़ाया है. कामख्या ताशा और रामेश्वर तेली असम के युवा नेताओं में से हैं जो फिलहाल सांसद हैं. भारतीय जनता पार्टी की सफलता का श्रेय इन्हीं युवा नेताओं को जाता है. जहां तक बात केंद्रीय नेतृत्व की है तो उनका योगदान बस इतना ही है कि उन्होंने इन युवा नेताओं को पार्टी के पुराने नेताओं की दखलंदाजी से दूर रखा.

कांग्रेस अपनी गलतियों से हारी

असम में वैसे तो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है. कुछ समय को छोड़कर यहां कांग्रेस की ही सरकार रही है. तरुण गोगोई सबसे ज्यादा समय तक असम के मुख्यमंत्री बने रहे. वह 2001 से लगातार मुख्यमंत्री के पद पर रहे. तरुण गोगोई असम के ज़मीनी नेता हैं. उन्होंने कांग्रेस को 15 साल तक सफलतापूर्वक असम की सबसे बड़ी पार्टी बनाए रखा. लेकिन, उन्हें सबसे बड़ा झटका 2014 के लोकसभा चुनाव में लगा, जब कांग्रेस पार्टी 14 में से सिर्फ 3 सीट जीत सकी. विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 साल के शासन की वजह से सत्ता विरोधी लहर का सामना करना था. इस बीच पार्टी में विद्रोह भी हुआ जब हेमंता विस्वा सरमा के साथ कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी. हकीकत यह है कि इन सब के बावजूद कांग्रेस अपने सगंठन, अच्छी रणनीति और मुस्लिम वोट के सहारे चुनाव जीत सकती थी. लेकिन, कांग्रेस ने एक भी ऐसा फैसला नहीं किया जिससे उन्हें जीत मिल सके. इसके उलट, उसने वह सारे काम किए जो पार्टी की हार सुनिश्चित कर रहे थे. कांग्रेस ने बिहार चुनाव के नतीजे से कोई सीख नहीं ली. जिस तरह बिहार में कांग्रेस ने लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ मिलकर एक महागठबंधन बनाकर सेकुलर वोट को बंटने से रोका था वदि वही फार्मूला असम में भी अपनाया गया होता तो वह भाजपा को चुनौती देने में सफल हो सकती थी. लेकिन, कांग्रेस ने असम में ऐसा नहीं किया. दूसरी तरफ, परिवारवाद और बांग्लादेशियों को पनाह देने वाली पार्टी के रूप में उभरी छवि से उसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ.

> असम में आधुनिक विचार और मान्यताओं की मौजूदगी के बावजूद पहचान का सवाल सबसे अहम बना हुआ है. असम के लोगों को लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से यहां आबादी का संतुलन बदल रहा है. यही वजह है कि असम की राजनीति के केंद्र में अवैध रूप से पलायन हुए बांग्लादेशियों का मुद्दा है. इसके ख़िलाफ कई दशकों से असम में आंदोलन चल रहा है. इन्हीं आंदोलनों से असम में संगठनों और नेताओं की नई खेप पैदा हुई है.

सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का तर्क ग़लत है

असम में जम्मू-कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा मस्लिम जनसंख्या है. यहां 34 फीसदी मुस्लिम आबादी है. कई विश्लेषकों की राय यह है कि असम में बीजेपी की जीत सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की वजह से हुई है. वे चुनाव के बाद हुए सर्वे के आधार पर यह दलील देते हैं कि चूंकि 60-65 फीसदी हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया इसलिए असम में धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण हुआ है. लेकिन यह सच्चाई नहीं है. असम के नतीजों का धार्मिक आधार पर विश्लेषण करना न तो तर्कसंगत है और न ही उचित है. फिर ऐसे विश्लेषकों को यह भी बताना चाहिए कि जब असम में भाजपा नहीं थी, तब कांग्रेस को हिंदुओं के जो वोट मिलते थे क्या वह धर्म के आधार पर मिलते थे? अगर असम में सांप्रदायिक-ध्रुवीकरण हुआ तो इन विश्लेषकों को यह बताना चाहिए कि यह कैसे संभव है कि 49 मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीटों में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई. विश्लेषकों की थ्योरी और अखबारों के सर्वे से अलग चुनावी नतीजों के सूक्ष्म परीक्षण से यह साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों ने किसी एक पार्टी के लिए सामूहिक रूप से वोट नहीं किया. यही वजह है कि इन 49 सीटों में बीजेपी को 15, कांग्रेस को 14, एयूडीएफ को 12, असम गण परिषद को 5 और बोडो पीपुल्स फ्रंट को 2 सीटों पर जीत मिली है.

हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं यह पहचान की लड़ाई है

आईडेंटिटी पॉलिटिक्स यानि पहचान की लड़ाई की सार्थकता पर बहस हो सकती है. यह सही है या गलत इस पर तर्क दिए जा सकते हैं लेकिन इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि असम विधानसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा पहचान ही था. असमिया, बोडो, दिमसा और बंगालियों की पहचान के साथ ही बाहरी-बांग्लादेशी का मुद्दा असम के चुनाव में मुख्य रहा. चुनाव से पहले आए सभी सर्वे में 70-75 फीसदी लोगों ने बंग्लादेशी घुसपैठ को चुनाव का सबसे अहम मुद्दा बताया था. असम में यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि असम में एथनिक ग्रुप्स (जनजातीय समूह) का महत्व रहा है. असम में आधुनिक विचार और मान्यताओं की मौजूदगी के बावजूद पहचान का सवाल सबसे अहम बना हुआ है. असम के लोगों को लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से यहां आबादी का संतुलन बदल रहा है. यही वजह है कि असम की राजनीति के केंद्र में अवैध रूप से पलायन हुए बांग्लादेशियों का मुद्दा है. इसके खिलाफ कई दशकों से असम में आंदोलन चल रहा है. इन्हीं आंदोलनों से असम में संगठनों और नेताओं की नई खेप पैदा हुई है. असम में इसी वजह से पहचान की लड़ाई कमजोर होने के बजाए मजबूत हुई है. चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषणों और नेताओं के बयानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी असम विधानसभा चुनाव को स्वदेशी बनाम बाहरी बनाने में कामयाब रही. असम के चुनाव का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने तय किया. चुनाव प्रचार की दिशा और दशा भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के मुताबिक तय हुई. यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की असम में ऐतिहासिक जीत हुई. ■

manishbph244@gmail.com

तमिलनाडु

अम्मा ने इतिहास पलट दिया

अंशु दीनमणि

पांच राज्यों में चुनाव हुए. सबके परिणाम आए. इनमें जयललिता ने मीडिया की सारी लाल-बुझक्कड़ी को फेल कर दिया. सारे आकलनों को पटखनी देते हुए जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके ने 32 वर्षों के रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए सत्ता पर लगातार दूसरी बार कब्जा किया. जयललिता की पार्टी को 134 सीटें हासिल हुईं, जबकि करुणानिधि की पार्टी डीएमके को 89 सीटों से ही संतोष करना पड़ा. डीएमके और कांग्रेसी तालमेल को तमिलनाडु की जनता ने खारिज कर दिया और जयललिता को सत्ता पर स्थापित कर दिया.

तमिलनाडु में जयललिता की तरफ से शुरू की गई योजनाएं उनकी दोबारा जीत की कारक बनीं. जयललिता ने अपने नाम पर भी कई स्कीमें शुरू की थीं. इनमें अम्मा कैंटीन से लेकर अम्मा पानी और अम्मा नमक तक शामिल हैं. इन योजनाओं के जरिए एक आदमी करीब 20 रुपये में तीन वक्त का खाना खा सकता है. जयललिता की जीत में महिला मतदाताओं की भी उल्लेखनीय भूमिका रही. तमिलनाडु में 74 फीसदी मतदान हुआ, लेकिन महिलाओं का वोटिंग 82 फीसदी थी. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं के ज्यादातर वोट अम्मा की पार्टी को ही गए.

राजनीतिक वजहों में डीएमके की अंदरूनी कलह और फूट ने भी जयललिता के पक्ष में काफी माहौल बनाया. डीएमके प्रमुख करुणानिधि के बेटे स्टालिन को बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किए जाने से पार्टी के वरिष्ठ नेता नाराज़ थे. इस वजह से कुछ लोगों ने तो पार्टी भी छोड़ दी थी. इसके अलावा तमिलनाडु के चुनाव में मोदी-फैक्टर की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता. मोदी-जया के बीच अच्छा समन्वय रहा है. केंद्र की कई बड़ी योजनाएं तमिलनाडु में काफी धूम-धड़ाके से लागू की गईं. इसके अलावा चेन्नई में आई बाढ़ के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल बेहतरीन रहा. मोदी के साथ बेहतर तालमेल और समन्वय के कारण जयललिता बनाम करुणानिधि में पलड़ा जयललिता का ही भारी रहा. तमिलनाडु में बीते दो दशक से मुक़ाबला दो शख्सियतों के बीच ही रहा है. पूरा प्रदेश अम्मा और करुणानिधि के बीच बंटा माना जाता है. 2015 में भ्रष्टाचार के एक मामले में जयललिता के जेल जाने पर उनके कुछ समर्थकों ने आत्मदाह तक कर लिया था. इस बार के विधानसभा चुनाव में भी मुख्य लड़ाई जयललिता और करुणानिधि के बीच ही रही. चुनावी डायलॉगबाजी में भी एक दूसरे के बीच प्रतिस्पर्धा रही. जयललिता ने कहा कि चुनाव जीतने पर वह प्रदेश में शराबबंदी लागू करेंगी तो करुणानिधि ने भी ऐसा ही डायलॉग दोहराया. जयललिता ने अपनी चुनावी रैलियों में कहा, मैं आपकी मां हूं और सिर्फ मां ही अपने बच्चों का दर्द समझ सकती है. इस पर करुणानिधि बोले, मैं आपके अभिभावक की तरह हूं इसलिए लोगों की तकलीफ समझता हूं. लेकिन मेरे पास सत्ता नहीं है. आप सत्ता देंगे, मैं आपकी समस्याएं दूर करूंगा.

तमिलनाडु में चुनावी माहौल बनाने के लिए जयललिता ने कई कार्ड भी खेले. उन्होंने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों को रिहा करने का फैसला करके एक राजनीतिक दांव खेला था. सुप्रीम कोर्ट में मामला चले जाने के कारण दोषियों की रिहाई तो नहीं हो पाई, लेकिन उसका जो राजनीतिक संदेश लोगों के बीच जाना था, वह चला गया. जयललिता ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लोगों को मुफ्त मोबाइल फोन और 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया. इसके साथ ही लड़कियों के लिए स्कूटी खरीदने की लिए 50 फीसदी छूट और हर गरीब घर से एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा भी चुनाव में खासा असरकारक रहा. हालांकि डीएमके ने भी 3-जी और 4-जी कनेक्शन मुफ्त में देने का वादा किया था. तमाम एग्जिट पोल के आकलनों ने करुणानिधि की पार्टी डीएमके के सत्ता में लौटने का अनुमान लगाया था. लेकिन, जयललिता की एआईडीएमके ने तमिलनाडु के सालों से चले आ रहे चलन को बदला डाला. वर्ष 1984 के बाद यहां कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं आई थी. लेकिन, जयललिता ने इसे बदल डाला. जयललिता ने कहा भी कि राज्य का इतिहास बदला है, हमें ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है. वर्ष 1984 से पहले एम जी रामचंद्रन तीन बार (1977 से 1980, 1980 से 1984 और 1985 से 1987 तक) तमिलनाडु की सत्ता पर क़ाबिज रहे थे.■

किसे कितनी मिली सीटें

दल का नाम	विजयी
कांग्रेस	8
एआईएडीएमके	134
डीएमके	89
आईयूएमएल	1
कुल	232

केरल

कांग्रेस के मुंह में भाजपा का करेला

केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में केरल के विकास की तुलना बदहाल अफ्रीकी देश सोमालिया से की थी. चुनाव परिणाम ने कांग्रेस को सोमालिया जैसी हालत में ही ला दिया. हालांकि चुनाव के बाद केरल में जिस तरह हिंसा हो रही है, उससे भी सोमालिया का ही एहसास हो रहा है. कांग्रेसनीत यूडीएफ गठबंधन को 140 में मात्र 47 सीटों पर ही सिमटना पड़ा जबकि वाम गठबंधन एलडीएफ को 83 सीटों के साथ भारी बहुमत मिला. भाजपा केवल एक सीट हासिल कर पाई. पूर्व क्रिकेटर एस. श्रीसंत पर भाजपा का लगाया दांव बेकार चला गया और वह चुनाव हार गए. भाजपा का वोट शेयर 4 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत पर जा पहुंचा. भाजपा के लिए इतना ही सार्थक है. केरल में लेफ्ट और राइट के बीच जानलेवा लड़ाई आम बात रही है.

केरल विधानसभा की 140 सीटों के लिए इस बार 109 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 1,203 उम्मीदवारों ने चुनाव मैदान में ताल ठोंकी थी. यहां हमेशा की तरह इस बार भी द्विकोणीय लड़ाई ही थी, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ को वाम मोर्चे के नेतृत्व वाली एलडीएफ ने जबरदस्त पटखनी दी. वीएस अच्युतानंदन के नेतृत्व में एलडीएफ को सत्ता में वापसी की उम्मीद पहले से ही थी, जो कि अंततः सही साबित हुई. पश्चिम बंगाल में अपना अस्तित्व खो चुके वाम मोर्चा को केरल में 92 साल के अच्युतानंदन की रणनीति, जोश और चुनावी गणित का सहारा था, जो सटीक साबित हुआ. एलडीएफ गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार में अच्युतानंदन ने पूरी ताकत झोंक दी थी. रोजाना औसत 200 किलोमीटर की यात्रा करने वाले अच्युतानंदन ने करीब 70 रैलियों को संबोधित किया, जिसका परिणाम सामने है. केरल के चुनाव में सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा, क्योंकि सोलर घोटाला और शराब घूसकांड जैसे मामले कांग्रेस के गले की हड्डी बन गए. तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने चुनाव परिणामों पर कहा कि यह हार काफी निराशाजनक है और यह वक्त कांग्रेस के लिए पुनर्विचार और पुनर्निर्माण का है. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि पार्टी को आत्मावलोकन की जरूरत है. केरल के बहुचर्चित जिशा बलात्कार और हत्याकांड का भी कांग्रेस गठबंधन को काफी नुकसान झेलना पड़ा.

केरल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थीं. यहां चुनाव इसलिए भी खास रहा क्योंकि इस चुनाव में भाजपा ने यूडीएफ को हराने में अहम भूमिका अदा की. केरल के इस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 10 फीसदी यानी कुल 21,29,726 वोट हासिल किए. माना जा रहा है कि इसमें से अधिकतर वोट यूडीएफ के ही हिस्से के थे. भाजपा इस वोट शेयर को मात्र एक सीट में ही परिवर्तित कर पाई, लेकिन यह साफ है कि इस अदृश्य वोट बैंक ने एलडीएफ की सत्ता हासिल करने में परोक्ष मदद की. 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद केरल में सत्ता बचाए रखना कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, वहीं एलडीएफ के लिए भी यह प्रतिष्ठा की लड़ाई थी. वाम मोर्चा वाले एलडीएफ ने केरल में 88 सीटें हासिल कीं तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को 51 सीटें मिलीं.

भाजपा ने केरल में दोनों पार्टियों के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं. भाजपा ने नवगठित भारत धर्म जनसेना के साथ गठबंधन किया था. ईसाईयों की बहुलता वाले केरल में भाजपा ने राजशेखरन के नेतृत्व में आक्रामक तरीके से हिंदुत्व कार्ड का सहारा लिया था. राज्य में लगभग 45 फीसदी ईसाई और मुसलमान हैं. हिंदू करीब 55 फीसदी हैं और उन्होंने कभी एकजुट होकर वोट नहीं किया. गौरतलब है कि राजशेखरन ने राज्य में विश्व हिंदू परिषद को स्थापित करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हालांकि नायर सेवा समाज द्वारा समर्थन देने से इंकार करने की वजह से भाजपा की इस योजना को बड़ा धक्का भी लगा. केरल विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा. यूडीएफ के मुख्यमंत्री ओमन चांडी के कार्यकाल में एक के बाद एक कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा. जहां तक मुख्य आरोपों की बात है तो तत्कालीन खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जोसेफ पर सौर घोटाले का आरोप लगना प्रमुख है. सौर घोटाले की मुख्य आरोपी सरिता नायर ने तो चांडी पर उनका यौन शोषण करने का आरोप भी लगाया था. एक अन्य आरोप में वार रिश्वत घोटाले में भी सत्ताधारी दल का नाम जोड़ा गया. भ्रष्टाचार के कई पुराने मामले भी उठाए गए, जिसमें 1991 का पामोलिन तेल आयात मामला शामिल था, तब चांडी वित्त मंत्री थे.

केरल में हर पांच साल के अंतराल में सत्ता बारी बारी से यूडीएफ और एलडीएफ के हाथों में जाती रही है. केरल में 1977 को छोड़ दें, तो हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन होता रहा है. जाहिर है इस बार बारी एलडीफ की थी. सत्ता विरोधी लहर के कारण कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई. केरल के आदिवासी इलाकों में गरीबी और अकाल से बच्चों की मौत के लिए भी तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी के दुलमुल रवैये को जिम्मेदार माना गया. केरल में क़ानून की पढ़ाई करने वाली एक दलित छात्रा के साथ बलात्कार और निर्मम हत्या के कुछ ही दिन बाद ही नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली एक अन्य दलित छात्रा के साथ बारकला के अयांती में हुए बलात्कार कांड ने भी जनता को झकझोर कर रख दिया. केरल में कोल्लम के पुत्तिंगल मंदिर में आतिशबाजी के दौरान आग लगने और विस्फोट से 100 से अधिक लोगों के मरने की वजह से चांडी सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठने लगे थे. ■

किसे कितनी मिली सीटें

दल का नाम	विजयी
इंडियन नेशनल कांग्रेस	22
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	19
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (M)	58
नेशनल कांग्रेस पार्टी	2
भारतीय जनता पार्टी	1
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग	18
केरल कांग्रेस (एम)	6
जनता दल (सेक्युलर)	3
कम्युनिस्ट मार्कसिस्ट पार्टी केरल स्टेट कमेटी	1
केरल कांग्रेस (जैकब)	1
केरल कांग्रेस (बी)	1
कांग्रेस (सेक्युलर)	1
नेशनल सेक्यूलर कांफ्रेंस	1
निर्दलीय	6
कुल	140

पुडुचेरी

छोटे से राज्य में कांग्रेस को बड़ी सी राहत

पुडुचेरी एक केंद्र शासित राज्य है. यह भारत का तीसरा सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र भी है. यहां का मुख्य उद्योग पर्यटन और मत्स्य पालन है. पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ एआईएनआरसी को पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस-डीएमके गठबंधन ने बहुमत हासिल किया. इस केंद्र शासित प्रदेश की 30 सीटों में से कांग्रेस को 15 और उसकी सहयोगी डीएमके को दो सीटें मिली हैं. जबकि सत्तारूढ़ एआईएनआरसी को आठ, एडीएमके को चार सीटें मिली हैं और एक सीट निर्दलीय के नाम रही.

निवर्तमान मुख्यमंत्री एन रंगासामी के लिए यह बड़ा झटका है जो चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे. उनकी पार्टी एआईएनआरसी को महज आठ सीटें मिलीं. शुरू में सत्तारूढ़ एआईएनआरसी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी, लेकिन बाद में इस गठबंधन ने रंगासामी की पार्टी पर बढ़त बना ली. अकेले चुनाव लड़ने वाली एआईएडीएमके को यहां चार सीटें मिलीं. मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने इंदिरा नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार वी अरुमुगम को 3,404 मतों के अंतर से पराजित किया.

किसे कितनी मिली सीटें

दल का नाम	विजयी
कांग्रेस	15
एआईएडीएमके	4
ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस	8
डीएमके	2
निर्दलीय	1
कुल	30

रंगासामी ने साल 2011 में कांग्रेस से अलग होकर एआईएनआरसी का गठन किया था. एआईएनआरसी, भाजपा और एडीएमके ने अकेले चुनाव लड़ा जबकि कांग्रेस और डीएमके ने गठबंधन किया था. कांग्रेस ने 21 और द्रमुक ने शेष सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. हालांकि, रंगासामी की छवि मिस्टर ऑनेस्ट की रही है और तमाम योजनाओं को ज़मीन पर उतारने में इन्हें महारत हासिल है, बावजूद इसके वह दोबारा सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए. साल 2011 के विधानसभा चुनाव में रंगास्वामी की ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और जयललिता की एआईएडीएमके ने गठबंधन किया था. तब एआईएनआरसी को 15 और एआईएडीएमके को पांच सीटें हासिल हुई थीं. कांग्रेस को सात और डीएमके को दो सीटें मिली थीं और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुआ था.

इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री एवं एआईएनआरसी संस्थापक एन रंगासामी, विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री वी वैतिलिंगम (कांग्रेस), पीसीसी नेता ए नमाशिवायम और पुडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष वी सवापति समेत कई महत्वपूर्ण उम्मीदवार मैदान में थे. रंगासामी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कई मुफ्त वाली योजनाएं चलाईं. लेकिन वह सरकार चलाने के लिए जरूरी राजस्व नहीं जुटा पाए. इसे नाकामयाबी माना गया. रंगास्वामी पहले कांग्रेस में ही थे, इसके बाद उन्होंने अलग पार्टी बनाई. कांग्रेस मतदाताओं को यह समझाने में कामयाब रही कि रंगास्वामी ने पार्टी तोड़कर गलत किया है. ■

तृणमूल कांग्रेस का नहीं था कोई विकल्प, वाम-कांग ने बाकी कसर पूरी कर दी

ममता की जीत तो पहले से तय थी...

केरल में राहुल गांधी ने मंच से कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टियों की विचारधारा सदियों पुरानी है, जिसकी प्रासंगिकता आज खत्म हो चुकी है. इधर पश्चिम बंगाल में वही राहुल गांधी एक ही माला में एक घनघोर कम्युनिस्ट नेता के साथ प्रसन्नतापूर्वक समाए हुए थे. ऐसे में लोगों में भ्रम और खीझ पैदा होना स्वाभाविक था. यह कैसी विचारधारा है? बसों, ट्रेनों और चाय की दुकानों पर मतदाताओं की यह खीझ देखी, सुनी और महसूस की जा सकती थी. लोगों का प्रश्न था आखिर क्यों इस गठबंधन को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए?

विनय बिहारी सिंह

पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का भारी मतों से जीतना तो पहले से ही तय था. क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं रह गया था. कौन था तृणमूल कांग्रेस का मुख्य प्रतिद्वंद्वी? जवाब है, वाममोर्चा-कांग्रेस (वाम-कांग) गठबंधन. शुरू से इस गठबंधन ने लोगों में गहरा भ्रम पैदा किया. इस दोस्ती का अनेक लोग कोई अर्थ नहीं निकाल पा रहे थे. लोगों में चर्चा थी कि दो साल पहले केंद्र में कांग्रेस के शासनकाल में चरम भ्रष्टाचार हुए. सरकारी धन का दुरुपयोग, धन कुबेरों को डूबने वाला कर्ज़ देने और कुशासन के मामले में कांग्रेस बुरी तरह बदनाम पार्टी रही है. इस गठबंधन के पास न कोई साझा स्पष्ट नीति थी और न ही कोई आकर्षित करने वाला साझा एजेंडा. उनका नारा था, ममता बनर्जी के कुशासन को खत्म करें. मतदाताओं पर इस नारे का कोई खास असर नहीं था. रही सही कसर अखबारों में छपी एक फोटो ने पूरी कर दी. साझा चुनाव प्रचार के दौरान एक मंच पर वाममोर्चा के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बड़ी सी माला पहने प्रसन्न मुद्रा में खड़े थे. एक ही माला में दोनों नेता समाए हुए यूं दिख रहे थे जैसे कांग्रेस-कम्युनिस्ट भाई-भाई का नारा लगा रहे हों. सभी जानते थे कि केरल में कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियों के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ रही है. केरल में राहुल गांधी ने मंच से कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टियों की विचारधारा सदियों पुरानी है, जिसकी प्रासंगिकता आज खत्म हो चुकी है. इधर पश्चिम बंगाल में वही राहुल गांधी एक ही माला में एक घनघोर कम्युनिस्ट नेता के साथ प्रसन्नतापूर्वक समाए हुए थे. ऐसे में लोगों में भ्रम और खीझ पैदा होना स्वाभाविक था. यह कैसी विचारधारा है? बसों, ट्रेनों और चाय की दुकानों पर मतदाताओं की यह खीझ देखी, सुनी और महसूस की जा सकती थी. लोगों का प्रश्न था आखिर क्यों इस गठबंधन को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए? इनकी विचारधारा एक कैसे हो गई? क्या समानता है कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस सर्वहारा वर्ग की कब से हमदर्द हो गई? जब मतदाता यह प्रश्न उछालने लगे थे तभी लग गया कि कांग्रेस-वाममोर्चा गठबंधन को लोग धूल चटाने वाले हैं. चुनाव परिणाम आने के एक दिन बाद ही माकपा के राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्र ने एक संवाददाता सम्मेलन में अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन को उचित बताया और कहा कि कई वाममोर्चा के साथियों के विरोध के बावजूद यह जारी रहेगा. पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करने के बाद वह अलीमुद्दीन स्ट्रीट स्थित माकपा के राज्य मुख्यालय (सेक्रेटेरिएट) में ऐसा कह रहे थे. उन्होंने कहा, हम राज्य में चुनाव परिणामों की विस्तार से समीक्षा करेंगे. लेकिन जो लोग इस गठजोड़ पर सवाल उठा रहे हैं, वे गलत हैं. पिछली बार वाममोर्चा और कांग्रेस ने विधानसभा में 56 सीटें हासिल की थीं. इस बार हमारे गठजोड़ को 77 सीटें मिली हैं. पिछली बार से हम ज्यादा मजबूत हुए हैं. क्या यह प्रगति नहीं है? हम भविष्य में गठबंधन जारी रखने के लिए अपनी सहयोगी पार्टियों और कांग्रेस से बातें करेंगे. जो लोग इस गठबंधन का विरोध कर रहे हैं वे जनता के दिमाग में भ्रम और शंकाएं पैदा कर रहे हैं. मतदाताओं ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हमें वोट दिया है.

यह बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि माकपा का एक धड़ा राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्र और पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के गठबंधन सिद्धांत के खिलाफ था और है. मुखालफत करने वाले ये नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गठबंधन करके हमारे वोटों का फायदा उठाया और सिर्फ 91 सीटों पर लड़कर 44 सीटें हथिया ले गई. इधर माकपा, राजद और जद (यू) गठबंधन को 32 सीटों से ही संतोष करना पड़ा. राज्य स्तर के कुछ नेताओं ने तो मीडिया के सामने भी इस गठबंधन का विरोध किया. वाममोर्चा के चेयरमैन रहे विमान बोस ने कहा, एटा जोट कोथाय, घोंट होएछे. शुधू बोझापोड़ा होएछे (यह गठबंधन कहां है? यह तो एक पैच-अप था, आपसी सहमति थी). माकपा के पोलित ब्यूरो सदस्य मोहम्मद सलीम ने शुरू में ही कहा था कि यह गठबंधन ठीक नहीं है. उनका कहना था कि कांग्रेस, माकपा की मदद करने की स्थिति में नहीं है. इस चुनाव परिणाम ने दिल्ली के पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के लोगों को भी सोच में डाल दिया है. इस गठबंधन का माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने समर्थन किया था. अब पार्टी के भीतर उनके इस कदम की आलोचना हो रही है. पश्चिम बंगाल के माकपा के सचिव सूर्यकांत मिश्र भी इस आलोचना के शिकार हैं और भविष्य की बैठकों में भी होंगे. माकपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, भवानीपुर से ममता बनर्जी 25 हजार से कुछ ज्यादा वोटों से जीतीं. उनका वोट प्रतिशत 47.6 था. माकपा नेता कांति गांगुली को रायदीघी में 46 प्रतिशत वोट मिले. वह केवल 1200 वोटों से हारे. तो ये सारी बातें सेंट्रल कमेटी की बैठक में उठने वाली हैं. गठबंधन के समर्थन या विरोध वाले खेमों में इतनी असहमतियां हैं कि परिणाम आने में समय लग सकता है. ■

वाममोर्चा-कांग्रेस गठबंधन बना रहेगा: सूर्यकांत मिश्र

परिणाम सामने आए तो अगले दिन एक प्रमुख अखबार ने बुद्धदेव भट्टाचार्य की वह फोटो प्रकाशित की जिसमें वे गहरी सोच में डूबे हुए हैं. क्या यह आत्ममंथन की तस्वीर है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुरावरम सुधाकर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के साथ वाममोर्चा का गठजोड़ काम नहीं आया. हमें 36-36 प्रतिशत वोट मिलने चाहिए थे. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. हमें गंभीरता से आत्ममंथन करना होगा. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) जिसे हम संक्षेप में यहां माकपा लिखेंगे, की नेता वृंदा करात ने कहा कि चुनाव नतीजे आने के बाद गंभीर विचार-विमर्श की जरूरत आ खड़ी हुई है. इस बार हुए विधानसभा चुनाव में कुल 294 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 211, कांग्रेस को 44, वाममोर्चा (प्रमुख घटक माकपा) को 32 और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 3 सीटें मिली हैं. बाकी 4 सीटें अन्य उम्मीदवारों को मिली हैं जो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे थे.

निश्चय ही आप के मन में सवाल उठ रहा होगा कि चुनाव से ठीक पहले नारदा कांड, निर्माणाधीन फ्लाई ओवर के अचानक गिरने और तमाम तरह के आरोपों के बावजूद कैसे ममता बनर्जी की पार्टी को भारी बहुमत से जीत हासिल हो गई? आइए क्रम से इस पर गौर करते हैं.

सबसे पहला कारण है अल्पसंख्यकों का एकजुट होकर ममता बनर्जी का समर्थन करना. पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों की आबादी 25.2 प्रतिशत है. इस बार चुनाव में इस समुदाय के ज्यादातर लोग ममता बनर्जी के साथ थे. इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से ममता बनर्जी की छवि एक ईमानदार और कड़क नेत्री की है. उनकी साफ-सुथरी व्यक्तिगत छवि को कोई चुनौती नहीं दे सकता. सभी जानते हैं कि हवाई चप्पल पहन कर ही वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठती हैं. ममता पहली रेल मंत्री थीं जिन्होंने 60 साल और उससे ज्यादा की आयु वालों को वरिष्ठ नागरिक माना और उनके टिकट दर में छूट देने का ऐलान किया था. रेलवे में उनकी बनाई यह परंपरा आज भी जारी है. दूसरी खूबी यह है कि बिना लाग-लपेट के वह दो टूक बातें करती हैं. एकदम स्पष्ट शब्दों में. वहीं उनकी छवि में कोई दाग नहीं है.

दूसरा कारण यह है कि वाममोर्चा के शासन को मतदाता लगातार 34 सालों तक देख चुके हैं. कांग्रेस पश्चिम बंगाल के लोगों से लगातार दूर जा रही है. हालांकि, इस चुनाव में उसे 44 सीटें मिली हैं. लेकिन ये वही सीटें हैं, जहां के मतदाता पार्टी को नहीं, नेता को वोट देते हैं. भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में मजबूत जनाधार नहीं है. इस पार्टी के प्रति लोगों में आकर्षण का कोई कारण नहीं दिखता. महंगाई पहले से ज्यादा हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक पश्चिम बंगाल के लिए आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाए हैं. लोग अब तक समझ नहीं पा रहे हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें. यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी तीन सीटें ही बटोर सकी है. ये सीटें हैं- खड़गपुर सदर (पश्चिम मेदिनीपुर), मदारीहाट (अलीपुरदुआर) और वैष्णवनगर (मालदा). हालांकि भाजपा इस बात से खुश है कि उसकी सीटों की संख्या बढ़ रही है.

तीसरा कारण यह है कि लोग यह मानते हैं कि दीदी यानी ममता बनर्जी अपनी पार्टी के उन नेताओं को अवश्य दंडित करेंगी जो उन्हें बदनाम कर रहे हैं या जिनका नाम घोटालों में लेकिन उनके मंत्रिमंडल में रह चुके आठ नेता इस चुनाव में हार गए हैं. हार का मुंह देखने वाले ये नेता हैं- बिजली मंत्री रहे मनीष गुप्ता (जादवपर), क़ानून व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकीं चंद्रिमा भट्टाचार्य (दमदम-उत्तर), पिछड़ी जाति व जनजाति विकास मामलों के मंत्री रह चुके उपेन विश्वास (बागदा), कपड़ा मंत्री रह चुके श्यामापद मुखर्जी (विष्णुपुर), खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कृष्णेंदु नारायण चौधरी (इंग्लिश बाजार), बिना किसी विभाग की मंत्री रह चुकी सावित्री मित्र (माणिकचक), पीडब्लूडी मंत्री रह चुके शंकर चक्रवर्ती (बालूरघाट) और पूर्व परिवहन व खेल मंत्री मदन मित्र (कमरहाटी). मदन मित्र तो सारधा घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं. मतदाताओं को ये सभी मंत्री पसंद नहीं आए. पश्चिम बंगाल में इस जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को जाता है.

जो वाममोर्चा पश्चिम बंगाल में लगातार 34 सालों तक सत्ता में रहा, वह आज तीसरे नंबर पर है. जिस कांग्रेस पार्टी से उसने गठजोड़ किया था वह दूसरे नंबर पर आ गई और विपक्ष के नेता का पद मांगने लगी. अब तक यह पद वाममोर्चा के पास था. पिछली विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके माकपा के सूर्यकांत मिश्र इस बार भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किए गए थे, लेकिन वे अपने क्षेत्र नारायणगढ़ से हार गए. यह वाममोर्चा के लिए बड़ा झटका है. सूर्यकांत मिश्र की छवि तेज-तर्रार नेता की है. लेकिन मतदाताओं ने उन्हें अस्वीकार कर दिया. जिस सिंगुर को लेकर वाममोर्चा खुश था कि ममता बनर्जी तो इंतजार कर रहे किसानों को आखिरकार अधिग्रहित ज़मीन नहीं लौटा सकीं (मामला अदालत में है), वहां शायद जीत होगी, लेकिन यह खुशी कुछ ही दिनों की रही और माकपा के रॉबिन देव चुनाव हार गए. वहां तृणमूल कांग्रेस के रवींद्रनाथ भट्टाचार्य बीस हजार से ज्यादा वोटों से जीत गए.

मुख्यमंत्री समेत सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कई उम्मीदवार जीते तो हैं लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में जीत का अंतर काफी घट गया है. आइए कुछ उदाहरण देखें-

1. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, भवानीपुर विधानसभा सीट से पिछली बार 54,213 वोटों से जीती थीं. इस बार वह 25,301 वोटों से जीती हैं.
2. शोभनदेव चट्टोपाध्याय, रासबिहारी सीट से पिछली बार 49,894 वोटों से जीते थे. इस बार वह 14,553 वोटों से जीते हैं.
3. सुब्रत मुखर्जी, बालीगंज सीट से पिछली बार 41,184 वोटों से जीते थे. इस बार 15,225 वोटों से जीते हैं.
4. नयना बंद्योपाध्याय (सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय की पत्नी) चौरंगी सीट से पिछली बार 57,739 वोटों से जीती थीं. इस बार 13,216 वोटों से जीती हैं.
5. स्मिता बक्शी, जोड़ासांको सीट से पिछली बार 31,509 वोटों से जीती थीं. इस बार 6,290 वोटों से जीती हैं. इसी इलाके में फ्लाईओवर बनते समय ही गिर पड़ा था. स्मिता बक्शी पर बचाव कार्य में सक्रिय रूप से हिस्सा न लेने का आरोप था.
6. अरूप विश्वास, टॉलीगंज सीट से पिछली बार 27,860 वोटों से जीते थे. इस बार 9,896 वोटों से जीते हैं.
7. पार्थ चटर्जी, बेहला पश्चिम सीट से पिछली बार 59,021 वोटों से जीते थे. इस बार 8,896 वोटों से जीते हैं.
8. न्रत्य बसु, दमदम सीट से पिछली बार 31,477 वोटों से जीते थे. इस बार 9,316 वोटों से जीते हैं.
9. सुजीत बसु, विधान नगर सीट से पिछली बार 85,925 वोटों से जीते थे. इस बार 6,988 वोटों से जीते हैं.

इस तरह स्पष्ट है कि मतदाताओं में इन उम्मीदवारों के प्रति आकर्षण घटा है. लेकिन चूंकि ममता बनर्जी अकेले ही सौ पर भारी पड़ने वाली नेता हैं, इसलिए उनकी ईमानदार और जुझारू छवि ने ही इस बार सत्ता की चाभी उन्हें सौंप दी है.

किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले यह भी जान लें. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 44.9 प्रतिशत, कांग्रेस को 12.3 प्रतिशत, वाममोर्चा को 27.41 प्रतिशत, भारतीय जनता पार्टी को 10.2 प्रतिशत वोट मिले. इसमें एक बात नोट करने लायक है. जिस भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में सिर्फ चार प्रतिशत वोट मिले थे, आज उसे 10.2 प्रतिशत वोट मिल रहे हैं तो इसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है. चूंकि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, इसलिए वहां एक खास समुदाय के वोट भाजपा के पाले में जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए.

अब कांग्रेस-वाममोर्चा गठबंधन के कुछ अन्य तथ्यों और माकपा के भीतर इसे लेकर अंतर्विरोध के कुछ बिंदुओं पर नज़र डालें. पोलित ब्यूरो के ज्यादातर सदस्य जिनके अगुवा प्रकाश करात थे, कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन के विरोध में थे. करात ने सिर्फ तारकेश्वर में एक सभा को संबोधित किया. इसके बाद वह किसी जनसभा में नहीं आए. जबकि वृंदा करात और सीताराम येचुरी ने कुछ अन्य जनसभाओं को संबोधित किया. लेकिन ये नेता मंच पर कांग्रेस के नेताओं के साथ नहीं बैठे. लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पार्क सर्कस में आयोजित एक जनसभा में एक मंच पर बैठे और एक माला में समाए. अब पोलित ब्यूरो के जो लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन का विरोध कर रहे थे, वे खुलकर अपनी नाराज़गी जताने लगे हैं. माकपा के मोहम्मद सलीम पहले से ही इस गठजोड़ का विरोध करते रहे हैं. अब राज्य के माकपा सचिव सूर्यकांत मिश्र, जो खुद अपनी सीट पर हार गए हैं, पर जिम्मेदारी आ गई है. वह इस चुनावी हार का विश्लेषण पोलित ब्यूरो के सामने रखेंगे. यह तथ्य सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल माकपा के ज्यादातर स्टेट कमेटी के सदस्य कांग्रेस के साथ गठजोड़ चाहते थे. उनका कहना है कि वह 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ गठजोड़ रखना चाहेंगे. लेकिन अब इस गठजोड़ को दोहराना इतना आसान नहीं है क्योंकि पोलित ब्यूरो का एक बड़ा हिस्सा इसके खिलाफ था और है.

कांग्रेस पार्टी तो खुश है. माकपा के साथ गठबंधन का भरपूर फायदा उसे ही मिला है. उसने वाममोर्चा के मतदाताओं का वोट तो अपनी ओर खींचा ही है, अपने मतदाताओं की संख्या भी बढ़ाई है. इसीलिए कांग्रेस को कई लोग गठजोड़ का वोट सोख लेने वाली पार्टी कह रहे हैं. इसीलिए ममता बनर्जी के सामने यह गठजोड़ कमजोर का कमजोर ही रहा. ■

feedback@chauthiduniya.com

यूपी का राजनीतिक समीकरण गड्ड-मड्ड कर रहे पांच राज्यों के नतीजे

नए पैंतरे आजमाने पर हो रहा है चिंतन

चौथी दुनिया ब्यूरो

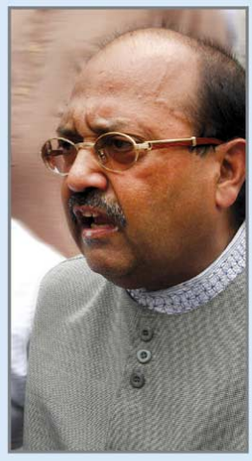
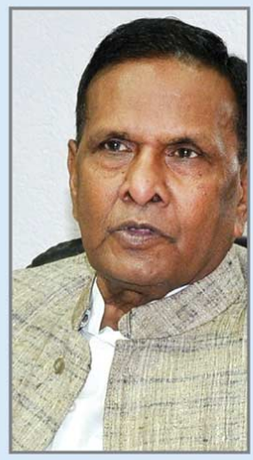

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे प्रत्यक्ष या परोक्ष उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर असर जरूर डालेंगे. परिणामों का असर ही है कि अभी कुछ दिन पहले तक चहल-पहल से भरी रही राजनीतिक गतिविधियां या बयानबाजियां फिलहाल थमी नज़र आती हैं. राजनीतिक प्रेक्षक इसे तूफान के पहले छाने वाला सन्नाटा बता रहे हैं. असम में भाजपा की जीत से न केवल भाजपा के राष्ट्रीय नेता बल्कि उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता भी उत्साह में हैं. वहीं ममता की धुआंधार जीत से गठबंधन महागठबंधन की प्रत्याशा में रात तक रही राजनीतिक पार्टियां अचानक सकते में आ गई हैं. यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी अपनी-अपनी रणनीतियों के बारे में पुनर्विचार कर रही हैं. सपा और बसपा दोनों को लग रहा है कि असम में चला मोदी का करिश्मा कहीं यूपी में भी उनके लिए मुश्किलें न खड़ी कर दे.

बदली हुई स्थिति में अब बसपा किसी से गठजोड़ करने पर विचार कर सकती है. बसपा के साथ कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलिमीन भी जा सकती है. वहीं सपा नेतृत्व भी राजनीतिक गठजोड़ की संभावनाएं तलाश रहा है. भाजपा अब उत्तर प्रदेश जीतने के लिए सारे प्रयास करेगी. लिहाजा, उत्तर प्रदेश ही अब एक साल तक चुनावी अखाड़ा बना रहेगा. बिहार में ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय राजनीति में भी दखल बढ़ाने की कोशिश शुरू की और उसके लिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक ज़मीन पुख्ता करने का अभियान चलाया. बिहार में शराबबंदी के कारण नीतीश की बढ़ी लोकप्रियता ने नीतीश कुमार के संघ मुक्त भारत अभियान के साथ-साथ शराब मुक्त समाज के अभियान को भी जोड़ दिया है. पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे नीतीश कुमार की रणनीति में अपेक्षित फेरबदल लाएंगे, राजनीतिक समीक्षक इसकी उम्मीद करते हैं. महागठबंधन के जरिए नीतीश कुमार के साथ जुड़ी कांग्रेस अब बदली हुई स्थितियों में यूपी में क्या करेगी, इस पर भी लोगों की निगाह है. वरिष्ठ राजनीतिकों का कहना है कि बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस से परहेज करने पर गंभीर हैं, क्योंकि बिहार में महागठबंधन से चिपक कर कांग्रेस ने फायदा उठाया, उसी तरह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने वाम मोर्चा के साथ चिपक कर उसका पूरा रस सोख लिया. 2017 में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं. लेकिन 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश का चुनाव इनमें सबसे अहम है. पंजाब की अहमियत उसके बाद है, जहां 117 सीटों वाली विधानसभा का चुनाव होना है. मणिपुर की 60 सीटों और गोवा की 40 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव होगा. ■

पांच राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे नीतीश कुमार की रणनीति में अपेक्षित फेरबदल लाएंगे, राजनीतिक समीक्षक इसकी उम्मीद करते हैं. महागठबंधन के जरिए नीतीश कुमार के साथ जुड़ी कांग्रेस अब बदली हुई स्थितियों में यूपी में क्या करेगी, इस पर भी लोगों की निगाह है.

सपा के लिए आसान नहीं 2017 की राहें

समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और उनके भाई शिवपाल सिंह यादव पूरी ताकत और मनोयोग के साथ प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता वापस पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं. जो लोग पार्टी से किसी न किसी कारण से नाराज़ होकर बाहर चले गए थे, उन्हें भी राज्यसभा व विधान परिषद का टिकट देकर पार्टी में उनकी पुनरवापसी तय की जा रही है. समाजवादी पार्टी में बेनी प्रसाद वर्मा, किरन पाल सिंह व अमर सिंह की फिर से वापसी हो गई है. यह वही बेनी प्रसाद वर्मा हैं जो कभी पानी पी-पीकर मुलायम सिंह को गरियाते थे और राहुल गांधी को रात में दो बजे भी पीएम बनवाने का सपना देखा करते थे. लेकिन अपने पुत्र-प्रेम में बेनी को सपा में आना पड़ा. इसका उन्हें लाभ भी हुआ और वह राज्यसभा पहुंच गए. इसी प्रकार अमर सिंह का भी राजनीतिक वनवास पूरा हुआ.

बेनी प्रसाद वर्मा और पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री किरनपाल सिंह की वापसी का ऐलान करते हुए सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि उनकी वापसी का संदेश केवल यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली तक जाएगा और अब दिल्ली दूर नहीं है. सपा के इस अभियान से कांग्रेस के पीके अभियान को गहरा आघात लगा है. वहीं प्रदेश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ रही सक्रियता को भी जातिगत आधार पर चोट लगी है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बेनी प्रसाद वर्मा बाराबंकी जिले के कद्दावर कुर्मी नेता हैं. वर्मा का आसपास के कुर्मी और मुस्लिम बहुल जिलों में अच्छा खासा प्रभाव है. यदि आजम खां सहित कुछ मुस्लिम वर्ग सपा से नाराज़ होता भी है तो उसकी भरपाई बेनी प्रसाद वर्मा के बहाने हो जाएगी. सपा छोड़ने के पूर्व बाराबंकी जिले में समाजवादी का मतलब बेनी बाबू ही होता था लेकिन बीच में सपा मुखिया से मनमुटाव होने के कारण बेनी कांग्रेस में चले गए थे. अब इस दौरान कांग्रेस का ग्राफ तेज़ी से गिर रहा है तथा पीके की अगुवाई में भी कांग्रेस की हालत खस्ता होती दिखाई पड़ रही है. बेनी के लिए यह भी परेशानी का सबब था कि कांग्रेस में उन्हीं के जिले के पीएल पुनिया का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा था. इसलिए उनके समाजवादी होने का रास्ता आसान हो गया.

रही बात किरन पाल सिंह की तो वह भी जाट नेता हैं तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा के पास कोई मजबूत जाट नेता नहीं था, इसलिए उन्हें चौधरी अजित सिंह को उन्हीं के घर में घेरने के लिए सपा में शामिल किया गया है. अब इन नेताओं की सपा में वापसी अपने क्षेत्रों की राजनीति में कितना गुल खिलाएगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अहम यह है कि बेनी के सपा में आने के बाद बाराबंकी व आसपास के जिलों में कांग्रेस के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है. अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं. साथ ही यह भी संभावना प्रतीत हो रही है कि जब इस क्षेत्र में बहुबलीय जोरदार मुकाबला होगा तो कम से कम यह क्षेत्र कांग्रेसमुक्त तो हो ही जाएगा. विधानसभा चुनाव में बेनी के बेटे राकेश वर्मा को टिकट मिलना भी सुनिश्चित हो गया है. उधर, अमर सिंह भी अपना राजनीतिक अंतःवास समाप्त करने के लिए बहुत उत्सुक थे. मुलायम ने उन्हें राज्यसभा का पास देकर आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका तय कर दी. राजनीतिक जोड़-तोड़ में अमर को महारत हासिल है, जिसका फायदा वह सपा को दिलाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे. ■

चुनावी नतीजों ने बिगाड़ा गठबंधन का स्वाद

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वामदलों की हुई भारी फजीहत के बाद बिहार में नीतीश कुमार के मिशन-2019 की संभावनाओं और रणनीति को लेकर राजनीतिक गलियारे में मंथन तेज है. गर्मागर्म बहसें जारी हैं और अपने-अपने हिसाब से नतीजे निकाले जा रहे हैं. पांच राज्यों के रिजल्ट्स ने नीतीश कुमार की दिल्ली-लक्ष्य की चुनौतियां बढ़ा दी हैं. अब तक नीतीश बनाम नरेंद्र मोदी की चर्चा आम थी. अब इस लड़ाई में ममता बनर्जी और जयललिता जैसे दो नए किरदार और शामिल हो गए हैं. ममता ने चुनाव जीतने के बाद कहा भी कि वह राष्ट्रीय राजनीति में जा सकती हैं. बंगाल में अपने दम पर शानदार जीत दर्ज करने वाली ममता बनर्जी और तमिलनाडु में दूसरी बार लगातार सत्ता हासिल कर इतिहास रचने वाली जयललिता को जनता ने इस दौड़ में शामिल कर दिया है. नीतीश कुमार के विरोधी नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी और जयललिता अपने बूते चुनाव जीत कर आईं, जबकि नीतीश कुमार गठबंधन के सहारे ही चुनाव जीतते और सत्ता पर काबिज होते रहे. वे कभी राजग के साथ रहे तो अभी राजद के साथ हैं. ममता बनर्जी की भी छवि कुशल प्रशासक की है, इसलिए जब 2019 के लिए कांग्रेस से इतर नेता चुनने की बात आएगी तो नीतीश कुमार के अलावा ममता भी महत्वपूर्ण विकल्प हो सकती हैं.

जदयू के लिए यह चिंता का विषय जरूर है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में जदयू उम्मीदवारों का प्रदर्शन बेहद फीका रहा. केरल में जदयू ने अपने सात उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें दो मौजूदा विधायक भी थे. लेकिन इनमें से कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया. जबकि नीतीश कुमार ने कुत्थूरबा, वटकारा और कोझीकोड में चुनाव प्रचार भी किया था. इसी तरह असम में जदयू ने एआईयूडीएफ के साथ तालमेल कर चार सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, पर इनमें कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया. असम में जदयू को कुल तीन हजार 20 वोट मिले. बंगाल में भी कांग्रेस और वाममोर्चा के साथ तालमेल कर दो सीटों पर जदयू ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन नाकामयाबी नहीं हाथ लगी. लिहाजा, पार्टी में नए सिरे से रणनीति तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है. बंगाल और असम के चुनाव परिणामों पर नीतीश कुमार ने गठबंधन और तालमेल को सवाल उठाए और भाजपा के ख़िलाफ़ वृहत्तर एकता की जरूरत को रेखांकित किया. नीतीश कुमार ने कहा कि वक्त आ गया है कि देशभर की समाजवादी शक्तियां एक मंच पर आएं. भाजपा की विचारधारा का विरोध करने वाले दल कैसे एक मंच पर आएं. इसके लिए नीतीश की कवायद जारी है, पर उनके रणनीतिकार इस बात को लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं कि जिस रास्ते पर अब तक का सफर नीतीश कुमार ने तय किया है उस रास्ते को और कितना परिमार्जित करने की जरूरत है.

नीतीश खेमे में चल रहे रणनीतिक मंथन के बीच राजद के तीन बड़े नेताओं तस्लीमुद्दीन, रघुवंश सिंह और प्रभुनाथ सिंह के मुखालफती सुर किरकिरी पैदा कर रहे हैं. जदयू ने इन सारे बयानों को काफी गंभीरता से लिया है, लेकिन पार्टी नेता राजद नेतृत्व के रुख का आकलन कर रहे हैं. लालू प्रसाद के बारे में एक बात यह भी कही जा रही है कि जो वह खुद अपने मुंह से नहीं कहते, उसे अपने नेताओं से कहवा रहे हैं. प्रशासनिक कामकाज और नौकरशाही पर नीतीश के अकेले नियंत्रण से भी लालू को नाराज़गी है. राजद और जदयू के बीच इस कटु-मधुर संबंध को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान कहते हैं कि मौजूदा सरकार ढाई साल में गिर जाएगी. पासवान का आरोप है कि गठबंधन में तालमेल का बेहद अभाव है और यह बिहार के लिए अशुभकारी है. बिहार की क़ानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी प्रधानमंत्री से मिल भी आए हैं. भाजपा नेता सुशील मोदी कहते हैं कि बिहार में अराजक स्थिति बनती जा रही है. ■

भाजपा का हाइटेक उत्साह

असम की जीत से पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा खेमे में काफी उत्साहजनक सरगर्मी है. विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश भाजपा को हाइटेक और डिजिटल करने का अभियान तेज़ी से चल रहा है. भाजपा के पार्टी दफ्तरों में अब एक मॉडर्न कार्य संस्कृति जगह बना रही है. लखनऊ में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले अटेंडेंस कार्ड देने पर विचार हो रहा है. इसके जरिए पार्टी के वरिष्ठ नेता यह जान सकेंगे कि कोई नेता दफ्तर में कितनी जल्दी आता है और कितना समय व्यतीत करता है. उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों को 2019 के आम चुनावों के संकेत के रूप में देखा जाएगा. पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में यूनिक नंबर होंगे, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं को विभिन्न दस्तावेजों, पार्टी की नीतियों और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारियां मिलेंगी और ऑनलाइन लाइब्रेरी के इस्तेमाल में उन्हें सहूलियत होगी.

अब सारी रिपोर्टें भी ऑनलाइन ही फाइल करनी होंगी. वरिष्ठ नेताओं से कहा गया है कि विभिन्न बैठकों और चर्चाओं के बारे में वे ऑनलाइन रिपोर्ट फाइल करें. इन रिपोर्टों की केंद्रीय नेताओं और ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा समीक्षा की जाएगी. यह ऑनलाइन सुविधा जुलाई से चालू हो जाएगी और पहले फेज में मंडल स्तर के 1,800 पदाधारी इससे जुड़ेंगे. बाद में करीब 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को राज्य मुख्यालय से ऑनलाइन जोड़ दिया जाएगा, जो मतदान के दौरान बूथ लेवल पर काम करेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

झाविमो को साथ लेकर नीतीश झारखंड में भी तैयार कर रहे महागठबंधन की जमीन

शराबबंदी के साथ लामबंदी

प्रशांत शरण

अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर झारखंड पर है, आदिवासी चेहरा बाबूलाल मरांडी को आगे कर नीतीश ने यहां पैर जमाना शुरू कर दिया है. वैसे शराबबंदी के बहाने जनता दल युनाइटेड सुप्रीमो ने झारखंड की ओर रुख किया है पर इनकी नजर अगले विधानसभा चुनाव पर है. नीतीश ने अपना अभियान झारखंड के धनबाद से शुरू किया और अपनी पहली ही सभा में लोगों की भीड़ देख गदगद हो गए. झारखंड में अगंद की तरह पांव जमाने के लिए झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का दामन थामा है और झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी भी लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं. बाबूलाल भी मजबूत जमीन की तलाश में हैं और नीतीश का समर्थन पाकर उत्साहित हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबूलाल को झारखंड का अगला सीएम भी घोषित कर दिया है. बाबूलाल की पहचान झारखंड में एक ईमानदार और कर्मठ नेता के रूप में है. भाजपा से अलग होने के बाद इन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया और विधानसभा चुनाव में आठ सीटों पर कब्जा भी किया पर भाजपा नेताओं ने इनकी पार्टी में सेंधमारी कर इनके छह विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया. अगर बाबूलाल और जदयू एक हुए तो अगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने होंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबूलाल के साथ अभी लगातार मंच साझा कर रहे हैं. झारखंड विकास मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक में भी नीतीश मुख्य अतिथि के हैसियत से आए हुए थे और इस बैठक में ही बाबूलाल को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया गया. नीतीश ने यह भविष्यवाणी की कि झारखंड के लोग बाबूलाल के तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और पार्टी को जो समर्थन मिल रहा है उससे यह लग रहा है कि अगला चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाने वाली है और यहां बाबूलाल एवं गठबंधन दलों की ही सरकार बनेगी. नीतीश कुमार की इस घोषणा के बाद बाबूलाल कहां पीछे रहने वाले थे. उन्होंने भी नीतीश को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में पेश करते हुए कहा कि साम्प्रादायिक ताकतों को जनता उखाड़ फेंकेगी और नीतीश के हाथों में ही भारत का नेतृत्व होगा.

झारखंड में जदयू के बढ़ते जनाधार का देख भाजपा खेमे में हडकंप है. भाजपा को यह अहसास है कि नीतीश अगर बाबूलाल का आदिवासी चेहरा आगे कर गठबंधन बनाने में सफल रहे तो भाजपा को लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है. इस गठबंधन में कांग्रेस एवं राष्ट्रीय जनता दल का भी आना तय है. राजद की जहां झारखंड के सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्रों पर अच्छी पकड़ है, वहीं कांग्रेस के भी इस गठबंधन में आ जाने से अल्पसंख्यक मतदाताओं का रुझान इस ओर बढ़ेगा और अगर एकमुश्त वोट इस गठबंधन को मिल गया तो अगले चुनाव में इस गठबंधन को बहुमत मिलने से कोई नहीं रोक सकता. भाजपा चुनाव में अलग-थलग पड़ जाएगी, क्योंकि संथाल परगना सहित अन्य क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी भाजपा के सामने एक मजबूत खंभे के रूप में सामने खड़ी है. झामुमो की संथाल परगना सहित कोल्हान प्रमंडल में अपने वोटरों पर अच्छी पकड़ है. झारखंड विकास मोर्चा भी पिछले विधानसभा चुनाव में आधे से ज्यादा सीटों पर दूसरे स्थान पर रहा था और इसबार गठबंधन के साथ आने पर उसे पूरा लाभ मिल सकेगा.

इसी से बौखला कर भाजपा ने नीतीश पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिया है. भाजपा नीतीश को सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित करने में लगी हुई है. राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में नीतीश ने पहले शराब की नदियां बहाकर लोगों को नशेड़ी बना दिया और अब शराबबंदी लागू कर वाहवाही लूटने में लगे हैं. बिना तैयारी के बिहार में शराबबंदी किए जाने का दुष्परिणाम सामने दिख रहा है. शराब की तस्करी बढ़ी है और लोग अवैध शराब के सेवन से मर रहे हैं. अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार इस बात को हवा देने में लगे हुए हैं कि बिहार में शराबबंदी के कारण अपराध में कमी आई है. जबकि रोज हत्याएं, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही हैं पर इसकी चिंता नीतीश को नहीं है और वे शराबबंदी को लेकर दूसरे राज्यों में राजनीति करने में व्यस्त हैं. नीतीश सत्ता के नशे में चूर हैं और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं. रघुवर दास ने कहा कि नीतीश का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, वे सपना देखना छोड़ कर बिहार को संवारें अन्यथा जनता अगले चुनाव में मजा चखा देगी.

दरअसल, नीतीश चाणक्य की तरह झारखंड की सीमाओं पर अपना जनाधार मजबूत कर झारखंड की राजनीति पर कब्जा की कोशिश में लगे हैं. उन्हें यह पता है कि झारखंड में भाजपा अन्तरकलह से गुजर रही है. गैरआदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से भाजपा के आदिवासी विधायकों ने अपना अलग खेमा बना लिया है. इस खेमे का नेतृत्व पर्दे के पीछे से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ही कर रहे हैं, जिनका शुरू से ही रघुवर दास के साथ छत्तीस का रिश्ता रहा है. मुंडा के साथ 28 आदिवासी विधायकों का कुनबा है और रघुवर को भी इस बात का अच्छी तरह से अहसास है कि मुंडा कभी भी उनकी सरकार गिरा सकते हैं. रघुवर को अपनी ही पार्टी के विधायकों पर विश्वास नहीं है और यही कारण है कि भाजपा को विधानसभा में बहुमत मिलने के बाद भी आलाकमान सहित खुद रघुवर आश्वस्त नहीं थे. भाजपा ने झारखंड विकास मोर्चा के विधायकों को तोड़ अपनी पार्टी में शामिल करा लिया. झाविमो के आठ में से छह विधायकों को भाजपा ने अपने पक्ष में कर लिया. इसके बाद भी भाजपाइयों की नजर कांग्रेस के विधायकों पर थी, पर कांग्रेस को तोड़ने में भाजपा असफल रही. कांग्रेस को नहीं तोड़ पाने के बाद भविष्य में अगर सरकार पर कोई संकट नजर आए तो सरकार कैसे बचे, इस रणनीति के तहत मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेना ठीक समझा. हर किसी विशेष मौके पर वे शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेना नहीं भूलते. रघुवर को गुरु जी पर पूरा भरोसा है कि अगर अर्जुन मुंडा ने कभी सरकार गिराने का प्रयास किया तो ऐसी स्थिति में झामुमो का समर्थन लेकर सरकार बचाई जा सकती है. दरअसल, मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तर्ज पर ही काम कर रहे हैं और किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ उनकी दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं. हाल ही में राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय के साथ हुए टकराव की कहानी समाचारपत्रों में सुर्खियां बटोर चुकी हैं. राय झारखंड राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और बाबूलाल की सरकार गिराने में राय ने अर्जुन मुंडा के साथ अहम भूमिका निभाई थी. ऐसी चर्चा है कि जल्दी ही फिर सरकार गिरेगी और मुंडा की ताजपोशी होगी. यही स्थिति झारखंड में बनती दिख रही है और रघुवर सरकार पर संकट के बादल गहराने लगे हैं. नीतीश कुमार भाजपा के इसी अन्तरकलह का फायदा उठाने में लगे हुए हैं. अब देखना है कि वे इस रणनीति में कितना सफल रहते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

कई सवालों पर बेबाकी से बोले बिहार के मुख्यमंत्री

हर हाल में जाएगी भाजपा सरकारः नीतीश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर पूरे देश में अभियान चलाने की बात कहते हैं. उन्होंने कहा कि शराब ने न जाने कितने परिवारों को बर्बाद किया है. बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जब ग्रामीण महिलाओं की स्थिति देखी और जब उन्होंने इस संबंध में जानकारी ली तो यह जानकर हम हतप्रभ हो गए कि परिवार की बर्बादी का मुख्य कारण शराब है. मैंने उसी दिन प्रण किया था कि अगर मैं सत्ता में दुबारा आया तो पूर्ण शराबबंदी लागू करूंगा और जनता से जो मैंने वादा किया था उसे पूरा किया. झारखंड में आपकी सरकार नहीं है, फिर यहां आप शराबबंदी कैसे लागू कराएंगे? इस सवाल पर नीतीश ने कहा कि इस अभियान में मुझे झारखंड की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, धनबाद से मैंने जब इस अभियान की शुरुआत की तो वहां उमड़े जनसैलाब को देख कर आश्चर्यचकित हो गया. मुझे यह अहसास हुआ कि झारखंड के लोग शराब से ज्यादा परेशान हैं, खासकर आदिवासी समुदाय. मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास से अनुरोध किया है कि वे झारखंड में भी पूर्ण शराबबंदी लागू करें. नीतीश ने कहा कि अगर झारखंड के मुख्यमंत्री को बिहार से विंध है तो वे गुजरात मॉडल को ही लागू करें. गुजरात में तो भाजपा की ही सरकार है और ऐसे भी महात्मा गांधी की ही इच्छा थी कि देश में शराब का सेवन न हो. नीतीश कुमार यह भी दावा करते हैं कि इस सरकार ने अगर इसे लागू नहीं किया तो जनता अगले चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएगी, इसके बाद सूबे में जब बाबूलाल मरांडी की सरकार बनेगी तो इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा. क्या आप इस बात से आश्वस्त हैं कि अगली सरकार बाबूलाल की ही बनेगी? इस सवाल पर नीतीश ने कहा कि झारखंड की जनता यह जान गई है कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और इस सरकार से उनलोगों का भला नहीं होने वाला है, ऐसे में निश्चित तौर पर अगली सरकार गैर भाजपाइयों की नहीं होगी. झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी इस गठबंधन में शामिल करेंगे? इस सवाल पर नीतीश बोले कि भाजपा को छोड़ कर सभी दलों से बातचीत की जाएगी और सबको एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि साम्प्रादायिक ताकतों से आम लोगों को मुक्ति मिल सके और लोग चैन से रह सकें. मुख्यमंत्री का यह दावा है कि शराब से अपराध घटता है, और बिहार में अपराध का ग्राफ तीन माह में ही कम हो गया है. क्या बाबूलाल मरांडी को गठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करेंगे? नीतीश ने कहा कि यह सभी दलों की राय से ही होगा, वैसे बाबूलाल मरांडी की छवि एक ईमानदार और कर्मठ नेता की है और इसका लाभ गठबंधन को मिलेगा.

झारखंड में सोच-समझकर निर्णय लिया जाएगाः सिंह

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की झारखंड में पैर जमाने की कोशिश से प्रदेश भाजपा के नेताओं में बेचैनी है. बौखलाए भाजपा नेता नीतीश पर जमकर निशाना साध रहे हैं. राज्य के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि नीतीश ने दस साल तक बिहार में शराब की नदियां बहाकर बिहारियों को शराबी बनाया और अब शराबबंदी की राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बहाने नीतीश झारखंड में राजनीति कर रहे हैं. नगर विकास मंत्री कहते हैं कि झारखंड में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. वे कहते हैं कि बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं लेकिन नीतीश को इसकी कोई चिंता नहीं है, उन्हें राजनीति की पड़ी है. मंत्री ने स्पष्ट कहा कि झारखंड में शराबबंदी के मसले पर हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा. इस संबंध में लोगों को पहले जागरूक किया जाएगा, साथ ही पड़ोसी राज्यों से यहां शराब आने पर कैसे रोक लगे, यह सब सोचकर और उसका उपाय करने के बाद ही इस बारे में सरकार कुछ निर्णय लेगी. सिंह तल्खी से कहते हैं कि नीतीश की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, पर उनका मंसूबा कभी पूरा नहीं होने वाला.

झारखंड में शराबबंदी लागू करनी ही होगी : मरांडी

झारखंड में नीतीश कुमार के शराबबंदी अभियान का साथ दे रहे झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में हर हाल में शराबबंदी लागू करनी होगी. मरांडी का कहना है कि जिस तरह से महिलाएं शराब के खिलाफ आगे आई हैं, उसे देखते हुए झारखंड सरकार अब इस मुद्दे को बहुत दिनों तक नहीं टाल सकती. यहां शराब को आदिवासियों की संस्कृति से जोड़कर बदनाम किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि सबसे पहले झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने ही हुंडी से शराब के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था. उस वक्त इसे लेकर शिबू सोरेन को व्यापक समर्थन मिला था. बाद में भी उन्होंने कई बार यह अभियान चलाया. इसलिए आदिवासियों को बदनाम करने की साजिश बंद करनी चाहिए. शराब के कारण सबसे ज्यादा आदिवासी दलित परिवार ही प्रभावित हो रहे हैं. आदिवासी शराब के ज्यादा सेवन के कारण ही 40 - 42 वर्ष की उम्र में ही बूढ़े हो जा रहे हैं और अकाल मौत का शिकार हो जाते हैं. क्या शराबबंदी अभियान के सहारे सत्ता पाने की ललक तो नहीं? इस सवाल पर मरांडी ने कहा कि शराबबंदी लोगों के हित में है. मैं जनता के लिए ही काम करता हूं न कि पूंजीपतियों के लिए. जनता मुझे प्यार दे रही है और भाजपा को सबक सिखाना चाह रही है. क्या आपकी पार्टी का जदयू में विलय हो जाएगा? इस पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला पार्टी की कार्यसमिति करेगी. नीतीश के समर्थन के सवाल पर उन्होंने कहा कि जदयू का पूरा समर्थन उन्हें मिल रहा है. उनकी पार्टी जदयू के साथ मिलकर पूरे राज्य में भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की रणनीति बना रही है. इसका लाभ अगामी चुनावों में गठबंधन को मिल सकता है.

www.kamalmorarka.com

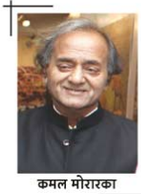

कमल मोरारका

दो साल बाद समाज का हर तबक़ा निराश है

सरकार क्या कर सकती है? एक काम उन्हें जरूर करना चाहिए. पब्लिक सेक्टर में सरकार को बहुत भारी मात्रा में निवेश करना चाहिए. ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा निवेश है. लेकिन भारत जैसे देश में इसके ठीक उलट है. हो सकता है कि आप जवाहर लाल नेहरू की आलोचना कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर की आलोचना कर सकते हैं, उसमें भ्रष्टाचार की बात करें, लेकिन यह सब अंधी दौड़ में शामिल होने जैसा है. रक्षा क्षेत्र में में हमने निर्णय लिया है कि जो हथियार हम बाहर से ला रहे हैं, उनका निर्माण हमें खुद करना चाहिए. यह अच्छी बात है. सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? हमारे पास पैसा है, विशेषज्ञता है. आप रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में निवेश क्यों नहीं करते हैं? ज़ाहिर है, कुछ समस्याएं हैं. समस्या यह है कि भाजपा एक दक्षिणपंथी पार्टी है और इसका मानना है कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है यह बात कहने के लिए तो ठीक है लेकिन सच यह है कि यदि नरेन्द्र मोदी मेक इन इंडिया कार्यक्रम को कामयाब होता देखना चाहते हैं तो उन्हें इस सिलसिले में एक काम ज़रूर करना चाहिए कि अलगे एक साल में उद्योग के क्षेत्र में भारी निवेश करें. उनके पास अभी भी तीन साल का समय शेष है. यदि प्राइवेट सेक्टर आता है तो ठीक है. यदि नहीं आता है तो सरकार को यह काम स्वयं करना चाहिए. इस वजह से बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा होंगे, अर्थव्यवस्था में एक बार फिर आत्मविश्वास पैदा होगा और एक बार जब सरकार पैसा लगाना शुरू कर देगी तो प्राइवेट सेक्टर का पैसा भी आना शुरू हो जाएगा. इसके लिए दो उपाय करने होंगे. पहला डर के माहौल को ख़त्म करना होगा और दूसरा सरकार को अनिवार्य रूप से भारी निवेश करना होगा. सरकार ने जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए मेरे ये सुझाव हैं.

अब ज़रा विपक्ष की बात करते हैं. कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और जिसका पूरे देश में आधार है, दुर्भाग्यवश वह हतोत्साहित हो गई है, जो किसी भी राजनितिक दल के लिए ठीक नहीं है. दूसरा यह कि उसका लोकसभा में केवल 44 सीटों पर सिमट जाना बुरा था, लेकिन एक वक़्त ऐसा भी था जब लोकसभा में भाजपा के केवल दो सदस्य थे. लिहाज़ा केवल एक चुनाव में मिली हार से बहुत फर्क नहीं पड़ता. आपको अगले चुनाव की तैयारी करनी चाहिए. दुर्भाग्यवश कांग्रेस गतिहीन हो गई है. ऐसा लगता है उनके अंदर की इच्छा शक्ति ही समाप्त हो गई है. यह ठीक नहीं है. अभी-अभी पांच राज्यों में चुनाव हुए हैं. तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और भाजपा दोनों का कुछ भी दांव पर नहीं लगा था. केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच हर चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वहां कांग्रेस की हार से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए. केवल असम एक ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस 15 साल से सत्ता में थी. कांग्रेस को असम में कुल 31 प्रतिशत वोट मिले और भाजपा को 29 प्रतिशत वोट मिले. असम गण परिषद की वजह से भाजपा एक गठबंधन बना पाई. भाजपा के लिए सबकुछ बहुत अच्छा नहीं है, जैसा कि उनके नेता इतने जोर-शोर से दावा कर रहे हैं. और कांग्रेस के लिए स्थितियां उतनी भी बुरी नहीं है जैसा कि उसके नेता समझ रहे हैं. फिर भी उन्हें यह ज़रूर तय करना चाहिए कि उनका नेता कौन है? राहुल अगर नेता बनना चाहते हैं तो उन्हें पार्टी को आगे ले जाना चाहिए, अगर वह नहीं चाहते हैं तो उन्हें पार्टी की बाग़-डोर किसी कार्यकारी अध्यक्ष के हाथों में दे देना चाहिए. यदि कांग्रेस ने अभी से काम करना शुरू कर दिया तो 2019 में उसका प्रदर्शन उतना बुरा नहीं होगा जैसी आशंका पार्टी के लोग जता रहे हैं.

अब मीडिया की बात. यह बड़े अफसोस की बात है कि सबसे बड़ी निराशा न तो एनडीए सरकार है और न ही विपक्षी कांग्रेस है, बल्कि सबसे बड़ी निराशा मीडिया है. अधिकांश मीडिया पथभ्रष्ट हो गई है. इन पांच राज्यों के चुनाव को ही ले लीजिए, मीडिया इस तरह दिखा रहा है जैसे कि पूरा देश भाजपा के पाले में चला गया हो. भाजपा को क्या मिला है केवल असम! मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि भाजपा के लोग असम को उत्तर प्रदेश क्यों समझ रहे हैं. असम लोकसभा में 14 सदस्यों को भेजता है. ऐसा लग रहा है कि असम जीतने के बाद 2019 ही जीत लिया. सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, 14 जीत गए हैं बाक़ी के 258 भी आ जाएंगे. यह कैसा मजाक है? लेकिन मीडिया में इक्का-दुक्का आलेखों को छोड़कर जिनमें समस्या का विश्लेषण किया गया और जिनकी मैं ज़रूर तारीफ करूंगा, अधिकांश मीडिया अंधदौड़ में लगा हुआ है जो बिलकुल ठीक नहीं है. मीडिया किसी भी देश के लोकतंत्र का रक्षक होता है, अगर मीडिया मदद न करे तो लोकतंत्र के पथभ्रष्ट होने में अधिक वक्त नहीं लगेगा. विधायिका और कार्यपालिका के अलावा मीडिया और न्यायपालिका दो स्तंभ हैं जो लोकतंत्र की निगरानी करते हैं. न्यायपालिक कभी-कभी ऐसा व्यवहार करती है जिसे समझना मुश्किल हो जाता है. प्रेस तो बहुत ही बुरी स्थिति में है. बेशक यहां पैसे की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को टीआरपी की ज़रूरत होती है और प्रिंट मीडिया को विज्ञापन की. ये सारी समस्याएं अपनी जगह हैं, लेकिन पत्रकारिता में एक मिशन ज़रूर झलकना चाहिए, यह मिशन केवल नाम के लिए ही नहीं होना चाहिए. नहीं तो प्रेस का पूरा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा. आशा करनी चाहिए की चीज़ें बेहतर होंगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

घूस का सच क्या है

अगस्टा वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर को लेकर प्रतिदिन नई-नई खबरें आ रही हैं. इटली की एक अदालत का फैसला आने के बाद से देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है. हेलिकॉप्टर सौदे को लेकर भाजपा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को निशाना बना रही है. लेकिन यह सवाल है कि अगर हेलिकॉप्टर सौदे में घूस लेने के बारे में सरकार के पास सबूत थे, तो वह दो साल तक चुप क्यों बैठी रही? इटली की कोर्ट द्वारा इसमें सजा सुनाए जाने और घूस लेने की बात कह जाने के बाद ही भारत सरकार क्यों जागी? इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो.

–सुशील यादव, *भोपाल, मध्य प्रदेश.*

सुरक्षा की गारंटी दे

बिहार के सीवान में हिंदुस्तान दैनिक के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन एवं उससे पहले की आपराधिक वारदातों में कई बेगुनाहों की मौत ने यह साबित कर दिया है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढता जा रहा है. उनके मन से पुलिस का खौफ कम होता जा रह है. जाहिर है, यह कानून और पुलिस की निष्क्रियता का भी नतीजा है. नीतीश कुमार से अनुरोध है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने वाले, चाहे वे कोई भी हो, उनको न केवल जेल के अंदर डालिए, बल्कि उनको आप सजा भी दिलाएं. सजायाफ्ता रसूखदार मुजरिम, राजद के अहम पद पाए हुए है. ऐसे व्यक्ति का राजनीतिक संरक्षण खत्म होना चाहिए. आप इस बात की गारंटी दीजिए कि अब कोई भी व्यक्ति, परिवार लाचार एवं बेबस हो चुकी कानून व्यवस्था का शिकार नहीं हो पाएगा. तभी आपकी कुछ वर्षों वाली छवि कायम रह पाएगी. अन्यथा आपकी वर्तमान छवि को धक्का लगेगा.

–संजय कुमार, *समस्तीपुर, बिहार.*

न्याय की दरकार

उत्तर प्रदेश में जब भी कोई पीड़ित फरियादी तहसील दिवस या जिलाधिकारी और मण्डलायुक्त के जनता दरबार में किसी के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र देता है, तो उसकी जांच उसी अधिकारी को सौंप दी जाती है जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है. ऐसी दशा में क्या कोई भी दोषी अधिकारी/कर्मचारी अपने ही विरुद्ध आख्या देगा या अपनी गलती स्वीकार करेगा? इस विसंगति को उजागर करने के लिए उदाहरण के लिए सूच्य है कि मैंने जब जिला मनोरंजन कर विभाग फैज़ाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जिला मनोरंजन कर अधिकारी फैज़ाबाद के विरुद्ध एक आरटीआई लगाई, जिसमें वे बूरी तरह फंस रहे थे. और इस वजह से वह नाराज़ होकर उन्होंने केबल ऑपरेटर अनिल गुप्ता पर दबाव डालकर नियमित भुगतान किए जाने के बावजूद मेरे डिश कनेक्शन कटवा दिया. मनोरंजन कर अधिकारी और ऑपरेटरों की मिलीभगत की वजह से कोई भी केबल ऑपरेटर मासिक किराया भुगतान की रशीद नहीं देता है. ऑपरेटरों के खिलाफ डिश टीवी उपभोक्ताओं ने शिकायती पत्र पर हस्ताक्षर कर और मनोरंजन कर चोरी के सबूत के साथ तहसील दिवस के मौके पर सदर फैज़ाबद में 7 अक्टूबर और 5 नवंबर 2014 को शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिम आज तक न्याय नहीं मिला, क्योंकि यह विभाग सीधे जिलाधिकारी के अधीन कार्यरत है.

फिर भी उसी आख्या को आधार बनाकर, उसे अंतिम सच मानकर यह प्रकरण मेरे विरुद्ध मंडल स्तर तक निस्तारित कर दिया गया है. जबकि मेरे समर्थन कई तथ्य और सबूत संलग्न थे. जिसपर मैंने 27 अगस्त 2015 को आरटीआई के माध्यम से जो 6 प्रश्न जिलाधिकारी और मंडलायुक्त फैजाबाद के विरुद्ध खड़े किए हैं उनका बिंदुवार जवाब फंस जाने के डर से आज तक नहीं दिया गया है.

अत: हालात, तथ्यों एवं प्रमाणों को देखते हुए इस मामले में दोषी मनोरंजन कर अधिकारी फैज़ाबाद को दंडित किया जाए.

–शिवकुमार फैजाबादी, *स्वतंत्र पत्रकार(आरटीआई कार्यकर्ता), फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश.*

जनता पस्त, सरकार मस्त

कवर स्टोरी-नरेंद्र मोदी का मंत्र, काम कम प्रचार ज्यादा (16 मई-22 मई 2016) पढ़ी. मोदी सरकार के दो साल पूरे होने पर यह एक अच्छा विश्लेषण है. मनीष कुमार ने कवर स्टोरी की हेडिंग में ही सब कुछ कह दिया है और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है. इस सरकार का ध्यान केवल प्रचार पर है. सरकार के दो साल पूरे हो गए, लेकिन सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया. महंगाई की बात करें, तो घटने की बजाए महंगाई बढ़ी ही है. दाल के दाम आसमान छू रहे हैं. रेल के किराए में कई बार बढ़ोत्तरी हो चुकी है, लेकिन सुविधाओं में कोई इजाफा नहीं हुआ. देश में विकराल सूखा पड़ रहा है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा है. विदेशों से कालेधन को लेकर आने की बात तो सरकार भूल ही गई है और नहीं लगता कि सरकार कालाधन वापस ले भी आएगी. इस सरकार में गरीब, किसान, मीडिल क्लास और यहां तक कि व्यापारी भी खुश नहीं है. अगर सरकार अभी भी नहीं चेती, तो आने वाले समय में लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देगा.

–रवि ओझा, *छपरा, बिहार.*

कैसे कैसे सांसद

जब तोप मुकाबिल हो-लगभग पचास सांसद बैंकों का हज़ारों करोड़ दबाए बैठे हैं (16 मई-22 मई 2016) के तहत संतोष भारतीय ने सही कहा है कि संसद के माननीय सदस्यों, आपकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन ये पचास सांसद बाकी सांसदों की विश्वसनीयता के ऊपर काला धब्बा हैं. इसलिए सांसदों को और संसद की एथिक्स कमेटी को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए. सरकार और संसद की एथिक्स कमेटी को उन सांसदों के नाम भी बताने चाहिए जो बैंकों का हजारों करोड़ दबाए बैठे हैं. विजय माल्या ही नहीं देश के कई ऐसे उद्योगपति हैं जिनके ऊपर बैंकों का हजारों करोड़ रुपये बकाया है. अगर अभी किसान या मध्यम वर्ग का व्यक्ति किसी वजह से किश्त नहीं दे पाता है, तो उसके ऊपर तुरंत बैंकों की तरफ से कार्रवाई की जाती है. सरकार को उन माननीयों के ऊपर भी जो बैंकों के हजारों करोड़ दबाए बैठे हैं कार्रवाई करनी चाहिए और उनके नाम सार्वजनिक करना चाहिए.

–रघुनाथ सिंह, *गोरखपुर, उत्तर प्रदेश.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

प्रचार नहीं, लोगों का सपना पूरा कीजिए

मोदी सरकार के दो साल पूरे हो गए. दो साल पूरे होने पर जश्न मनाना एक परंपरा भी है और केंद्र में पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार का उत्साह भी है. हम भी इस जश्न में शामिल होना चाहते हैं. शायद देश का हर व्यक्ति इस जश्न में शामिल होना चाहता है, लेकिन जश्न में शामिल होने की परिस्थितियां अनुकूल नहीं दिखाई दे रही हैं और यह स्थिति हमारे लिए दुखदायी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार सफल हो यह अतिआवश्यक है. इसलिए, क्योंकि पिछले पैंसठ सालों में जितनी सरकारें आईं उन्होंने स्वाभाविक गति से तो विकास किया, लेकिन उन्होंने देश की बहुसंख्यक जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं सुझाया. लोगों को रियायतें तो दीं पर लोगों की जिंदगी में, जीने की परिस्थितियों में बदलाव आए, ऐसा कुछ नहीं किया. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह डर तो था कि देश सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ मुड़ने लगेगा, पर यह खतरा भी उठाया जा सकता था अगर देश के लोगों की समस्याएं, उनके सपने, रोजी-रोजगार, थाली में रोटी, शिक्षा में सुधार या बीमारी से लड़ने के साधन सामने दिखाई दिए होते. यही आशा थी कि सरकार ऐसे ही वादे करके आई है और उन्हें पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगी.

अब इस आगे बढ़ने की दिशा में जिन लोगों से वादे किए गए थे वही लोग निर्णायक भी हैं अभी भी नरेंद्र मोदी से विश्वास हिला नहीं है और विश्वास न हिलने के पीछे अशक्त, लुंज-पुंज और कल्पनाहीन विपक्ष खड़ा है. पैंसठ साल बाद जब दुनिया में सूचना क्रांति हो रही है तब भी लोगों के पास जानकारियां आधी-अधूरी, पूरी या झूठी पहुंच रही हैं, उस समय भी सरकार समझ रही है कि वह प्रचार का सैलाब पैदा कर अब भी लोगों को बहला सकती है और दूसरी तरफ विपक्ष यह समझ रहा है कि हम जो भी करेंगे उससे सरकार के प्रति गुस्से से उपजे क्षोभ को अपना भविष्य मान जनता उन्हें समर्थन दे देगी. न सरकार समझ रही है और न विपक्ष समझ रहा है कि लोगों का विश्वास अब धीरे-धीरे लोकतांत्रिक पद्धति से डगमगाने लगा है. अब बहुतों को लगने लगा है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति समस्याओं को बढ़ाने, समस्याओं को शोषण के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की शासन पद्धति है. शायद यह बात न सत्ता पक्ष की समझ में आएगी न विपक्ष के समझ में आएगी. समझ में तब आएगी जब असंतोष का यह राक्षस सड़कों पर सैलाब के रूप में जलजला लाता दिखाई देगा. प्रचार ने और टेलीविजन ने कई सरकारों को खाया है. पहली सरकार नरसिम्हा राव की सरकार थी, जिस सरकार ने दूरदर्शन को विचार का सबसे बड़ा हथियार बनाया और वह हथियार नरसिम्हा राव के खिलाफ गया. उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ प्रचार दूरदर्शन, प्राइवेट चैनल और अगर याद आए तो याद कीजिए शाइनिंग इंडिया का वह चमत्कारी नारा जिसने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को ज़मीन पर चारों खाने चित्त गिरा दिया था. उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार प्रचार के मोह में इतना फंस गई कि उसे अपने किए हुए गलत काम याद ही नहीं आए, और अब मोदी सरकार जो जश्न में और प्रचार में बुरी तरह उलझी हुई है.

हम सिर्फ समझाने की विनम्र कोशिश कर रहे हैं. आप कितना भी प्रचार करें, कितनी भी आशाएं पैदा करें, कितने भी सपने दिखाएं, लेकिन अब देश के बहुसंख्यक वर्ग को अगर शिक्षा की नई आशा, बीमारी से लड़ने की सुविधा, बेरोज़गारी के राक्षस से परेशान नौजवान और सबसे बड़ा वर्ग जिसे हम वंचित कहते हैं, और किसान अगर उसे कोई आशा नहीं दिखाई देती है तो यह प्रचार बिल्कुल बेमानी और बेकार साबित होगा. इस देश में सूखे से लड़ने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है. पानी रोकने का कोई अभियान सरकार के पास नहीं है. किसानों की आत्महत्या रोकने का कोई भी समाधान सरकार के पास नहीं है. और सरकार नई योजनाओं की लंबी फेहरिस्त का, टेलीविजन और अखबारों के जरिए लोगों की खुशहाली का प्रचार करके अगर यह समझती है कि वह लोगों भरमा लेगी तो मुझे इसमें संदेह है.

हम फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि वह क्यों अपनी ही पार्टी के सांसदों से देश में कितना काम हुआ है इसकी जानकारी नहीं लेते? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के देश में फैले हुए करोड़ों कार्यकर्ताओं से इस बात की जानकारी नहीं लेते कि कहां कितना काम हुआ है? उनकी अपनी योजनाएं जिसमें सबसे महत्वाकांक्षी योजना विद्युत उत्पादन की थी. आंकड़ों में उनके मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं कि हमने तीन साल पहले ही सारा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, लेकिन गांवों में तो बिजली नहीं दिखाई देती. उत्पादन के लिए बिजली की उपलब्धता के साथ जो आधारभूत सुविधाएं बढ़नी चाहिए थी वह तो बढ़ती नहीं दिखाई देतीं. उल्टे आधारभूत सुविधाओं के शुरुआती बिंदु जिनमें सड़क, पानी, अस्पताल, बिजली, संचार यह सब छिन्न-भिन्न दिखाई दे रहे हैं. इनके सुधार की अगर कोई संभावना नहीं है, तो फिर हम किस बात का जश्न मनाएं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टाफ के लोग भी अगर किसी को फोन करते होंगे और बीच में एक दो बार कॉल ड्रॉप न हो तो यह चमत्कार उनके साथ तो हो सकता है, पर देश के करोड़ों लोगों के साथ यह चमत्कार नहीं हो रहा है. और संचार कंपनियां पुरानी भाषा में खरबों रुपये इस कॉल ड्रॉप के जंजाल को फैलाकर कमा रही हैं. इसके ऊपर न प्रधानमंत्री का ध्यान जाता है और न उनके संचार मंत्री का ध्यान जा रहा है. अंत में हम इतना ही कह सकते हैं. दो साल का जश्न मनाइए. आने वाले तीन सालों के भी जश्न की अभी से योजना बना लीजिए. पर कम से कम अपने ही संसाधनों से, अपनी ही पार्टी द्वारा लिए गए फीडबैक से अपनी आखों के सामने पड़े उस पर्दे को हटा दीजिए कि देश को जहां जाना चाहिए था, वहां जा भी रहा है या नहीं. स्वाभाविक विकास को अपनी उपलब्धि मत मानिए. अपनी उपलब्धि उसे मानिए जो स्वाभाविक विकास की गति को तेज़ करे, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए. और जब हम लोग कहते हैं तो देश के 70 प्रतिशत लोगों को उसमें शामिल करते हैं सिर्फ तीस प्रतिशत लोगों को शामिल नहीं करते हैं. हमारा धर्म है कि हम आपके सामने देश की वस्तु स्थिति लाएं. हमारी इस कोशिश को आप अपना विरोध न समझें, इतना आग्रह तो हम आपसे कर ही सकते हैं. ■

दो साल का जश्न मनाइए. आने वाले तीन सालों के भी जश्न की अभी से योजना बना लीजिए. पर कम से कम अपने ही संसाधनों से, अपनी ही पार्टी द्वारा लिए गए फीडबैक से अपनी आखों के सामने पड़े उस पर्दे को हटा दीजिए कि देश को जहां जाना चाहिए था, वहां जा भी रहा है या नहीं. स्वाभाविक विकास को अपनी उपलब्धि मत मानिए. अपनी उपलब्धि उसे मानिए जो स्वाभाविक विकास की गति को तेज़ करे, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए. और जब हम लोग कहते हैं तो देश के 70 प्रतिशत लोगों को उसमें शामिल करते हैं सिर्फ तीस प्रतिशत लोगों को शामिल नहीं करते हैं.

editor@chauthiduniya.com

असम में भाजपा की जीत

मोदी सरकार के लिए तोहफ़ा है

मेघनाद देसाई

यह राहुल (गांधी) की गलती नहीं थी. पिछले दिनों कांग्रेस को जिस पराजय का सामना करना पड़ा उसके लिए जलवायु परिवर्तन, परमाणु खतरा, कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी, अल-नीनो ज़िम्मेदार हो सकते हैं लेकिन राहुल गांधी नहीं. एक बार जब यह बात साफ हो गई तो हम भारतीय राजनीति के रहस्य को समझ सकते हैं.

चुनावी नतीजों के आने के कुछ हफ्ते पहले ही यह तय लगने लगा था कि भाजपा असम में सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरेगी. असम चुनाव के नतीजे भाजपा के देश की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी शेष रह जाने की दिशा में एक और कदम था. पार्टी का वोट प्रतिशत उन क्षेत्रों में भी बढ़ा है जहां उसकी हैसियत नवागंतुक की थी. असम में भाजपा ने चतुराई भरी रणनीति अपनाई और एक स्थानीय चेहरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया. और अपने सहयोगी दलों की चुनाव जीतने में मदद की. असम में वंशवादी परंपरा स्थापित करने की तरुण गोगोई की कोशिश नाकाम हो गई.

फिलहाल समस्या कांग्रेस और वाम मोर्चे की है. कांग्रेस के पास अब केवल एक बड़ा राज्य कर्नाटक बचा है, जबकि सीपीएम अभी-अभी केरल की सत्ता में आई है. केरल बहुत बड़ा नहीं तो छोटा राज्य भी नहीं है. तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके का खेल बिगाड़ने वाली पार्टी साबित हुई. अगर डीएमके अपने दम पर चुनाव लड़ी होती तो वह शायद जीत सकती थी. पश्चिम बंगाल में सीपीएम कैडर ने वाममोर्चे का कांग्रेस के साथ गठबंधन पसंद नहीं किया. सीपीएम के वोट तो कांग्रेस को मिल गए, लेकिन कांग्रेस के वोट सीपीएम के खाते में ट्रान्सफर नहीं हुए क्योंकि कांग्रेस के पास पश्चिम बंगाल में वाममोर्चे के खाते में ट्रान्सफर करने लायक वोट ही नहीं थे.

लिहाज़ा अब भविष्य में जब गठबंधन की बात आएगी तो कांग्रेस को विष की तरह देखा जाएगा. यह बात तो तय है कि 2019 में कांग्रेस किसी भी गठबंधन का नेतृत्व नहीं करेगी. ऐसा भी हो सकता है कि उसे किसी गठबंधन में शामिल ही न किया जाए, यहां तक कि तीसरे नंबर के खिलाड़ी के रूप में भी नहीं, जैसा कि बिहार में हुआ था. चूंकि कांग्रेस वंशवादी नेतृत्व से अपना दामन नहीं छुड़ाएगी, लिहाज़ा हम धैर्यपूर्वक उसका पतन तब तक देखते रहेंगे, जब तक कि वह पूरी तरह से समाप्त न हो जाए. जिस तरह किसी बॉलीवुड फिल्म में तीन का अंत सभी को मालूम होता है उसी तरह कांग्रेस का अंत भी सबको मालूम है. एक विजेता की छवि खोने से पहले ही प्रशांत किशोर पार्टी का साथ छोड़ देंगे.

कांग्रेस के पास अब केवल एक बड़ा राज्य कर्नाटक बचा है, जबकि सीपीएम अभी-अभी केरल की सत्ता में आई है. केरल बहुत बड़ा नहीं तो छोटा राज्य भी नहीं है. तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके का खेल बिगाड़ने वाली पार्टी साबित हुई. अगर डीएमके अपने दम पर चुनाव लड़ी होती तो वह शायद जीत सकती थी. पश्चिम बंगाल में सीपीएम कैडर ने वाममोर्चे का कांग्रेस के साथ गठबंधन पसंद नहीं किया. सीपीएम के वोट तो कांग्रेस को मिल गए, लेकिन कांग्रेस के वोट सीपीएम के खाते में ट्रान्सफर नहीं हुए क्योंकि कांग्रेस के पास पश्चिम बंगाल में वाममोर्चे के खाते में ट्रान्सफर करने लायक वोट ही नहीं थे.

बहरहाल सीपीएम की भी अपनी समस्याएं हैं. अंदरूनी कलह के बावजूद पार्टी ने केरल चुनाव जीत लिया, लेकिन पश्चिम बंगाल को हमेशा के लिए खो दिया. कांग्रेस से उसकी कभी नज़दीकी और कभी दूरी का खेल समझ से परे है. हरकिशन सिंह सुरजीत के कार्यकाल में यह कांग्रेस के संरक्षण में फली-फूली थी. लेकिन, परमाणु मुद्दे पर यूपीए-1 के साथ उसके झगड़े ने राष्ट्रीय स्तर पर सीपीएम को समाप्त कर दिया. हालिया चुनावों में उसने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से हाथ मिलाया (जिसका फायदा उसे नहीं मिला) और केरल में उससे कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा. अब ऐसा लगता है कि सीपीएम का एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह जाने का समय आ गया है. क्योंकि बंगाल में एक समाजवादी पार्टी की हैसियत से तृणमूल कांग्रेस को चुनौती देने और केरल में एक कम्युनिस्ट मोर्चे के रूप में अपना वजूद कायम रखने के बावजूद एक राष्ट्रीय पार्टी बनती नहीं दिख रही है.

जयललिता और ममता बनर्जी दोनों को स्वयं को क्षेत्रीय स्तर तक सीमित रखने का फायदा एक बार फिर मिल गया. एक मज़बूत क्षेत्रीय पार्टी बनकर आप अधिक कामयाब हो सकते हैं बजाय इसके कि राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना पालें. मायावती को इससे सबक सीखते हुए उत्तर प्रदेश से बाहर चुनाव लड़ने का ख्याल छोड़ देना चाहिए. इन नतीजों में आम आदमी पार्टी के लिए भी संदेश है. आम आदमी पार्टी का दिल्ली का आधार उसकी महत्वकांक्षाओं की तुलना में बहुत छोटा है. लेकिन वह बहुत तेज़ी से एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकती. एक क्षेत्रीय शक्ति बनने के क्रम में पंजाब में कांग्रेस को अपदस्थ करने का उसके पास मौक़ा है. उत्तर प्रदेश में पहले से ही बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के रूप में दो मज़बूत क्षेत्रीय दावेदार मौजूद हैं. लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा उत्तर प्रदेश का गणित बिगाड़कर किंगमेकर की भूमिका में आ सकती है.

दरअसल असम की जीत भाजपा के लिए केंद्र की सत्ता में आने की दूसरी वर्षगांठ का तोहफा है, जिसे उसने अपनी मेहनत से हासिल किया है.■

feedback@chauthiduniya.com

मगध 'घोटाला' विश्वविद्यालय

जांच होती है कार्रवाई नहीं

बिहार सरकार के निगरानी विभाग द्वारा 120 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता एवं 2011 से अब तक की गई पीएचडी की डिग्री की जांच की जा रही है. पीएचडी की डिग्री के मामले में पता चला है कि कई विदेशियों को बिना भारत आए ही पीएचडी की डिग्री प्रदान कर दी गई है. इस मामले को लेकर लोगों का कहना है कि यह जांच भी आने वाले समय में बिना परिणाम के ही समाप्त हो जाए, तो कई आश्चर्य नहीं होगा.

सुनील सौरभ

बिहार के सबसे बड़े मगध विश्वविद्यालय में पिछले तीन दशक से वित्तीय अनियमितता, फर्जी डिग्री घोटाले समेत अनेक तरह की गड़बड़ियों की जांच होती आ रही है. जांच कमेटियों के सदस्य जांच में सक्रियता भी दिखाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जांच कमेटी की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है या फिर जांच कमेटियां ही सुस्त हो जाती हैं. आखिर में नतीजा यह निकलता है कि मगध विश्वविद्यालय में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती. पुन: नए मामले आने पर इसी तरह की जांच शुरू होती है और कुछ दिनों के बाद फिर वही स्थिति आ जाती है और जांच बेमानी साबित होती है. जब तक जांच होती है, तब तक आरोपी सेवानिवृत्त हो जाते हैं या फिर अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद विश्वविद्यालय छोड़ देते हैं. बिहार सरकार के निगरानी विभाग द्वारा 120 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता एवं 2011 से अब तक की गई पीएचडी की डिग्री की जांच की जा रही है. पीएचडी की डिग्री के मामले में पता चला है कि कई विदेशियों को बिना भारत आए ही पीएचडी की डिग्री प्रदान कर दी गई है. इस मामले को लेकर लोगों का कहना कि यह जांच भी आने वाले समय में बिना परिणाम के ही समाप्त हो जाए, तो कई आश्चर्य नहीं होगा. इससे पूर्व में भी मगध विश्वविद्यालय में अनेक बड़े भ्रष्टाचार के मामले आए और उसकी जांच भी शुरू हुई, लेकिन उसका परिणाम शून्य रहा. पूर्व आईएएस अभिमन्यु सिंह जब मगध विश्वविद्यालय के कुलपति थे, तब बौद्ध अध्यन विभाग के प्रधान डॉ. वाईके मिश्र के द्वारा एक सौ पीएचडी कराए जाने की जांच के लिए राजभवन से कमेटी गठित की गई थी. उस समय यह मामला अखबारों की सुर्खियां बना था. लेकिन यह भी मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मार्च 1962 को हुई थी. तब से दो दशक तक मगध विश्वविद्यालय एक आदर्श गुरुकुल के रूप में पूरे देश में चर्चित था. इसके प्रथम कुलपति डॉ. केके दत्ता मगध विश्वविद्यालय को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में शामिल कराना चाहते थे और उनका प्रयास भी सफल रहा. तब मगध विश्वविद्यालय के विभागों के प्रधान इस विषय के देश के जाने-माने विद्वान हुआ करते थे. दो दशक तक मगध विश्वविद्यालय बिहार ही नहीं देश के अच्छे विश्वविद्यालयों में शामिल रहा. लेकिन कुछ समय बाद इस विश्वविद्यालय में अनेक तरह की गड़बड़ियों की शुरुआत होने लगी. मगध विश्वविद्यालय के स्थापना के समय ट्रेजरर का पद भी स्वीकृत था. इस पद पर शहर के जाने-माने अधिवक्ता रमाबल्लभ प्रसाद सिंह को पदस्थापित किया गया था. वह कड़क मिजाज और ईमानदार पदाधिकारी के रूप में जाने जाते थे. उनके कार्यकाल के दौरान कभी किसी तरह की वित्तीय अनियमितता नहीं हुई. वह मगध विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को कोई भी गलत काम नहीं करने देते थे. उसी समय 1974 में एक आईएएस को मगध विश्वविद्यालय का कुलपति बनाकर भेजा गया. कुलपति के गलत कामों पर टेजरर रमाबल्लभ प्रसाद सिंह रोक लगा देते थे. तब आईएएस कुलपति ने बिहार सरकार को लिखित पत्र देकर विश्वविद्यालय से टेजरर का पद ही समाप्त करा दिया. उसके बाद कुलपति को मनमानी करने की छूट मिल गई. उसके बाद मगध विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता के मामले भी बढ़ने लगे, जबकि इससे पूर्व 1969-70 में गणित के एक प्राध्यापक राम शरण प्रसाद ने परीक्षा के पूर्व ही प्रश्न पत्र आउट कर दिया.

शिखा गुप्ता फर्जी डिग्री घोटाला कांड मगध विश्वविद्यालय का चर्चित डिग्री घोटाला था. शिखा गुप्ता गया के तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक अनुराग गुप्ता की पत्नी थीं. मगध विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बिना परीक्षा दिए ही शिखा गुप्ता को डिग्री दे दी गई.

तब विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें अपने पद से हटा दिया, लेकिन आज स्थिति बदल गई है. 1975-76 में तत्कालीन कुलपति डॉ. नर्मदेश्वर प्रसाद की कुलपति निवास में रहस्यमय मौत के पीछे भी कई मामले थे. मगध विश्वविद्यालय के प्राध्यापक नलिन के शास्त्री के खिलाफ एक सत्र में टीए के पांच लाख रुपये निकाले जाने के मामले में जांच कमेटी बैठी थी. यही कारण था कि कमीशन से मगध विश्वविद्यालय के रजिस्टार के लिए अधिसूचना के बाद भी वे रजिस्टार नहीं बने सके थे. तत्कालीन परीक्षा नियत्रंक रामदेव यादव और उप परीक्षा नियंत्रक एसएस वल्खी पर भी फर्जी डिग्री घोटाले का आरोप लगा था. उसके बाद जांच कमेटी भी बनी, लेकिन यह नहीं पता चला कि जांच का क्या हुआ. मगध विश्वविद्यालय के भूगर्भशास्त्र विभाग के प्रधान डॉ. बीएन पांडेय जब सीसीडीसी थे, तब उन पर भी राशि गबन का आरोप लगा था. उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन सभी मामलों की तरह यह मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. डॉ. बलबीर सिंह भशीन जब मगध विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति थे, तब उन्होंने अपनी प्राध्यापक पत्नी का पूरा एरियर तमाम नियमों को ताख पर रखकर निकाल लिए थे. इस ममाले में भी जांच बैठी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ. शिखा गुप्ता फर्जी डिग्री घोटाला कांड मगध विश्वविद्यालय का चर्चित डिग्री घोटाला था. शिखा गुप्ता गया के तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक अनुराग गुप्ता की पत्नी थीं. मगध विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बिना परीक्षा दिए ही शिखा गुप्ता को डिग्री दे दी गई. तब यह मामला पूरे देश में चर्चित हुआ था. लेकिन मगध विश्वविद्यालय ने इस मामले की भी लीप-पोती कर छोड़ दिया और आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. उसी प्रकार 2006 में डॉ. बीएन पांडेय मगध विश्वविद्यालय के कुलपति बने. दशकों से मगध विश्वविद्यालय में बिगड़ी व्यवस्था को रास्ते पर लाने का श्रेय उन्हें जाता है. लेकिन कार्यकाल पूरा करते ही बीएन पांडेय पर भी वित्तीय अनियमितता के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई. लेकिन सभी की तरह उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.

मगध विश्वविद्यालय में किसी तरह की गड़बड़ी की जांच तो शुरू होती है, लेकिन जांच को अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है. मगध विश्वविद्यालय में गड़बड़ी होने का मूल कारण यह है कि कुलपति या प्रति कुलपति के पद पर आने वाले लोग तीन साल के बाद चले जाते हैं, लेकिन गड़बड़ी करने वाले पदाधिकारी और कर्मचारी विश्वविद्यालय के ही होते हैं. यही कारण है कि हर नए आने वाले कुलपति को कई गुटों में बंटे मगध विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचारियों का समूह अपने हिसाब से सलाह देकर गुमराह करने का प्रयास करता है. यही वजह है कि मगध विश्वविद्यालय में वित्तीय गड़बड़ी और फर्जी डिग्री के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जांच होने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकलता है.■

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग

संगठन में व्यापक फेरबदल करने की तैयारी

सुनील सौरभ

बिहार की राजनीति में मगध का हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहा है. यही वजह है कि आजादी के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव से ही सभी राजनीतिक दलों की नजर मगध पर रही है. मगध के 26 विधानसभा क्षेत्रों पर जिस भी पार्टी या गठबंधन की स्थिति मजबूत रही और वह बिहार के सत्ता शीर्ष पर काबिज रहा. अगर हम कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो बिहार में जब भी कांग्रेस की पकड़ ढिली हुई, उस समय समाजवादियों की पकड़ मगध पर मजबूत हुई और उनके गठबंधन की सरकार बनी. लेकिन यह अलग बात है कि ऐसी सरकार पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी. 1990 के बाद बिहार का पूरा रजानीतिक समीकरण उलट-पलट हो गया. लंबे समय तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया. कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई कि उसको राजद जैसी क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन कर अपना अस्तित्व बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा. लेकिन 2005 में पुन: बिहार का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया. भाजपा-जदयू के गठबंधन को बहुमत मिला और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने. एनडीए को तब जीत मिली, जब उसकी पकड़ मगध पर मजबूत हो गई. मगध के 26 में से 22 विधानसभा क्षेत्रों पर एनडीए की जीत हुई. बदलते राजनीतिक समीकरण में लंबे समय तक लालू का विरोध कर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे नीतीश ने 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू यादव से हाथ मिला लिया. नतीजा यह हुआ कि सामाजिक न्याय, अतिपिछड़ा और महादलित की बात कर महागठबंधन ने सरकार बना ली और इसका सबसे बड़ा खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा. प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के तमाम प्रयासों के बाद भी भाजपा को विधानसभा चुनाव में जनता का समर्थन नहीं मिल पाया. वहीं दूसरी ओर महागठबंधन को व्यापक जनसमर्थन मिला और नीतीश के नेतृत्व में उनकी सरकार बनी. इसमें मगध का सबसे बड़ा योगदान रहा. अधिकतर सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीते. केवल चार सीटों पर भाजपा गठबंधन को सफलता मिल पाई. इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मगध में अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी में है. इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व की योजना है कि बिहार में जिस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हुए हैं, उसमें सेंध लगाई जाए. इसी फॉर्मूले पर मगध में भाजपा के संगठन में व्यापक फेरबदल करने की योजना बनाई जा रही है. फिलहाल मगध के पांच जिलों में से चार जिलों में भूमिहार जाति के जिला अध्यक्ष हैं और बचे एक औरंगाबाद जिले में राजपूत जाति का जिला अध्यक्ष है. लंबे समय से मगध के इन पांचों जिलों के भाजपा के अध्यक्ष इन्हीं दो जातियों के रहे हैं. भाजपा का मानना है कि भूमिहार जाति के लोग बिहार में मतदान के समय तन-मन-धन के साथ पार्टी की मदद करते हैं. लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरण के इस दौर में सत्ता के लिए सभी वर्ग और जाति का वोट प्राप्त करना जरूरी है. इसलिए पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित और महादलित समुदाय को भाजपा की ओर आकर्षित किया जाए, क्योंकि मगध में पिछड़ी, अतिपिछड़ी, दलित और महादलित जाति की संख्या अधिक है. इसे देखते हुए जिला अध्यक्ष के पद पर पिछड़ी और अतिपिछड़ी जातियों से आने वाले तेजतर्रार और युवा नेतृत्व को संगठन की बागडोर सौंपी जा सकती है. लगातार ऊंची जाति के सभी जिलों में जिलाध्यक्ष होने की वजह से पिछड़ी, अतिपिछड़ी जातियों और दलित जातियों का भाजपा को व्यापक जन समर्थन नहीं मिला.

कृष्णा कुमार सिंह

प्रेम कुमार

नागमणि

इसलिए भाजपा मगध में इस बार संगठन को मजबूत करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग पर जोर दे रही है. गया शहर के विधायक प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाना भी मगध की अतिपिछड़ी जातियों पर मजबूत पकड़ बनाना है. पिछले ढाई दशक से गया भाजपा में प्रेम कुमार और विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह का चलता रहा है. प्रेम कुमार गया महानगर संगठन में पहले से ही अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाह रहे हैं, जबकि कृष्ण कुमार अपने चहेतों को ही गया जिला अध्यक्ष के पद पर बैठाते आ रहे हैं. लेकिन इस बार यह मिथक तोड़ा जा सकता है. प्रेम कुमार के चहेते और अतिपिछड़े वर्ग से आने वाले किसी युवा को गया का जिला अध्यक्ष बनाया जा सकता है और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा. इसमें तेजतर्रार युवा नेता आरएस नागमणी का नाम भी शामिल है.

मगध के अन्य जिलों औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और नवादा का भी यही हाल है. इतना निश्चित है कि इस बार संगठन चुनाव में प्रेम की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. ऐसे भी मगध में महादलित के बाद सबसे अधिक जनसंख्या पिछड़ी और अतिपिछड़ी जातियों की है. अब देखना है कि भाजाप को मगध में सोशल इंजीनियरिंग का आने वाले चुनावों में कितना फायदा मिलता है. स्थिति को भांपते हुए पिछड़ी और अतिपिछड़ी जातियों से आने वाले कई नेता जिला अध्यक्ष बनने के लिए सक्रिय हो गए हैं. भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की चाहत है कि सामाजिक समरसता और सोशल इंजीनियरिंग के सहारे पूरे बिहार में पिछड़ी, अतिपिछड़ी जातियों के साथ-साथ दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में कर सके. इन्हीं वजहों से भाजपा मगध पर पैनी दृष्टि रखे हुए हैं और भविष्य के लिए संगठन को मजबूत करने में लगी है.■

feedback@chauthiduniya.com

Mob. : 9386745004, 9204791696 www.iiher.org, Email : anilsulabh6@gmail.com

INDIAN INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION & RESEARCH

Health Institute Rd, Beur (Near Central Jail), Patna -2.

(Recognised by Govt. of Bihar, RCI, Govt. of India, IAP & ISPO)

AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

POST GRADUATE COURSES :

Name of Courses		Eligibility	Duration
MPT	Master of Physiotherapy	BPT	2yrs.
MOT	Master of Occupational Therapy	BOT	2yrs.
DEGREE COURSES			
BPT	Bachelor of Physiotherapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BOT	Bachelor of Occupational Therapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BPO	Bachelor of Prosthetic & Orthotic	I.Sc	4yrs.+6 Months of Internship
BASLP	Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology	I.Sc	3yrs.+1 year of Internship
BMLT	Bachelor of Medical Laboratory Technology	I.Sc	3yr.+6 Months of Internship
BMRIT	Bachelor of Radio Imaging Technology	I.Sc	3yrs.+6 Months of Internship
B.Ophth.	Bachelor of Ophthalmology	I.Sc	4yr.+6 Months of Internship
B.Ed.	(Special Education)	Graduate	1yr.
1 YEAR ABRIDGED DEGREE FOR DPT / DOT			
DIPLOMA COURSES :			
DPT	Diploma In Physiotherapy	I.Sc (Bio)	3yrs.+6 Month of Internship
D-X-Ray	Diploma In X-Ray Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DMLT	Diploma In Medical Laboratory Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DECG	Diploma In E.C.G.	I.Sc (Bio)	2yr.
DOTA	Diploma In O.T. Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DHM	Diploma In Hospital Management	Graduate	1yr.
CMD	Certificate In Medical Derssing	Matirc with Science & English	1yr.

ADMISSION OPEN

Form & Prospectus -
Can be obtained from the office against a payment of Rs. 500/-. only by cash. Send a DD of Rs. 550/- only in the favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna, for postal delivery.

डॉ. अनिल सुलभ
निदेशक प्रमुख

बिहार में विधान परिषद और राज्यसभा के लिए चुनाव

मछली पानी में, बंटवारा अभी से

चुनावी गणित कहता है कि विधान परिषद की एक सीट के लिए 31 सदस्यों के वोट की जरूरत होगी. इस हिसाब से पांच सीट तो बिना लागलपेट के महागठबंधन को मिल जाएगी. इसके बाद महागठबंधन के पास 23 सरप्लस वोट बचेगा. सदन में भाजपा और उसके सहयोगियों की कुल संख्या 58 है. इस आधार पर भाजपा एक सीट सीधे हासिल कर लेगी. इसके बाद उसके पास 27 सरप्लस वोट बचेगा. इसी सरप्लस वोटों के आधार पर सातवीं सीट के लिए दावेदारी होगी.

मीसा भारती

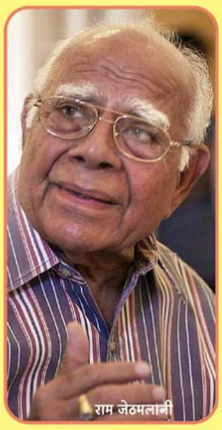
राम जेठमलानी

शरद यादव

सुधीर शर्मा

सुशील मोदी

सरोज सिंह

बिहार में विधान परिषद की सात और राज्यसभा की पांच सीटों के लिए 10 और 11 जून को होने वाला चुनाव नीतीश कुमार के लिए भाजपा से हिसाब चुकता करने का सुनहरा मौका साबित हो सकता है. सभी जानते हैं कि 2014 के राज्यसभा के चुनाव में भाजपा ने जदयू के बागी विधायकों की ओर से खड़े किए गए उम्मीदवार अनिल शर्मा को समर्थन देकर नीतीश कुमार के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी. चूंकि इस चुनाव में वोट दिखाकर देने की बाध्यता नहीं है इसलिए क्रॉस वोटिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. अब यह चुनाव मैनजमेंट करने वाले महारथियों पर निर्भर करता है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि परिषद की सातवीं सीट के लिए घमासान के आसार अभी से बनने लगे हैं. गौरतलब है कि विधानसभा में महागठबंधन की सदस्य संख्या 178 है. दलगत स्थिति इस प्रकार है– राजद 80, जदयू 71 , भाजपा 53, कांग्रेस 27, भाकपा माले 3, लोजपा 2, हम एक, रालोसपा 2 और निर्दलीय चार. राज्यसभा में बिहार की 16 सीटों में से अभी 12 जदयू के पास और भाजपा के पास चार है. चुनावी गणित कहता है कि विधान परिषद की एक सीट के लिए 31 सदस्यों के वोट की जरूरत होगी. इस हिसाब से पांच सीट तो बिना लागलपेट के महागठबंधन को मिल जाएगी. इसके बाद महागठबंधन के पास 23 सरप्लस वोट बचेगा. सदन में भाजपा और उसके सहयोगियों की कुल संख्या 58 है. इस आधार पर भाजपा एक सीट सीधे हासिल कर लेगी. इसके बाद उसके पास 27 सरप्लस वोट बचेगा. इसी सरप्लस वोटों के आधार पर सातवीं सीट के लिए दावेदारी होगी. इस काम में चार निर्दलीय सदस्यों के वोट अहम हो जाएंगे.

राज्यसभा की पांच सीटों के लिए खास उलझन नहीं है. एक सीट के लिए 41 वोट चाहिए. 178 की ताकत के बूते महागठबंधन चार सीटें आसानी से ले लेगा. पाचवीं सीट पर भाजपा आसानी से अपने उम्मीदवार को जीता ले जाएगी. लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार इतनी आसानी से विधान परिषद की सातवीं सीट पर भाजपा का कब्जा नहीं होने देंगे. भाजपा का दावा है कि उसकी अपनी संख्या 53 की है, पांच उसके सहयोगी हैं और चार निर्दलीय हैं. मतलब 62 की ताकत एनडीए के साथ है. यानी 31 के हिसाब से दो सीटों की जीत में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी. लालू और नीतीश भाजपा के इसी गणित को बिगाड़ने में दिमाग लगा रहे हैं. जानकार सूत्र बताते हैं कि सातवीं सीट के लिए महागठबंधन की ओर से कांग्रेस को उम्मीदवार खड़ा करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है. कांग्रेस के मना करने पर किसी धनकुबेर निर्दलीय प्रत्याशी को आगे किया जा सकता है. रणनीति यह है कि सातवीं सीट पर एनडीए को जबरदस्त झटका दिया जाए. चार निर्दलीय विधायकों पर डोरे डाले जाने का काम शुरू है. निर्दलीय विधायक रिंकू सिंह से नीतीश कुमार से मिल भी आए हैं. रिंकू सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें समर्थन क्यों नहीं देंगे. इसी तरह अन्य निर्दलीय विधायकों के साथ ही साथ लोजपा और रालोसपा के विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए ऑपरेशन जारी है. नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को सरकार में होने का पूरा फायदा मिल रहा है. विधायकों से कहा जा रहा है कि आप साथ दीजिए सरकार आपके साथ है. रिंकू सिंह की मुख्यमंत्री से मुलाकात इसी की एक कड़ी थी. कहा तो यह भी जा रहा है कि कुछ भाजपा विधायकों पर भी डोरे डाले जा रहे हैं और उनसे क्रॉस वोटिंग के लिए कहा जा रहा है. बदले में आश्वासनों की झड़ी लगी हुई है. आश्वासनों पर भरोसा करने का कारण भी है क्योंकि सरकार लालू और नीतीश की है. पहले यह माना जा रहा था कि निर्दलीय विधायकों में फूट नहीं पड़ेगी और चारों के चारों भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे. लेकिन रिंकू सिंह वाले प्रकरण ने भाजपा को चौकन्ना कर दिया है. रिंकू सिंह को वापस अपने खेमे में लाने के लिए भाजपा ने प्रयास शुरू कर दिए हैं. लेकिन भाजपा के लिए असली चिंता का विषय रालोसपा और लोजपा के विधायक हैं. इसको एकजुट रखना एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है. हालांकि इन दोनों दलों के चारों विधायक अभी से छाती ठोक कर कह रहे हैं कि पाला बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन लालू और नीतीश की तिकड़मी चाल क्या गुल खिलाएगी यह कहना मुश्किल है. लालू प्रसाद खुलेआम कह रहे हैं कि पासवान को अपने परिवार और पार्टी की चिंता है, इसलिए वह बार-बार कह रहे हैं कि यह सरकार ढाई साल में गिर जाएगी. सभी जान लें कि यह सरकार गिरने वाली नहीं है. बेहतर होगा पासवान अपनी पार्टी और परिवार को संभालें. मतलब साफ है कि लालू प्रसाद ने इशारों ही इशारों में रामविलास पासवान को आने वाले संकट की तरफ इशारा कर दिया है. जहां तक राज्यसभा और विधान परिषद के लिए संभावित उम्मीदवारों की बात है तो इसके लिए हरेक दल में लंबी लाइन लगी हुई है. बात जदयू से शुरू करें तो इस पार्टी के खाते में राज्यसभा की दो और विधान परिषद की दो सीटें आने वाली हैं. राज्यसभा के लिए इस पार्टी से शरद यादव, आरसीपी सिंह और केसी त्यागी का नाम सबसे आगे है. संभावना है कि इन तीनों में से ही दो लोगों को राज्यसभा का टिकट मिलेगा. जदयू से विधान परिषद के लिए सीपी सिन्हा और गुलाम रसूल बलियावी का नाम तय किया गया है. बात राजद की करें तो राबड़ी देवी और मीसा भारती में से एक का राज्यसभा जाना तय है. ज्यादा संभावना है कि मीसा भारती को दिल्ली का टिकट मिल सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति के महेजनर राबड़ी देवी की उपयोगिता यहां ज्यादा महसूस की जा रही है. बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद के दोनों बेटे भी चाहते हैं कि सदन में उनका मागदर्शन मिलता रहे. राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए राजद से प्रख्यात वकील रामजेठमलानी की नाम की चर्चा है. विधान परिषद की सीट के लिए भोला राय, निरंजन कुमार पप्पू, रामचंद्र पूर्वे और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना सहाब का नाम चर्चा में है. शहाबुद्दीन के सीवान जेल से भागलपुर जेल भेजने की घटना से उनके समर्थकों में नाराजगी है. लालू प्रसाद चाहते हैं कि हिना सहाब को परिषद में भेजकर उनकी नाराजगी दूर की जाए.

लालू प्रसाद खुलेआम कह रहे हैं कि पासवान को अपने परिवार और पार्टी की चिंता है, इसलिए वह बार-बार कह रहे हैं कि यह सरकार ढाई साल में गिर जाएगी. सभी जान लें कि यह सरकार गिरने वाली नहीं है. बेहतर होगा कि पासवान अपनी पार्टी और परिवार को संभालें. मतलब साफ है कि लालू प्रसाद ने इशारों ही इशारों में रामविलास पासवान को आने वाले संकट की तरफ इशारा कर दिया है. जहां तक राज्यसभा और विधान परिषद के लिए संभावित उम्मीदवारों की बात है तो इसके लिए हरेक दल में लंबी लाइन लगी हुई है.

परिषद की एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जिसके लिए हरकू झा सबसे प्रबल दावेदार हैं. एक नाम प्रेमचंद्र मिश्रा का भी आ रहा है. लेकिन कांग्रेस चाहती है कि उसे एक सीट राज्यसभा की दी जाए और इसके लिए सीपी जोशी और शकील अहमद का नाम चर्चा में है. भाजपा से राज्यसभा के लिए सुशील कुमार मोदी का नाम सबसे आगे है. बताया जा रहा है कि श्री मोदी को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. परिषद के लिए भाजपा में दावेदारों की पूरी फौज है लेकिन सबसे प्रबल दावेदारों में सुधीर शर्मा और सुखदा पांडे का नाम शामिल है. भाजपा सातवीं सीट के लिए भी अपना पूरा जोर लगाएगी और इसके लिए अतिपिछड़ा समाज से किसी को मौका दिया जा सकता है. हालांकि भाजपा के सहयोगी दल लोजपा का कहना है कि विधानसभा चुनाव के समय ही यह तय हुआ था कि परिषद की एक सीट लोजपा को दी जाएगी. लेकिन बदले हालात में लगता नहीं कि सहयोगी दलों के खाते में कोई सीट आएगी. फिलहाल सहयोगी दल अपने विधायक ही बचा लें तो बड़ी बात होगी.■

feedback@chauthiduniya.com

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : डॉ., साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। दीनानाथ सिंह, राँची

उत्तर : आप REPL निर्मित ऑर्थोविट कैप्सूल एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोते समय लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालीश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 21 वर्ष है, काम क्रीड़ा में जबरदस्त उल्लास उठता है। मगर स्पर्श मात्र से ही स्खलित हो जाता हूँ। अंग भी छोटी है-मैं क्या करूं? प्रभात, औरंगाबाद

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें और विगोरा ऑयल से मालिश करें, निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 32 वर्ष है कुछ दिनों से शीघ्रपतन से परेशान हूँ और एक बार सम्बन्ध स्थापित करने के बाद दोबारा मन नहीं करता और आलस्य बना रहता है। अरूण सिन्हा, नोयडा

उत्तर : आप REPL निर्मित विगोरा 5000 दिन में 3 बार) कप पानी में लें और विगोरा ऑयल से अंग पर मालिस करें। आपकी परेशानी दूर हो जायेगी।

प्रश्न : मैं 42 वर्षीय दो बच्चों का पिता हूँ मेरी समस्या यह है कि मुझे पत्नी से सहवास की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो मुश्किल से 15 सेकेन्ड के लिए । मैं क्या करूं? शंकर तिवारी, गुरगांव

उत्तर : बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है। तनाव, भागदौड़ एवं किशोरावस्था की गलती बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें। निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : उम्र 64 वर्ष है। संभोग की तिव्र इच्छा होती है मगर शिश्न में कोई हरकत नहीं होती है। इसलिए मन मारकर रह जाता हूँ। सुनील मेहरा वर्धमान

उत्तर : इस उम्र में ऐसा होता है। आप विगोरा 5 X का 5 शीशी का कोर्स करें और साण्डह ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें।

प्रश्न : डॉ., साहब मैने टी.वी. पर विज्ञापन देखकर वासनोउत्पति के लिए एक हलवा तरह की दवा मंगवाया उस दवा से फायदा तो कुछ नहीं हुआ उलटा पूरी रात सिर दर्द से छटपटाता रहा। कोई आर्युवेदिक और हानिरहित दवा बताएं। ईश्वरी राय, गाजियाबाद

उत्तर : ईश्वरी जी, कुछ दवा निर्माता बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और अपने दवा में सिर्फ सिल्डेनाफी मिलाकर बेचते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे सुझाव से आप REPL निर्मित सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आर्युवेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफैक्ट नहीं है।

प्रश्न : मैं 24 वर्षीया एक अविवाहित युवती हूँ मेरे स्तनों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जिससे मैं काफी परेशान रहती हूं, आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करायेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा।

उत्तर : स्तनों का का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से स्तन में उभार आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आयेंगी।

प्रश्न : मैं 36 वर्षीय विवाहित स्त्री हूँ पिछले एक वर्ष से पानी गिरने की समस्या है और मेरी जननांग भी काफी ढीली हो गई है। कोई हानिरहित उपचार बतायें। आभा दिल्ली।

उत्तर : आभा जी आप विगोरा 1000 दिन में 2 बार 15-15 बूँद आधा कप पानी मिलाकर पियें और Virgin Oil का अंरूनी हिस्से पर लगाएं। यह बिल्कूल ही हानिरहित दवा है।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है एवं सहवास की भी इच्छा नहीं होती है। कोई आयुर्वेदिक दवा बतायें। शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें :
REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला
फेडरल, पटना - 801505

Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)
E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com

डिस्ट्रीब्यूटर: दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुर: आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141-2315071, उत्तर प्रदेश-कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512-2372347, 9415127822, मुगलसराय: प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश-जबलपुर : मनीष फार्मा 0761-4004863, 9425157379, छत्तीसगढ़-भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788-403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहार: मॉर्डन डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम- मोरिक होमियो रेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेडर्स 9903175579, देव मार्कटिंग 033-30221018, सिलिगुड़ी : कलकत्ता होमियो 9593313011, झारखंड: सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा-भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक -विजापुर 9341610592 गुलबर्ग:9343834519

खच्छ भोजन और खच्छ जल से दूर होगी बीमारियाँ
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
डॉ. अशोक कुमार सिन्हा
MBBS, Ex Civil Surgeon Khizarsarai, Gaya
डॉ अशोक कुमार सिन्हा जो कि भूतपूर्व सिविल सर्जन हैं और गया, खिजरसराय में निजि क्लिनिक चला रहे हैं से बातचीत के क्रम में देश में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि धूप में पूरी बांह के सूती कपड़े पहन कर निकलें साथ ही भरपेट पानी पीकर निकलें। पानी की एक बोतल भी साथ रखें। चूकि गर्मी में शरीर से पसीना ज्यादा निकलता है और डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। इन दिनों पेट की समस्या ज्यादा रहती है। इसलिए आपको चाहिए कि बाहर का जंक फूड न खायें। बाजार का खाना बीमारियों का घर है। स्वच्छ भोजन और स्वच्छ जल आपको गर्मी में कई बीमारियों से बचाती है। उन्होंने बताया कि इन दिनों उनके पास टायफायड और जॉन्डिस के ज्यादा मरीज आ रहे हैं।
URSLIV Tab. Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX Cap Syp. Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL -D Cap Omeprazole 20 mg & Domperidone 10 mg
डॉ. सिन्हा के अनुसार जॉन्डिस एक वायरल इन्फेक्शन डिजिज है इसे हेपटाइटिस 'ए' भी कहते हैं। जॉन्डिस के लक्षणों में बुखार आना, आँख का पीला होना, उल्टी महसूस होना, भूख नहीं लगना जैसे लक्षण हैं। चूकि यह वायरल इन्फेक्शन डिजिज है इसलिए गंदा पानी और बाजार के भोजन से बचें। घर में भी भोजन साफ और शुद्धता के साथ बनना चाहिए। यदि आपको जॉन्डिस के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सक से सम्पर्क करें और ऐसे मरीजों को पूरा आराम दें। इन्हें आराम की जरूरत होती है साथ ही इन्हें ग्लूकोज का सेवन कराते रहें।
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd. A Division of Ariskon Pharma
-भारती

सूखाग्रस्त बुंदेलखंड के अभावग्रस्त लोगों ने कहा, नहीं मिल रही कोई राहत

भूख पर भारी भ्रष्टाचार

सूफी यायावर

राहत पैकेजों से अकालग्रस्त बुंदेलखंड को कोई राहत नहीं मिल रही है. राहत पैकेजों में भारी घोटाले की खबरें सामने आ रही हैं. किसानों के राहत के लिए आए पैकेज से नेता, अफसर, ठेकेदार और दलाल मालामाल हो रहे हैं. बुंदेली समाज के एक सर्वेक्षण में इसका सनसनीखेज खुलासा हुआ है. बुंदेली समाज के संयोजक और रोटी-बैंक के प्रणेता तारा पाटकर ने उस सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि 91 प्रतिशत लोगों ने माना है, उन्हें कोई राहत नहीं मिली है. 98.1 प्रतिशत लोगों ने कहा है कि राहत पैकेज किसानों का क्षेत्र से हो रहा पलायन रोक नहीं पाया. सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि बुंदेलखंड के 70 प्रतिशत गांव खाली हो चुके हैं.

तारा पाटकर ने सर्वेक्षण का हवाला देते हुए बताया कि 98.6 फीसदी लोगों ने बताया है कि तालाबों और कुओं व अन्य परम्परागत जलस्रोतों को बचाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए सरकारों ने कोई सार्थक प्रयास नहीं किए. अब कागजों में भी मात्र चार हजार तालाब ही बचे दिख रहे हैं. सर्वे में शत प्रतिशत लोगों ने माना कि 50 लाख से अधिक पशुधन मौत के मुहाने पर है. पशुओं के लिए सरकार की तरफ से भूसा चारा और पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है. इस वजह से रोजाना हजारों पालतू पशु मर रहे हैं. 94.9 प्रतिशत लोगों ने कहा है कि बुंदेलखंड के हृदयस्थल महोबा आ रहे पानी एक्सप्रेस को झांसी से लौटा देना अखिलेश सरकार का सबसे गलत फैसला था, जिसने राहत पैकेज वितरण के राजनीतिक लाभ को धो डाला.

सर्वेक्षण में एक हजार लोगों से बातचीत की गई, लेकिन एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जिसने बिजली व्यवस्था से अपनी परेशानी का जिक्र न किया हो. जनता बिजली कटौती, मनमाने लोड व बिलों से बुरी तरह त्रस्त है. 85 फीसदी लोगों ने कहा कि अखिलेश सरकार का राहत पैकेज वास्तविक जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा है. सपा के लोग अपने लोगों और नाते रिश्तेदारों के बीच राहत पैकेज बंटवा रहे हैं. 90.9 प्रतिशत लोगों ने कहा है कि बुंदेलखंड संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि भारी भ्रष्टाचार से जूझ रहा है. बुंदेलखंड के लोग राहत पैकेज के नाम पर अब तक आए धन का पूरा ब्यौरा मांग रहे हैं. राहत पैकेज में भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच कराने की मांग की जाने लगी है. मांग हो रही है कि राहत पैकेज के तहत बुंदेलखंड आ रहे धन की निगरानी रखने के लिए जिला और तहसील स्तर पर वकीलों, पत्रकारों और सम्मानित नागरिकों की निगरानी समिति बनाई जाए. 92.5 प्रतिशत लोगों ने माना कि अकाल झेल रहे लोग अब उसकी राहत के नाम पर भ्रष्टाचार झेल रहे हैं. तारा पाटकर ने कहा कि एक से 15 मई के बीच मध्य बुंदेलखंड के सभी सात जिलों महोबा, हमीरपुर, बांदा, झांसी, ललितपुर, उरई-जालौन व चित्रकूट में सर्वेक्षण किया गया था. इसके अलावा एक हजार लोगों से फोन पर बातचीत की गई.

पाटकर कहते हैं कि जो राहत सामग्री बांटी भी गई वह अत्यंत घटिया थी. दाल में घुन लगा मिला. आलू सड़ा हुआ था. मिल्क पाउडर और आटा की क्वालिटी अत्यंत घटिया थी. शिकायत पर प्रशासन ने जांच का आदेश भी दिया है. बुंदेलखंड में बांटे जा रहे राहत पैकेट में आटा, तेल, घी, मिल्क पाउडर, चने की दाल और आलू दिए जा रहे हैं. बांदा के आवास विकास कॉलोनी में इसकी पैकिंग हो रही है. बताया जा रहा है कि मजदूर जूते पहन कर दाल के ढेर पर चढ़ते हैं और उसी दाल को पैक कर देते हैं. राहत पैकेट में भी कमीशनबाजी हो रही है. कमीशन के चक्कर में घटिया सामग्री पैक की जा रही है. पैकेट को सड़क किनारे गंदगी के बीच रखा जाता है. यह सामग्री जौनपुर के एक सप्लायर से सप्लाई की जाती है. इसमें आटा, सरसों तेल, देसी घी, मिल्क पाउडर और चने की दाल घुन लगी हुई है. आलू ऐसा है कि जिसे पशु भी न खाए. पानी के लिए अलग मारामारी हो रही है. झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, जालौन, ललितपुर और चित्रकूट में पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है. हैंडपंप पहले से खराब पड़े हैं और कुओं में पानी तलहटी में चला गया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुंदेलखंड को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार को 1,304 करोड़ रुपये दिए और एक हफ्ते में किसान के खाते में धनराशि भेजने को कहा था, मगर किसानों के खातों में एक रुपया भी जमा नहीं हुआ. हमीरपुर समेत कई जिलों में किसानों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं और किसानों का पलायन लगातार जारी है. बुंदेलखंड में 40 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है. इनमें से कई आत्महत्याएं हैं.

बुंदेलखंड से किसानों और कामगारों का परिवार सहित पलायन लगातार जारी है...

पलायन का आंकड़ा भयावह

सूखा और अकालग्रस्त बुंदेलखंड से लोगों के पलायन का आंकड़ा भयावह है. बुंदेलखंड के बांदा से सात लाख 37 हजार 920, चित्रकूट से तीन लाख 44 हजार 801, महोबा से दो लाख 97 हजार 547, हमीरपुर से चार लाख 17 हजार 489, उरई (जालौन) से पांच लाख 38 हजार 147, झांसी से पांच लाख 58 हजार 377 और ललितपुर से तीन लाख 81 हजार 316 लोगों का पलायन हुआ. बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश से जुड़े जिलों में टीकमगढ़ से पांच लाख 89 हजार 371, छतरपुर से सात लाख 66 हजार 809, सागर से आठ लाख 49 हजार 148, दतिया से दो लाख 901, पन्ना से दो लाख 56 हजार 270 और दतिया से दो लाख 70 हजार 477 किसान और कामगार आर्थिक तंगी और भुखमरी की वजह से अन्यत्र शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं.

जरूरतमंदों के पेट भर रहा है रोटी-बैंक

पूर्व पत्रकार तारा पाटकर द्वारा शुरू किए गए रोटी-बैंक अभियान से इलाके के लोगों को काफी राहत है. रोटी-बैंक के जरिए मुफलिसी के शिकार लोगों के साथ-साथ उन किसान परिवारों को भी भोजन मुहैया कराया जा रहा है जो सूखे से त्रस्त होकर लाचार हैं. महोबा से शुरू हुई रोटी-बैंक मुहिम पूरे बुंदेलखंड और प्रदेशभर में फैल गई है. अब रोटी-बैंक' जरूरतमंद लोगों के घर-घर जाकर उन्हें घर की

रोटी-बैंक के प्रणेता तारा पाटकर (बीच में) टीम के साथियों के साथ

बनी रोटी और सब्जी मुहैया करा रहा है. रोटी-बैंक अभियान से जुड़े लोग घर-घर जाकर लोगों से दो रोटी दान करने को कहते हैं, ताकि जरूरतमंद और भूखे लोगों को खिलाया जा सके. यह अभियान अब एक आंदोलन में बदल चुका है. इस मुहिम के जरिए हर रोज कम से कम एक हजार जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जा रहा है. अभियान के प्रणेता तारा पाटकर बताते हैं कि इस मुहिम की शुरुआत भिखारियों और रेलवे स्टेशन पर दिखने वाले गरीबों को खाना खिलाने के इरादे से हुई थी. लेकिन अब महोबा के अधिकतर हिस्सों में रोटी-बैंक की मुहिम ने रफ्तार पकड़ ली है. अस्पताल के बाहर मरीजों के तामीरदार, सड़क पर रहने वाले गरीब, रेलवे स्टेशन के इर्द-गिर्द रहने वाले गरीब या झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग, सबों को रोटी-बैंक के जरिए खाना उपलब्ध हो रहा है. पाटकर कहते हैं कि हम तब तक ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहते जब तक कि हम यह सुनिश्चित न कर लें कि खाना बरबाद नहीं होगा और यह जरूरतमंदों तक पहुंचेगा.

feedback@chauthiduniya.com

चार साल जनता को बनाया बेवकूफ, पांचवें साल फिर मेढकों की तरह लगे फुदकने

रायबरेली के लोगों को चाहिए राजनीतिक विकल्प

डॉ. पंकज सिंह/रवींद्र सिंह

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने नए-नए मापदंड गढ़ने शुरू कर दिए हैं. रायबरेली में भी खहर के खलीफे मैदान में सक्रिय नजर आने लगे हैं. गांधी-नेहरू परिवार का गढ़ मानी जाने वाली रायबरेली की सरजमीं पर बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो चुका था. सपा ने छह में से पांच विधानसभा सीटों पर काबिज होकर अपनी साइकिल की रफ्तार बरकरार रखी. लोगों का भारी समर्थन पाकर सपाई सीटें तो जीत गए, लेकिन लगभग पांच साल बीतने को है, साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे विधायक हवा में उड़ने लगे और जनता की कोई सुध नहीं ली, उल्टे, लोगों के दुख-दर्द को कम करने के बजाय उसे बढ़ाया ही.

उत्तर प्रदेश सरकार ने रायबरेली के एक विधायक को कैबिनेट में जगह देकर मान बढ़ाया परंतु रायबरेली के विकास का ये माननीय कोई मान नहीं रख सके. उनकी नजरें अपनी ही जेब भरने और सुविधाएं मजबूत करने पर लगी रहीं. सपा विधायक अपने कार्यकाल में कहीं जबरन जमीन कब्जियाने के विवाद में तो कभी ठेकेदारी और रंगदारी के विवाद में उलझे रहे. इस काल अवधि में विधायक पुत्रों व भाइयों ने जनता के बीच जमकर तांडव किया तो प्रशासन भी असहाय होकर तमाशा देखने पर ही मजबूर रहा. जनता के बीच पिछले चार साल में इन सफेदपोशों की उपस्थिति लगभग शून्य ही रही. इतना ही नहीं सत्ताविहीन सफेदपोश तो मानो कोमा में ही चले गए थे. 2017 का विधानसभा चुनाव उन्हें जैसे ही नजदीक आता दिखा, सभी खद्दरधारी बरसाती मेढ़कों की तरह जनता के बीच आकर फिर से फुदकने लगे. पूरे कार्यकाल में सपा के सफेदपोशों ने त्राहिमाम मचाए रखा, वहीं कांग्रेस और बसपा घोर निद्रा में सोती रही. बहकी-बहकी भाजपा दिशाहीन ही नजर आती रही. इस तरह रायबरेली की जनता के दरबार में सभी पार्टियां फ्लॉप साबित हुई हैं. अब देखना यह है कि इन सात माह के दौरान कौन-कौन नेता जनता की नजरों में अपने आप को क्या-क्या साबित कर पाता है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने रायबरेली के एक विधायक को कैबिनेट में जगह देकर मान बढ़ाया परंतु रायबरेली के विकास का ये माननीय कोई मान नहीं रख सके. उनकी नजरें अपनी ही जेब भरने और सुविधाएं मजबूत करने पर लगी रहीं. सपा विधायक अपने कार्यकाल में कहीं जबरन जमीन कब्जियाने के विवाद में तो कभी ठेकेदारी और रंगदारी के विवाद में उलझे रहे.

बीते जिला पंचायत व विधान परिषद् के चुनावों में सत्तासीन समाजवादी पार्टी की जमकर किरकिरी हुई. संगठन की एकता का भांडा भी फूटा. जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए रायबरेली में कांग्रेस व सपा आमने-सामने थी. जिसमें सपा प्रत्याशी प्रभात साहू को जिताने का हाईकमान की तरफ से निर्देश भी जारी हुआ था. जिसके बाद रायबरेली के पांचों विधायक व संगठन के कार्यकर्ताओं ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन कुल 52 मतों में से महज 20 मत सपा प्रत्याशी प्रभात साह को मिल सके.

वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अवधेश सिंह 30 मत पाकर विजयी घोषित हुए थे. इसी तरह विधान परिषद् सदस्य के चुनाव में सपा से मुकेश सिंह, कांग्रेस से दिनेश सिंह और भाजपा से सुरेंद्र बहादुर सिंह ने ताल ठोकी थी. परंतु ऐन मौके पर सपा संगठन व स्वार्थी विधायकों ने मुकेश की नाटकीय ढंग से उम्मीदवारी ही समाप्त करवा दी और स्वयं जाकर दूसरे दल के नेताओं की गोद में बैठ गए. इस चुनाव में एक बार फिर मैनेजमेंट का महारथी माने जाने वाले दिनेश ने भाजपा के सुरेंद्र को 597 मतों से मात देते हुए जीत हासिल की. इस चुनाव में कुल 2085 मत पड़े थे, जिसमें 1264 मत दिनेश को और 667 मत भाजपा के सुरेंद्र सिंह को मिले थे. जबकि सपा प्रत्याशी मुकेश को महज 42 मत ही प्राप्त हुए. इस तरह सपा के दिग्गजों व संगठन की एकता की हवा निकल गई. हालांकि राजनीति के जानकार यह भी बताते हैं कि सपा नेतृत्व ने कांग्रेस के साथ मिलीभगत करके जिला पंचायत और विधान परिषद् दोनों गुपचुप तरीके से कांग्रेस को दे दिया. कांग्रेस ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सपा नेतृत्व के समक्ष गुहार लगाई थी.

बहरहाल, सपा, बसपा और कांग्रेस को ढोती आ रही जनता नये विकल्प के लिए आतुर है. कांग्रेस मुखिया सोनिया गांधी जहां खुद जनता का प्रतिनिधित्व कर रहीं हों, राहुल खुद जहां की नुमाइंदगी करते हों, वहां की जनता आज भी बिजली, पानी व सड़क की मूलभूत समस्याओं से जूझ रही हो, यह किस तरह की उपलब्धि है? अब सार्वजनिक स्तर पर उछल रहे ये सवाल निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं हैं. बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सभी विधायकों को पटखनी देकर जहां जनता ने कांग्रेस को सुधरने का मौका दिया वहीं सपा को रायबरेली की जनता के लिए कुछ करने का मौका भी दिया, लेकिन बीते समय में न ही कांग्रेस अपना रुख सकारात्मक करते हुए जनता के बीच दिखी और न सपा जनता की नजरों में अपनी छवि कायम रख पाई. बहुत पहले से दिशाहीन रही भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रही है. रायबरेली में भाजपा का कोई ढंग का जनप्रतिनिधि भी नहीं रहा. फिलहाल जनता इन परंपरागत पार्टियों के झूठे आश्वासन व सफेदपोशों के आतंक से त्रस्त होकर रायबरेली में इस बार बदलाव के संकेत दे रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

पानी के अभूतपूर्व संकट के बीच प्रतापगढ़ की विलुप्त नदी को जिंदा करने की अभूतपूर्व सीख

फिर से कलकल बहने लगी बकुलाही नदी

पूरे देश में पानी के संकट और नदी-तालाबों के सूखते चले जाने की भीषण त्रासदी के बीच बकुलाही ने अकुलाहट कम कर दी है. उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के एक छोटे से क्षेत्र में लोगों ने अथक परिश्रम करके लुप्त हो चुकी बकुलाही नदी को फिर से जिंदा कर लिया है. बकुलाही नदी फिर से कलकल बहने लगी है. इस पहल और प्रयास से अगर आपको कोई सीख मिलती हो तो उसे ग्रहण करें और अपने-अपने क्षेत्र में ऐसी नदियों और तालाबों का पुनरुद्धार करने में लग जाएं. लोगों को साथ लें और किसी नदी, किसी तालाब या किसी कुएं को जिंदा कर लें. फिर देखें आपके और आपकी कई पीढ़ियों के जीवन में खुशियां किस तरह झरने की तरह झरझर बहने लगेंगी. बकुलाही नदी पुनरुद्धार अभियान के संयोजक समाज शेखर ने मौके से जो रिपोर्ट भेजी है, बड़ी प्रेरणादायी है. उन्होंने बकुलाही के पुनरुद्धार की जो सार्थक पहल की और जो लोग इस जन-अभियान से जुड़े, उसके लिए उन्हें चौथी दुनिया की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं...

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भयहरणनाथ धाम के पास स्थित बकुलाही नदी की 18 किलोमीटर लंबी लुप्तप्राय हो चुकी प्राचीन धारा को जिंदा कर लिया गया है. अब वह फिर से पुनर्नवा होकर सजल वेग से प्रवाहित हो रही है. करीब दो दर्जन से अधिक गांवों के लाखों लोगों की वर्षों की अतृप्त प्यास बुझ रही है. नदी पर जगह-जगह समाज के सहयोग से फिर से बांस की चहली बन रही है और लोग उससे इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आ-जा रहे हैं. बकुलाही के पुनरुद्धार से पूरे नदी क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल है. जगह-जगह लोग एकत्र होकर नदी का नजारा देख रहे हैं, अवरोध हटा रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं.

प्रतापगढ जनपद के दक्षिणांचल के करीब 50 गांवों में आज केवल एक ही मुद्दा है, बकुलाही के पुनरुद्धार का. बकुलाही के समक्ष सारे मुद्दे गौण हैं. बकुलाही पुनरुद्धार की पहल की गई तो यह बात कल्पना से भी परे थी कि दो-ढाई दशकों से पानी के लिए तरसती लाखों की आबादी इस तरह उद्वेलित होगी कि बकुलाही को सदानीरा बनाने का अभियान जन आन्दोलन का रूप ले लेगा. उल्लेखनीय है कि आज से तकरीबन 30 वर्ष पहले बकुलाही नदी की प्राकृतिक धारा से छेड़छाड़ की गई थी. यह छेड़छाड़ नैसर्गिक नहीं बल्कि राजनीतिक थी. बकुलाही नदी की धारा को 25 वर्ष पहले कुछ निहित स्वार्थों की खातिर बीच से 'लूप कटिंग' कर तकरीबन 18 किलोमीटर छोटा कर दिया गया था. 18 किलोमीटर लम्बी बकुलाही नदी की मूलधारा का अपहरण कर लिया गया था. 18 किलोमीटर के दायरे में जलधारा के तट पर बसे 50 गांवों से उनकी नदी उनसे छीन ली गई थी. तब से लगातार पूरे तोरई, पूरे वैष्णव, जदवापुर, सरायदेवराय डीहकटरा, छतौना, मनेहू, हिंदुपुर, बाबूपुर, सरायमेदीराय, बरईपुर, मिश्रपुर, सिउरा, हैसी, बुकनापुर, पनई का पूरा, शोभीपुर, जमुआ, वैरीसाल का पुरवा, रामनगर, भटपुरवा, ढेमा और गौरा समेत दर्जनों गांवों की खुशियां छिन गई थीं. जल स्तर धीरे-धीरे पातालमुखी हो गया. सिंचाई के लिए फसलें तरसने लगीं. वन क्षेत्र उजाड़ होने लगे. प्रवासी पक्षियों ने पलटकर देखना बंद कर दिया. तकरीबन चार दर्जन गांवों की लगभग दो-ढाई लाख आबादी के बीच अपनी नदी बकुलाही को फिर से पाने की ललक और पानी की प्यास बढ़ती गई. जब इसके पुनरुद्धार का प्रयास शुरू हुआ तो लाखों प्यासे लोगों को मानो संजीवनी मिल गई. फिर तो कदम से कदम जुड़ते गए. हाथ से हाथ मिलते गए.

लोग चाहें तो क्या नहीं हो सकता!

बकुलाही नदी पुनरुद्धार अभियान में जब लोगों का हुजूम काम में लगा था, बांध पर मिट्टियां डाली जा रही थीं, जेसीबी मशीनें नदी को साफ करने में लगी थीं, प्रशासन जनता के साथ धरातल पर सहयोग कर रहा था तो राज और समाज एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रित हो गया था. इस साझा संस्कृति ने भविष्य के कई रचनात्मक कार्यों की तरफ संकेत दिया है. राज ने मनरेगा समेत कई प्रशासनिक सहयोग की शक्ति झोंक दी तो समाज ने अपनी सामुदायिक शक्ति परवान चढ़ा दी. नतीजा बकुलाही की निर्मल बहती जलधारा और लोगों की खुशियों से भरी किलकारियों के रूप में सामने है. ऐसा ही कहीं और भी तो हो सकता है!

वेदों में जिक्र है इस नदी का

बकुलाही नदी अति प्राचीन वेद वर्णित नदी है. इस नदी का प्राचीन नाम 'बालकुनी' था, किन्तु बाद में परिवर्तित होकर 'बकुलाही' हो गया. बकुलाही शब्द लोक भाषा अवधी का शब्द है. जनश्रुति के अनुसार बगुले की तरह टेढ़ी-मेढ़ी होने के कारण भी इसे बकुलाही कहा जाता है. बकुलाही नदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के भरतपुर झील से हुआ. वहां से चलती हुई यह नदी बेंती झील, मांझी झील और कालाकांकर झील से जलग्रहण करते हुए बड़ी नदी का स्वरूप प्राप्त करती है. प्रतापगढ़ मुख्यालय के दक्षिण में स्थित मान्धाता ब्लॉक को हरा-भरा करते हुए यह नदी आगे जाकर खजुरनी गांव के पास गोमती नदी की सहायक सई नदी में मिल जाती है. बकुलाही नदी का संक्षिप्त वर्णन वेद पुराण तथा कई धर्मग्रंथों में है. महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण में बकुलाही नदी का उल्लेख किया गया है. वाल्मीकि रामायण में बकुलाही नदी का जिक्र इस प्रकार है कि जब भगवान राम के वन से वापस आने की प्रतीक्षा में व्याकुल भरत के पास हनुमान जी राम का संदेश लेकर पहुंचते हैं. हनुमान जी से भरत जी पूछते हैं कि मार्ग में उन्होंने क्या-क्या देखा. इस पर हनुमान जी का उत्तर होता है, सो अपश्यत राम तीर्थम् च नदी बालकुनी तथा बरूठी / गोमती चैव भीमशालम् वनम् तथा बकुलाही नदी का वर्णन श्रीभयहरणनाथ चालीसा (पंक्ति क्रमांक-2%) में भी है, बालकुनी इक सरिता पावन / उत्तरमुखी पुनीत सुहावन।।.

बकुलाही की इस 18 किलोमीटर की मूलधारा के बीच सुरसा राक्षस अवरोधक की तरह मुंह फाड़े खड़ी हैं. यह राक्षस हैं गेल इंडिया की पाइप लाइन. नदी के बीच से गुजरने वाली पाइप लाइन बिछाने के मानक अलग होते हैं. लेकिन गेल इंडिया की पाइप लाइन बिछाने के पूर्व ही बकुलाही की धारा का अपहरण हो चुका था. जिसका नतीजा हुआ कि गेल इंडिया ने बिना पानी की नदी देख कर सारे कायदे-कानून ताक पर रख दिए और नदी में पाइप लाइन डाल दिया.

पहले जन जागा, फिर जनसमूह जाग गया. फिर जनसैलाब उमड़ने लगा. भूजल दिवस निकट था. बकुलाही-पुत्रों ने संकल्प उठाया और उसे यथार्थ कर दिखाया. बकुलाही पंचायत का निर्णय मील का पत्थर साबित हुआ. लोगों ने भूजल सप्ताह के पूर्व ही नदी का नजारा बदल डाला. श्रमदान को आन्दोलन से जोड़कर बकुलाही नदी पर कच्चा बांध बनाया गया और नदी की धारा को उसके प्राकृतिक मार्ग पर जाने के लिए घुमाया गया. 18 किलोमीटर लम्बे नदी के पुराने मार्ग में जितने भी अवरोध आए उसे हटाते हुए 25 वर्षों बाद बकुलाही मैया अपने बेटों के साथ चल पड़ी. परिणामतः बकुलाही में हुआ जल संचयन जनपद का ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण बन गया. लोगों ने जिस जगह कच्चा बांध बनाकर यह अनूठा प्रयोग किया वह शासन की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है. अब उसी स्थान पर पक्का चेक डैम बनाकर 18 किलोमीटर लम्बा जल संचयन कर 50 गांवों के लाखों लोगों को पानी देकर उनकी प्यास बुझाई जा सकती है, उनकी हरियाली लौटाई जा सकती है.

बकुलाही की इस 18 किलोमीटर की मूलधारा के बीच सुरसा राक्षस अवरोधक की तरह मुंह फाड़े खड़ी है. यह राक्षस है गेल इंडिया की पाइप लाइन. नदी के बीच से गुजरने वाली पाइप लाइन बिछाने के मानक अलग होते हैं. लेकिन गेल इंडिया की पाइप लाइन बिछाने के पूर्व ही बकुलाही की धारा का अपहरण हो चुका था. जिसका नतीजा हुआ कि गेल इंडिया ने बिना पानी की नदी देख कर सारे कायदे-कानून ताक पर रख दिए और नदी में पाइप लाइन बिछाने का मानक पूरा नहीं कर, वैसे ही पाइप लाइन डाल दिया. बकुलाही के पुनरुद्धार के बाद अब गेल इंडिया की नींद टूटी है, लेकिन अब वह अपनी गलतियां कैसे सुधारे, इसे लेकर ही संशय है. ऐसे में इलाके के लोग मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से इतने बड़े जन-अभियान को स्थायित्व मिल सके. पक्का चेक डैम बनाकर बकुलाही की दोनों धाराओं को बहाल रखने का प्रशासन का निर्देश भी ठंडे बस्ते में ही पड़ा है.

बहरहाल, अभी फिलहाल बकुलाही नदी की 18 किलोमीटर की प्राचीन धारा के पुनरुद्धार का सामाजिक कार्य पूरा हो चुका है. जन सहयोग से पिछले छह वर्षों के अथक प्रयास से नदी को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है. आवश्यकतानुसार खुदाई का कार्य हुआ है. कुछ कार्य मनरेगा से भी हुआ है. प्राचीन धारा में जल धारा को डायवर्ट करने के लिए जन सहयोग से सौ मीटर लम्बा और 15 फिट ऊंचा मिटटी का बांध बनाया गया है. इसमें एक साल लगा. अभी श्रमदान कर बांध पर सौ ट्रॉली मिट्टी फिर से डाली गई है. अब बरसात होगी तब पूरे प्रवाह के साथ एक बार फिर नदी अपने पुरानी मौज में बहने लगेगी. इसका लाभ यहां की प्रकृति के सभी जीव जन्तुओं को मिलेगा. प्राचीन धारा में पानी डायवर्ट होने से नदी का बहाव मन्द होगा और नदी सदानीरा बनी रहेगी और बरसाती नदी के कलंक से भी उसे मुक्ति मिलेगी.

पिछले लंबे अर्से से बकुलाही के पुनरुद्धार का काम हो रहा था. इलाके के लोगों ने भी इस पहल में खूब साथ दिया. गौरा में नदी मार्ग में बाधक पाइपों को जनसहयोग से हटवाया गया. सरायदेवराय व बाबूपुर में स्थानीय कार्यकर्ताओं और प्रधानों के साथ रणनीति बनाई गई. छतौना के ग्राम प्रधान मनोज कुमार और पूरेतोरई के प्रधान रामपूजन ने भी इस जन-अभियान में पूरा साथ दिया. प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी विद्या भूषण ने लोगों का भरपूर साथ दिया और इस समेकित प्रयास का परिणाम है कि बकुलाही की मुख्य धारा में बिना किसी बांध के यहां के लोग पर्याप्त अमूल्य जल प्राप्त कर रहे हैं. अभियान के सदस्यों का कहना है कि सब लोग मिल कर सालभर इस नदी को हर प्रयास से जीवित रखेंगे, जैसे-जैसे नदी घटती जाएगी, मुख्य धारा को प्राचीन धारा में मोड़ दिया जाएगा. इससे अब क्षेत्र में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी. इस जन-अभियान में ग्रामीण अभियंत्रण के अवर अभियंता संजय सिंह, ग्राम प्रधान पूरेतोरई रामपूजन पटेल, छतौना प्रधान मनोज कुमार, बाबूपुर प्रधान शंकर लाल, सरायदेवराय प्रधान मोती लाल, गौरा प्रधान कमलाकांत, ग्राम विकास अधिकारी नरेंद्र दुबे, सच्चिदानंद पांडेय वगैरह के सहयोग उल्लेखनीय हैं.

भयहरणनाथ धाम परिसर व धाम के पीछे स्थित प्राचीन शिवगंगा तालाब पर संयुक्त मजिस्ट्रेट संजय कुमार खत्री के निर्देश पर खंड विकास अधिकारी सावित्री देवी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत पूरेतोरई द्वारा सघन रूप से वृक्षारोपण भी किया गया. इसमें लोगों का सक्रिय सहयोग रहा. यहां कुल 80 वृक्षों का रोपण किया गया, जिसमें जामुन, कंजी, गूलर, शीशम आदि शामिल हैं. पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी स्थानीय सच्चिदानंद पांडेय ने संभाली है. पूरे अभियान के दौरान धाम परिसर में मानस मर्मज्ञ पं. कमलेश नारायण त्रिपाठी द्वारा मानस कथा की संगीतमय प्रस्तुति होती रही. इस आयोजन में भयहरणनाथ धाम क्षेत्रीय विकास संस्थान के उपाध्यक्ष राजनारायण मिश्र व देवी प्रसाद मिश्र ने प्रमुख भूमिका निभाई. ■

feedback@chauthiduniya.com

मिथकीय चरित्रों का बोलबाला

अनंत विजय

एक तरफ जहां हिंदी साहित्य लेखन में एकरसता जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और लगभग एक ही ढर्रे पर कहानी, कविता और उपन्यास लिखे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों ने विषयों की विविधता को लेकर खासे प्रयोग किए. हिंदी में पुरातन भारतीय चरित्रों और मिथकीय चरित्रों पर लिखने को एक खास विचारधारा ने सांप्रदायिकता से जोड़ दिया. उसी मिथकीय चरित्रों पर लिखकर अंग्रेजी के लेखकों ने न केवल प्रसिद्धि पाई बल्कि करोड़ों रुपये भी कमाए. भगवान शंकर के चरित्र चित्रण को लेकर अमिष त्रिपाठी ने जितनी प्रसिद्धि पाई वो हिंदी के लेखकों के लिए फिलहाल तो अकल्पनीय नजर आती है. बाबा भोलेनाथ पर ट्रायोलॉजी लिखकर अमिष ने अंतराष्ट्रीय स्तर पर अपने लेखन की न केवल पहचान बनाई बल्कि जमकर पैसे भी कमाए. उसकी इस सफलता के बाद एक प्रकाशन गृह ने उनसे करोड़ों रुपये अग्रिम देकर आने वाली किताबों को छापने का अधिकार खरीदा था. तब देशभर के अखबारों में यह करार सुर्खियां बनी थी. हिंदी के विचारधारा युक्त साहित्यकार अमिष त्रिपाठी को लाख खारिज करें, लेकिन उन्होंने अपना एक पाठक वर्ग तैयार किया और अपने तमाम साक्षात्कार में वो भगवान शंकर के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर बात करते हैं. अमिष इस हिंदु देवी देवता पर बात करने से बिल्कुल नहीं हिचकते हैं. उन्हें इस बात की भी चिंता नजर नहीं आती है कि हिंदू देवी देवताओं के चरित्र पर बात करने वालों को संघी मान लिया जाता है. वो बेबाक होकर कहते हैं कि आज उनके पास जो कुछ भी है वो बाबा भोलेनाथ की कृपा से है. अंग्रेजी में सिर्फ अमीष त्रिपाठी ही नहीं हैं जो मिथकीय चरित्रों पर लिखते हैं. अभी हाल ही में देवदत्त पटनायक की एक किताब शिखंडी एंड अदर टेल्स दे डोंट टेल यू देखने को मिली. देवदत्त पटनायक भी लगातार भारतीय मिथकीय चरित्रों को अपने लेखन का विषय बनाते हैं. देवदत्त पटनायक हेल्थकेयर में नौकरी करने के बाद लेखन की ओर मुड़े थे और उन्होंने शिव, विष्णु, हनुमान, लक्ष्मी भारत की देवियां स्वतंत्र रूप से किताबें लिखीं और उनकी सारी किताबें पाठकों ने खासी पसंद की. उनकी किताबों का हिंदी में भी अनुवाद हुआ और हिंदी के पाठकों ने भी अमिष के उपन्यासों की तरह पटनायक की किताबों को भी हाथों हाथ लिया. हमारे देश की युवा पीढ़ी बेहद चाव से इन मिथकीय चरित्रों को पढ़ना जानना चाहती है. अच्छी बात यह है कि इन लेखकों में कइयों ने इन मिथकीय चरित्रों को आधार बनाकर बाल साहित्य भी रचा. पटनायक की ही करीब आधा दर्जन किताबें बच्चों को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं जो उनके बीच लोकप्रिय हैं. अब तो इन मिथकीय चरित्रों और उनके प्रबंधन कौशल को आधुनिक प्रबंधन से जोड़कर किताबें लिखी जा रही हैं. चाहे वो शंकर हों या विष्णु या कृष्ण का चरित्र. क्राइसिस के दौरान उनके प्रबंधकीय कौशल को लेकर या संकट से निबटने के उनके सूत्रों को आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत के तौर पर पेश कर किताबें लिखी जा रही हैं.

हिंदी साहित्य में स्थिति इसके बिल्कुल उलट है. हिंदी में नरेंद्र कोहली ने राम पर लिखना शुरू किया तो उनको रामकथा मर्मज्ञ और आगे बढ़कर जब उन्होंने महाभारत पर अपने लेखन का फोकस किया तो उनको धार्मिक लेखक कहकर साहित्य की तथाकथित मुख्यधारा से अलग रखा गया. विपुल लेखन करने वाले नरेंद्र कोहली को लाखों पाठक तो मिले पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के योग्य नहीं समझा गया. कोहली

अंग्रेजी में जिस तरह से भारतीय मिथकीय चरित्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई किताबें युवा पाठकों को लुभा रही हैं वह इस बात को साबित करती हैं कि आज की युवा पीढ़ी की रुचि धर्म की ओर बढ़ रही है. इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आज हमारी युवा पीढ़ी जो अपनी संस्कृति के बारे में जानना चाहती है, उस विचारधारा को परखना चाहती है, जो हमारे देश में पहले से मौजूद थी. हिंदी के लेखकों ने तो मराठी के लेखक शिवाजी सावंत से भी सीख नहीं ली.

को आज तक उनके श्रम और लेखन के हिसाब से हिंदी साहित्य में वो प्रतिष्ठा नहीं मिली, जिसके वो हकदार हैं. उम्र के पचहत्तरवें पड़ाव को पार करने के बाद भी लगातार वो भारतीय पौराणिक मिथकीय चरित्रों को अपने लेखन का विषय बना रहे हैं. धर्म को अफीम मानने वाली विचारधारा को यह सोचना चाहिए कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले को भारतीय मानस की न तो समझ है और न ही यह सिद्धांत भारत के लिए मुफीद है. विदेशी सिद्धांत को भारतीय साहित्य पर लागू करवाने की जिद ने धर्म और मिथक पर लिखने वालों को दोयम दर्जे का लेखक करार देने की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई. हिंदी और अंग्रेजी लेखन का यह अलग-अलग चरित्र समझने की जरूरत है. दरअसल भारतीय अंग्रेजी लेखन किसी भी तरह की विचारधारा के अधिनायकवाद से स्वतंत्र है और वो विषयों को पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर चुनता है और उस पर लेखन करता है. हिंदी की स्थिति अंग्रेजी से बिल्कुल उलट है. यहां अब भी विचारधारा विशेष का दबदबा है और उसके दायरे से बाहर लेखन करने वालों को हाशिए पर डाल दिया जाता है. ज्यादातर उन्हीं लेखकों को सम्मान और साहित्यिक यश आदि मिलता है जो विचारधारा की बेड़ियों में रहकर लेखन करते हैं. विचारधारा के दायरे से बाहर लेखन करने वालों को नीचा दिखाने की कोशिश होती रही है. इसका नतीजा यह रहा कि नए लेखकों ने सफलता के इस शॉर्टकट को अपनाया और विचारधारा युक्त लेखन की ओर प्रवृत्त होते चले गए. विषयों की विविधता के अन्वेषण की बजाए उन्हीं विषयों पर लिखा जो कि हिंदी साहित्य में स्वीकृत थी. नए लेखकों ने इस चौहद्दी को तोड़ने की कोई कोशिश नहीं की. निर्मल वर्मा और अज्ञेय ने इस दायरे को तोड़ा तो उनको भी साहित्यक कॉमरेडों ने नहीं बख्शा. दिनकर को भी नहीं. अभी एक गोष्ठी में मैंने, कविता में यथार्थ की खुरदरी जमीन पर पाठकों के लहूलुहान होते रहने का सवाल उठाया था. यह इस वजह से ही हुआ कि हिंदी के नए लेखक विषयगत नवीनता की ओर उन्मुख नहीं हो पाए. उनके सामने नरेंद्र कोहली, निर्मल वर्मा, अज्ञेय और दिनकर का उदाहरण था. निर्मल वर्मा ने तो इस साहित्यक बेइमानी पर लिखा भी है. जिस मार्क्सवादी स्वर्ग का बखान हमारे हिंदी के अधिकांश लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी बरसों से करते आए हैं, उसके भीतर झांकने की बौद्धिक ईमानदारी शायद ही किसी ने अपनी लेखकीय जिम्मेदारी समझ कर बरती हो. यह जानते हुए भी कि राजा नंगे हैं, अपनी आंखें बंद रखना ही उन्होंने सुविधाजनक समझा. इससे उन्होंने दो सुख एक साथ प्राप्त कर लिए. वह राजनीतिक रूप से सही, पॉलिटिकली करेक्ट भी बने रहे और सत्य बोलने के खतरों से भी बचे रहे. भारत के मार्क्सवादियों ने पिछले वर्षों में नए रंग पोतने और पुराने धब्बों को पोंछने में जो हस्तकौशल दिखाया, वह आश्चर्यजनक है. यहां निर्मल वर्मा साफ तौर पर संकेत करते हैं कि साहित्य में किस तरह से विचारधारा विशेष के लेखकों ने बेइमानियां की.

अंग्रेजी में जिस तरह से भारतीय मिथकीय चरित्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई किताबें युवा पाठकों को लुभा रही हैं वह इस बात को साबित करती है कि आज की युवा पीढ़ी की रुचि धर्म की ओर बढ़ रही है. इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आज हमारी युवा पीढ़ी जो अपनी संस्कृति के बारे में जानना चाहती है, उस विचारधारा को परखना चाहती है, जो हमारे देश में पहले से मौजूद थी. हिंदी के लेखकों ने तो मराठी के लेखक शिवाजी सावंत से भी सीख नहीं ली. अगर हमारे लेखक मृत्युंजय की लोकप्रियता को ही देख लेते तो आज हिंदी का विस्तार कहीं अधिक हो रहा होता. आज इस बात का अफसोस भी है कि हमारी नई पीढ़ी बाबा भोलेनाथ, इच्छवाकु, राम, विष्णु जैसे चरित्रों को समझने के लिए अमिष त्रिपाठी और देवदत्त पटनायक को पढ़ने की जरूरत हो रही है. हिंदी में इन पर विपुल साहित्य मौजूद हैं, लेकिन इनको धर्म की किताबें बताकर हाशिए पर डालने वालों ने अमिष और देवदत्त जैसे लेखकों के लिए लेखन की उर्वरक जमीन तैयार की. आज हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि हिंदी में मौजूद मिथकीय साहित्य अंग्रेजी के रास्ते फिर से अनुदित होकर हिंदी में आ रहा है और लाखों की कमाई कर रहा है. वहीं मूल हिंदी में इनको छापने वाली संस्था गीता प्रेस बदहाली के दौर से गुजर रही है. क्या हिंदी उस औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त हो सकेगी. इन सवालों के साथ विचार तो इस पर भी किया जाना चाहिए कि हिंदी में मिथकीय चरित्रों पर लिखी गई पुस्तकों को पाठकों से दूर करने वाले कौन लोग हैं. उनको साहित्य में चिन्हित कर उनसे भी इस बाबत जवाब मांगा जाना चाहिए. जब तक सार्वजनिक रूप से इस साजिश को बेनकाब नहीं किया जाएगा, तब तक हिंदी साहित्य को उसका उचित हक नहीं मिल पाएगा. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.vbn@gmail.com

अशोक

परिचय

यह भारतीय वनौषधियों में एक दिव्य रत्न है. भारतवर्ष में इसकी कीर्ति का गान बहुत प्राचीनकाल से हो रहा है. श्री सीता माता जी को लंका में प्राय: एक वर्ष तक इसी वृक्ष के नीचे रावण ने रखा था. प्राचीनकाल में प्रसन्नता एवं शोक को दूर करने के लिए अशोक वाटिकाओं एवं उद्यानों का प्रयोग होता था और इसी आश्रय से इसके नाम शोकनाश, विशोक, अपशोक आदि रखे गए हैं. सनातनी वैदिक लोग तो इस पेड़ को पवित्र एवं आदरणीय मानते ही हैं, किन्तु बौद्ध भी इसे विशेष आदर की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म अशोक वृक्ष के नीचे हुआ था. इसका सम्बन्ध कामदेव से भी है. पुष्प धन्वा कामदेव के पंचपुष्प बाणों में अशोक पुष्प की भी गणना की गई है और इसके पर्यायवाची नामों में स्मराधिवास, नट आदि नाम भी सम्मिलित किए हैं. अशोक के वृक्ष भारतवर्ष में सर्वत्र बाग-बगीचों में तथा सड़कों के किनारे सुंदरता के लिए लगाए जाते हैं. भारत के हिमालयी क्षेत्रों तथा पश्चिमी प्रायद्वीप में 750 मी की उंचाई पर मुख्यत: पूर्वी बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में साधारणतया नहरों के किनारे व सदाहरित वनों में पाया जाता है. मुख्यतया अशोक की दो प्रजातियां होती हैं, जिनका प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है.

बाह्य-स्वरूप

अशोक- यह लगभग नौ मी उंचा, मध्यमाकार का सुंदर सदाहरित, छायादार वृक्ष होता है. इसकी कांड एवं शाखाएं अनेक तथा फैली हुई होती हैं, छाल गहरे भूरे से धूसर वर्ण की होती है. औषधि रूप में पेड़ की छाल का ही अधिक प्रयोग किया जाता है. इसके पत्र 5-25 सेमी लंबे तथा नोंकदार होते हैं. कोमलावस्था में यह श्वेताभ लाल वर्ण के परंतु बाद में गहरे हरे रंग के हो जाते हैं. पत्रकों के किनारे किंचित लहरदार होते हैं. इसके पुष्प नारंगी अथवा नारंगी-पीत वर्ण के, सिंदूरी वर्ण में परिवर्तित, अनेक, अत्यधिक सुगन्धित,

गुच्छों में, 7.5-10 सेमी व्यास के होते हैं. इसकी फली चपटी, कृष्ण वर्ण की, चर्मिल, 10-25 सेमी लंबी, 3.5-5 सेमी चौड़ी, दोनों ओर संकुचित, सिरायुक्त होती है. इसके बीज 4-8, 3.8 सेमी लम्बे, 2.5-3.7 सेमी व्यास के चपटे होते हैं. पेड़ के काण्डत्वक् से श्वेत रस निकलता है, जो शीघ्र ही वायु में सूखकर लाल हो जाता है. यही अशोक का गोंद होता है. इसका पुष्पकाल मार्च से अप्रैल तक तथा फलकाल अगस्त से अक्टूबर तक होता है.

नकली अशोक- इसका सदाहरति, सीधा तथा सुन्दर 15-20 मी उंचा वृक्ष होता है. असली अशोक के समान इसकी शाखाएं सघन नहीं होती हैं. इसका कांड सीधा एवं चिकना होता है. इसकी छाल धूसर-भूरे वर्ण की तथा पतली होती है. नवीन शाखाएं पतली तथा अरोमश होती हैं. इसके पत्र चमकीले हरित वर्ण के, 12.5-20 सेमी लंबे एवं 2.5-5 सेमी चौड़े होते हैं. वृक्ष के काफी बड़े हो जाने पर कई वर्षों बाद वर्षाकाल में इसमें आम के बौर जैसे पुष्प लगते हैं. इसके पुष्प 2.5-3.8 सेमी व्यास के, सघन, पीताभ-हरित वर्ण के होते हैं. फल छोटे, अंडाकार, एक बीजी, हरे, पक्वावस्था में बैंगनी वर्ण के तथा अरोमश होते हैं. इसका पुष्पकाल फरवरी से मई तक तथा फलकाल जुलाई से सितंबर तक होता है.

आयुर्वेदीय गुण-कर्म एवं प्रभाव

अशोक

- अशोक लघु, रूक्ष, कसैला, चरपरा, विपाक में कटु और शीतल होता है. यह ग्राही, रक्त-संग्राहक, वेदना-स्थापक, वर्ण को उज्जवल करने वाला, हड्डी जोड़ने वाला, सुगन्धित, हृद्य, त्रिदोषहर, तृषा, दाह, कृमि, शोथ, गुल्म, शूल, उदर रोग, आधमान, विष, अर्श, रक्त-विकार, गर्भाशय की शिथिलता, सर्व प्रकार के प्रदर, ज्वर, संधिवातज पीड़ा और अपच आदि रोगों का नाशक है. इसका प्रयोग कष्टार्तव, रक्तपित्त, अश्मनी तथा मूत्रकृच्छ्र में करते हैं. अशोक की छाल कटु, तिक्त, ज्वर व तृषा नाशक, आंत्रसंकोचक, अपच की बीमारी को दूर करने वाली, रक्त-विकार, थकावट, शूल, अर्श इत्यादि रोगों में लाभदायक है. इसके अतिरिक्त पेट बढ़ने की बीमारी, अत्यधिक रक्तस्राव तथा गर्भाशयगत रक्तस्राव में उपयोगी है. इसकी छाल का स्वरस बहुत संकोचक एवं रक्तप्रदर शामक है.
- अशोक के बीज मूत्रल होते हैं.
- अशोक के पुष्प रक्तजप्रवाहिका नाशक होते हैं.
- अशोक की कांडत्वक् तिक्त, तीक्ष्ण, शैत्यकारक, स्तम्भक, विषघ्न, कृमिरोधी, विशोधक, मृदुकारी, अजीर्ण, तृष्णा, दाह, रक्तविकार, काण्ड-भग्न, उदरशोग, अर्श, व्रण, श्रम तथा गर्भाशयगत रक्तस्त्राव स्तम्भक होती है.

जारी...

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

शांति केवल गुरु-कृपा द्वारा संभव

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

मनुष्य के आशंकाग्रस्त एवं अशांत जीवन में शांति कैसे लाई जाए?

आशंका और अशांति की उत्पत्ति या तो भौतिक द्रव्य से होती है या तो अन्य सामाजिक, पारिवारिक विसंगतियों से होती है अथवा अपने ही विचारों और भावधारा के कारण होती है. इन तीनों में से प्रथम प्राकृतिक आपदा एवं बीमारी, द्वितीय सांसारिक जंजाल तथा तृतीय मन का अज्ञान है. विज्ञान द्वारा प्राकृतिक आपदाओं तथा बीमारी से बचने के लिए आदमी रास्ता ढूंढ़ रहा है, पर किसी भी विज्ञान द्वारा इन दो (प्राकृतिक आपदा तथा बीमारी) को सम्पूर्ण रूप से नियंत्रण में लाना संभव नहीं है. यह तो जगत बीती बातें हैं, जो सब को प्रभावित करती हैं, केवल आपबीती नहीं. मानव-समाज इसलिए जिंदा है कि वह अपनी बुद्धि के प्रयोग से प्राकृतिक आपदाओं एवं बीमारियों से किसी प्रकार बचा रहा. इसीलिए हर व्यक्ति को अपने को विपत्ति और बीमारी से बचाने के लिए एक संतुलित जीवनधारा को अपनाना पड़ेगा. सांसारिक जंजाल में घुसने के पीछे आदमी की अपनी कामनाएं, वासनाएं काम करती हैं. वह पहले अपने लिए पत्नी, पुत्र, कुटुम्ब आदि को लेकर एक पारिवारिक संगठन बनाता है और आशा करता है कि यह संगठन उनको सुख दे, दु:ख नहीं. इस प्रकार की विचारधारा उसको दु:खी रखती है, जैसे कि बंदर का हाथ घड़े के अन्दर जाने पर बाहर नहीं आ पाता है और बंदर उस घड़े को लेकर परेशान होकर कूदता रहता है. आत्मा जब जीव का रूप धारण कर लेती है, तब जीवन में दो गुण आ जाते हैं, वे हैं-आवरण एवं विक्षेप. जीव अपनी आत्मा की दिव्यता को नहीं समझ पाता है. यहां पर जीव के ज्ञान के ऊपर परदा पड़ गया है. अब यह जीव उस असीमित, निर्गुण और सच्चिदानंद रूपी आत्मा से निकलकर स्वयं को बद्ध जीव समझता है और परिवार कुटुम्ब, समाज आदि से बंधा हुआ रहता है. इसी को ही शास्त्र में श्री विष्णु माया भी कहा गया है. सारे सांसारिक जंजाल इस विष्णु माया से उत्पन्न होते हैं. श्री साईंनाथ जैसे सद्गुरु के पास जितने भी आदमी जाया करते थे या आज जितने भी भक्त हैं, वह ज्ञानवश या अज्ञानवश इस विष्णुमाया से निकलने के लिए प्रयासरत हैं. केवल सद्गुरु ही इस माया-शक्ति का आवरण हटाकर भक्तों को सही मार्ग पर लाने में सक्षम हैं. अपने सीमित बुद्धि के मायावी खेल से निकलकर अगर कोई व्यक्ति सद्गुरु की शरण में सम्पूर्ण रूप से जाए और उनके बताए हुए मार्ग पर चले, तभी वह क्रमशः शांति-लाभ प्राप्त कर सकता है.

वस्तुवादी जगत् में समृद्धशाली एवं प्रभावशाली होने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. यद्यपि उन्हें कुछ पदवी या समृद्धि प्राप्त होती है, फिर भी उनको शांति नहीं मिल पाती. फलतः समाज में एक अशांति

की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, इसका मूल कारण क्या है?

श्री साईं-सच्चरित्र को पढ़ने से इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा जो कि दृष्टांतों पर ही आधारित है. दुख का कारण क्या है? दुख का निवारण कैसे किया जा सकता है? इसके बारे में शाक्यमुनि गौतमबुद्ध ने बताया है. चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदु धर्म या बौद्ध धर्म, दु:ख का कारण इच्छा या प्रवृत्ति को बतलाया जाता है. प्रवृत्ति पूर्वजन्म के संस्कार और प्रारब्ध कर्म से ही उत्पन्न होती है. इच्छा-शक्ति द्वारा तृष्णा और प्रवृत्तियों का दमन करना ही असली रास्ता है. इसलिए हम लोगों को अपने आम जीवन में, वस्तु जगत में सब कुछ पाने के लिए इतना कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सारी जागतिक वस्तुएं चिरस्थायी नहीं हैं. जो चिरस्थायी हैं, वह है- हमारा पुण्य-कर्म, जो जन्म-जन्मांतर तक हमारा साथी है. पुण्य कर्म वही होगा जो दूसरों के लिए किया जाता है- चाहे वह आदमी हो या अन्य कोई और. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

मुश्किल दौर में भारतीय बॉक्सिंग

भारतीय बॉक्सिंग अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है. रियो ओलंपिक के लिए अब तक केवल एक मुक्केबाज क्वालीफाई कर सका है, इसके लिए राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन को लेकर पिछले तीन सालों से चल रही रस्साकशी जिम्मेदार है. खेल प्रशासन से जुड़े लोगों के हितों के सामने देशहित, खेलहित और खिलाड़ियों के हित गौण हो गए हैं.

नवीन चौहान

साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में विजेंदर सिंह ने बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता था. तब ऐसा लगा था कि इसके बाद भारतीय बॉक्सिंग जगत में क्रांति आ जाएगी. बीजिंग के चार साल बाद लंदन ओलंपिक में एमसी मेरीकॉम ने कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था. लगातार दो ओलंपिक में बॉक्सिंग में मिले पदक देश के युवाओं को बॉक्सिंग की ओर आकर्षित कर रहे थे और इस बात की तसदीक कर रहे थी कि भारतीय बॉक्सिंग और बॉक्सरों का भविष्य उज्ज्वल है. लेकिन मजह चार साल बाद रियो ओलंपिक के आते-आते हमारे मुक्केबाज़ असहाय नज़र आ रहे हैं, एक तरफ ओलंपिक के आयोजन में 60 दिन से भी कम समय बचा है और अब तक शिव थापा के रूप में केवल एक भारतीय मुक्केबाज़ ओलंपिक कोटा हासिल कर सका है. जबकि लंदन ओलंपिक में आठ और बीजिंग में पांच भारतीय मुक्केबाज़ों ने भाग लिया था. आखिर इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है?

बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता विजेंदर सिंह के प्रोफेशनल बॉक्सिंग का रुख करते ही, रियो ओलंपिक में पदक के लिए लोगों की नज़रे एक बार फिर पांच बार की विश्व चैंपियन और लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता एमसी मेरीकॉम की ओर मुड़ गईं थीं. लंदन में पदक जीतने के बाद मेरीकॉम ने अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया और कई महीनों तक बॉक्सिंग रिंग से दूर रहीं. दो साल बाद ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों से वह रिंग में वापसी करना चाहती थीं. लेकिन वह ट्रायल में पिंकी झांगर से हार गईं और तीन सदस्यीय भारतीय दल में शामिल नहीं हो सकीं. पिंकी के साथ सरिता देवी और पूजा रानी ने ग्लासगो में भारत का प्रतिनिधित्व किया था.

इसके बाद दक्षिण कोरिया के इंचियोन शहर में हुए एशियाई खेलों में मेरीकॉम ने भाग लिया और महिलाओं की 51 किग्रा फ्लाईवेट स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया. फाइनल मुकाबले के दौरान उनके कंधे में चोट लग गई, इस कारण साल 2015 में उन्हें पूरे सीजन रिंग से बाहर रहना पड़ा. दिसंबर 2015 में उन्होंने एक बार फिर वापसी की और रियो में हुए ओलंपिक ट्रायल इवेंट के सेमी-फाइनल में जगह बनाई, लेकिन सेमी-फाइनल में हार की वजह से ओलंपिक के लिए अपनी जगह सुनिश्चित नहीं कर सकीं. इसके बाद उन्हें रियो ओलंपिक के लिए अपनी जगह पक्की करने का दूसरा मौका दो महीने पहले चीन के क्वीआन में आयोजित एआईबीए एशिया और ओशिएना चैंपियनशिप में मिला था. यहां भी वह सेमी-फाइनल से आगे नहीं बढ़ सकीं. सेमी-फाइनल में चीनी मुक्केबाज़ रेन कैंकन के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा और यह मौका भी उनके हाथ से निकल गया. इसके बाद कजाखस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में उनके पास ओलंपिक टिकट हासिल करने का आखिरी मौका था. रियो जाने के लिए उन्हें इस बार कम से कम सेमी-फाइनल में जगह बनानी थी, लेकिन उन्हें दूसरे दौर में जर्मनी की अजीजे निमानी ने 2-0 के अंतर से हराकर करोड़ों भारतीयों के अरमानों पर पानी फेर दिया. इसके साथ ही मेरीकॉम का ओलंपिक चैंपियन बनने का सपना भी धराशाई हो गया.

साल 2012 में लंदन ओलंपिक में भाग लेने वाला भारतीय बॉक्सिंग दल. फोटो-प्रभात पाण्डेय

मेरीकॉम के अलावा भी अन्य महिला मुक्केबाज भी ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने में असफल रहीं. अस्ताना में चल रही विश्व चैंपियनशिप में मेरीकॉम के अलावा अन्य दो मुक्केबाजों सरिता देवी और पूजा रानी की ओर सभी की नज़रें थीं, लेकिन ये दोनों भी ओलंपिक कोटा हासिल नहीं कर सकीं. महिलाओं के 60 किग्रा वर्ग में सरिता देवी को भी दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा. जबकि 75 किग्रा वर्ग के दूसरे दौर में पूजा रानी का सामना साल 2012 की विश्व चैंपियन ब्रिटेन की सवाना मार्शल से हुआ, पूजा ने ग्लासगो एशियाई खेलों में महिलाओं के 75 किग्रा वर्ग का कांस्य पदक हासिल किया था. उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा. उनकी हार से भारत की महिला बॉक्सिंग की अंतिम आशा भी धूमिल हो गई. इस विश्व चैंपियनशिप में रियो ओलंपिक के लिए 12 कोटा स्थान निर्धारित होने थे. यदि इन तीनों बॉक्सरों में से कोई भी सेमी-फाइनल तक पहुंचता, उसे ओलंपिक कोटा हासिल हो जाता.

जो हाल महिलाओं का है कुछ वैसा ही पुरुषों का भी है. शिव थापा को छोड़कर अब तक अन्य कोई मुक्केबाज़ ओलंपिक कोटा हासिल नहीं कर सका है. साल 2008 में बीजिंग में पांच पुरुष मुक्केबाजों ने ओलंपिक कोटा हासिल किया था. जिनमें से विजेंदर सिंह सेमी-फाइनल और जितेंदर और अखिल कुमार क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे. विजेंदर को कांस्य पदक हासिल हुआ था. बीजिंग की सफलता के बाद लंदन के लिए सात पुरुष मुक्केबाज़ों ने ओलंपिक कोटा हासिल किया. इनमें से विजेंदर सिंह और देवेंद्रो सिंह क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे. इस बार पुरुष मुक्केबाज़ों की झोली खाली रही थी.

इस बार आशा की जा रही थी कि 27 वर्षीय मनोज कुमार आसानी से ओलंपिक कोटा हासिल कर लेंगे. मनोज लंदन ओलंपिक में प्री-क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे. वहां उन्हें विवादास्पद तरीके से विश्व के नंबर एक खिलाड़ी ब्रिटेन के चॉम स्टालकर के हाथों पराजय मिली थी. उन्होंने पिछले साल दोहा इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 64 किग्रा वर्ग का स्वर्ण पदक भी हासिल किया था. लेकिन इसके अलावा कोई अन्य बड़ी उपलब्धि उनके हाथ नहीं लगी है. मनोज के अलावा देवेंद्रो सिंह, सुमित सांगवान और विकास कृष्णन से भी आशा है कि वे जून में होने वाले क्वालीफायर्स में जीत हासिल कर रियो के लिए अपनी जगह पक्की कर लेंगे. यह पुरुषों के लिए आखिरी क्वालीफाइंग प्रतियोगिता है. यदि इसमें टिकट पाने के दबाव में भारतीय मुक्केबाज़ बिखर गए तो रियो से बॉक्सरों की झोली खाली लौटने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और सारा दबाव शिव थापा के कंधों पर आ जाएगा.

बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता विजेंदर सिंह के प्रोफेशनल बॉक्सिंग का रुख करते ही, रियो ओलंपिक में पदक के लिए लोगों की नज़रे एक बार फिर पांच बार की विश्व चैंपियन और लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता एमसी मेरीकॉम की ओर मुड़ गईं थीं. लंदन में पदक जीतने के बाद मेरीकॉम ने अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया और कई महीनों तक बॉक्सिंग रिंग से दूर रहीं. दो साल बाद ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों से वह रिंग में वापसी करना चाहती थीं. लेकिन वह ट्रायल में पिंकी झांगर से हार गईं और तीन सदस्यीय भारतीय दल में शामिल नहीं हो सकीं.

लंदन ओलंपिक के बाद दिसंबर 2012 में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज़ी संगठन (एआईबीए) ने इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन (आईएबीएफ) को चुनावों में गड़बड़ी की आशंका की वजह से अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया था. इसके बाद विभिन्न राज्य इकाइयों के बीच हुई खींचातानी के बाद सितंबर 2014 में नव गठित संस्था बॉक्सिंग इंडिया (बीआई) के चुनाव एआईबीए के पर्यवेक्षक की उपस्थिति में संपन्न हुए. इससे पहले बीआई को एआईबीए ने अस्थाई मान्यता दे दी थी, इसके बाद ही भारतीय मुक्केबाज़ एशियाई खेलों में भारतीय झंडे के नीचे भाग ले सके थे, लेकिन मई 2015 को बॉक्सिंग इंडिया के अध्यक्ष संदीप जाजोदिया को विशेष बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा दिया गया. आईएबीए द्वारा बॉक्सिंग इंडिया को मान्यता दिए जाने के बावजूद भारतीय ओलंपिक संघ ने बॉक्सिंग इंडिया को मान्यता नहीं दी और मुक्केबाज़ी के लिए स्व गठित एडहॉक समिति को भंग नहीं किया. जबकि एआईबीए ने आईएओ को एडहॉक (तदर्थ) समिति को भंग करने के निर्देश दिए थे. अभी भी राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.

पिछले तीन-चार सालों में फेडरेशन को लेकर अनिश्चित्ता बनी रही, ऐसे में न तो नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हो सका और न ही मुक्केबाजों की समस्याओं का समाधान हुआ. नए खिलाड़ियों को फेडरेशन के सहयोग की सबसे ज्यादा आवश्यक्ता होती है. पिछले चार साल में देश में बॉक्सिंग की किसी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा का आयोजन भी नहीं हुआ. ऐसे में खिलाड़ियों के सामने असमंजस की स्थिति खड़ हो गई. खिलाड़ी अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते थे वह उन्होंने एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में कर दिखाया.

इस बार ओलंपिक क्वालिफिकेशन के नियमों में भी फेर बदल किए गए थे. राष्ट्रीय फेडरेशन के न होने की वजह से मुक्केबाजों को इन नियमों की सही तरह से जानकारी भी नहीं हो पाई, न ही उन्हें इसके हिसाब से ट्रेनिंग मिल सकी. नेताओं और खेल प्रशासकों के अहम का खामियाजा आज मुक्केबाज़ों को भुगतना पड़ रहा है. यदि 2012 में मुक्केबाज़ी संघ के चुनाव सही तरह से हुए होते तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते. ओलंपिक का आयोजन चार साल में एक बार होता है हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह ओलंपिक पदक जीते. हर कोई यह जानता है कि खेलों में ओलंपिक से बड़ा और कुछ नहीं होता. खेल प्रशासकों ने अपनी हठधर्मिता से देश के युवा मुक्केबाज़ों का सपना तोड़ा है. आज नहीं कल राष्ट्रीय संघ का गठन हो जाएगा. परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, लेकिन जो नुकसान खिलाड़ियों का हुआ है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी. इन्हीं वजहों से कई बार लोग खेलों का प्रशासन खिलाड़ियों के हाथों में देने की वकालत करते हैं, क्योंकि वे ही खिलाड़ियों का दर्द सही तरीके से समझ सकते हैं. समय किसी के लिए नहीं रुकता इस बात से सभी वाकिफ हैं खिलाड़ियों के लिए उम्र सबसे ज्यादा मायने रखती है खिलाड़ियों का जो समय गुज़र गया है वह लौटकर वापस नहीं आएगा.

इन सभी वजहों से आज मुक्केबाज़ी की स्थिति बेहाल है. ओलंपिक सिर पर है और खिलाड़ियों के पास स्पॉन्सर नहीं हैं. जिन खिलाड़ियों को भारत सरकार की टॉप्स स्कीम या ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट जैसी संस्था से मदद मिल रही है उन्हें अपनी आधारभूत जरूरतों के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ रहा है. लेकिन बाकी मुक्केबाजों का तो भगवान ही मालिक है. यदि स्थितियां ऐसी ही बनी रहीं तो देश के अधिकांश खिलाड़ी विजेंदर की राह पर चलते हुए प्रोफेशनल बॉक्सिंग की ओर रुख कर लेंगे. यदि ऐसा हुआ तो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले मुक्केबाज़ों का टोटा हो जाएगा. इस स्थिति के लिए खिलाड़ियों को दोषी नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि उनके पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचेगा. लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय मुक्केबाज़ी इतने बड़े झटके के बाद फिर से उबर सकेगी. फिलहाल कोई सुधार होता दिखाई नहीं पड़ रहा है.■

navinonline2003@gmail.com

फ्लैशबैक

पहली नज़र में ही शर्मिला टैगोर को दिल दे बैठे थे नवाब पटौदी

शर्मिला टैगोर भारतीय फिल्मों की सशक्त अभिनेत्री रही हैं. शर्मिला टैगोर का जन्म हैदराबाद में एक बंगाली हिंदु परिवार में हुआ था. उनके पिता गितेंद्रनाथ टैगोर एल्गिन मिल्स के ब्रिटिश इंडिया कंपनी के महाप्रबंधक थे. वर्ष 1959 में सत्यजीत रे की फिल्म अपुर संसार से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली शर्मिला ने 60 के दशक में ही बिकनी पहनकर लोगों को चौंका दिया था. उनकी शादी भारतीय क्रिकेट को ऊंचाईयों की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले मंसूर अली खान पटौदी से हुई है. नवाब पटौदी से विवाह के बाद शर्मिला टैगोर ने अपना नाम आयशा सुल्तान रख लिया. 1 मार्च 1967 को उनकी मंगनी हुई और 27 दिसंबर, 1969 को बाल्य डेर स्टेट कोलकाता में शादी. शर्मिला और पटौदी की शादी में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन और इंदिरा गांधी भी शामिल हुई थीं.

फिल्मों में अपने श्रेष्ठ अभिनय से वह दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई. फिल्मकार शक्ति सामंत ने अपनी रोमांटिक फिल्म कश्मीर की कली (1964) में शर्मिला को कलाकार शम्मी कपूर के साथ पेश किया. उसके बाद सावन की घटा फिल्म में शर्मिला ने बिकनी पहन कर तहलका मचा दिया. एक अंग्रेजी फिल्म पत्रिका के कवर पर बिकनी में छपा शर्मिला का पोज अनेक लोगों को खासकर बंगाल के भद्रलोक को नागवार गुजरा. सेक्स-सिम्बल के रूप में शर्मिला का बॉलीवुड में मार्केटिंग सफल भी रहा.

उस दौर के दर्शक निम्मी, मीना कुमारी, माला सिन्हा, वहीदा रहमान के परिचित चेहरों से बाहर आकर कुछ अलग देखना और महसूस करना चाहते थे. शर्मिला ने सिर पर पल्लू धारण करने वाली और ललाट पर बड़ा-सा लाल टीका लगाने वाली नायिकाओं की परम्परा को तोड़ा.

राजेश खन्ना के साथ शर्मिला की जोड़ी काफी लोकप्रिय हुई. फिल्म आराधना, अमर प्रेम तथा सफर फिल्मों के जरिए रजतपट पर प्रेम-प्यार को नए एंगल से परिभाषित किया गया. राजेश खन्ना की परदे पर सफलता के पीछे, परदे के पीछे से किशोर कुमार की जादू भरी आवाज़ का ही यह कमाल था कि वह लाखों दिलों की धड़कन बन गए.

शर्मिला की प्रमुख फिल्मों में अनुपमा (1966), देवर (1966), एन इवनिंग इन पेरिस (1967), आराधना (1969), सत्यकाम (1969), तलाश (1969), सफर (1970), अमर प्रेम (1971), बंधन (1971), छोटी बहू (1971), आविष्कार (1973), दाग (1973), अमानुष (1974), चुपके चुपके, मौसम (1975), नमकीन (1982), दूसरी दुल्हन (1983), न्यू दिल्ली टाइम्स (1985), विरुद्ध (2005), जवैलरी बॉक्स (2006), एकलव्य (2007), तस्वीर 8 बाय 10 (2009), मार्निंग वॉक (2009) रहीं.

शर्मिला फिल्म सेंसर बोर्ड की चेयर परसन भी रही हैं. उनके कार्यकाल में फिल्म सेंसरशिप को उदारता मिली. नतीजा यह हुआ कि फिल्मों में किसिंग और बेडरूम-सीन आम होते चले गए. उन्होंने तो एक बार यह स्टेटमेंट जारी किया था कि टेलीविजन पर रात ग्यारह बजे के बाद एडल्ट मूवी दिखाई जा सकती है, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं. नवाब पटौदी के निधन के बाद वह अकेली जरूर हो गई हैं. मगर बेटा सैफ और दो बेटियों (सोहा व सारा) ने उन्हें संभाला.■

शाहिद-करीना नहीं आएंगे साथ

शाहिद कपूर और करीना कपूर खान ने इसी शर्त पर *उड़ता पंजाब* नामक फिल्म साइन की थी कि दोनों का एक भी दृश्य साथ नहीं होगा. ऐसा हुआ भी. ट्रेलर लांच पर दोनों एक ही मंच पर नज़र आए. असहज थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने इस कार्यक्रम को खत्म किया.

उड़ता पंजाब अब रिलीज के लिए तैयार है और फिल्म का प्रमोशन जोर-शोर से शुरू हो चुका है. कई इवेंट में कलाकार भी भाग ले रहे हैं. शाहिद और करीना ने फिल्म की मार्केटिंग टीम को स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कार्यक्रम बनाएं जिनमें दोनों साथ में न हो. यानी किसी कार्यक्रम में शाहिद दिखेंगे तो किसी में करीना.

शाहिद और करीना साथ में आकर किसी तरह का विवाद नहीं पैदा करना चाहते हैं. संभव है कि फिल्म से ज्यादा उनकी चर्चा हो. साथ में अजीबो गरीब प्रश्नों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बॉलीवुड के बादशाहों को कंगना का जवाब

बॉलीवुड के किसी भी खान के साथ अब तक किसी भी फिल्म में काम न करने को लेकर जो बात उन्होंने कही वह शायद सभी को हैरान करने वाली है. कंगना ने साफ-साफ कहा कि उन्हें कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए बॉलीवुड के खान एक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ी. वो आज जिस मुकाम पर हैं, वो अपने दम और काबिलियत पर हैं. अब यह देखना होगा कि कंगना की इस बात पर सबसे पहले कौन सा खान एक्टर कैसा रिएक्ट करता है.

●●●

इन दिनों हर किसी की जुबां पर बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत की बातें हैं. पहले रितिक रोशन के साथ विवाद को लेकर और अब तीसरा नेशनल अवॉर्ड जीतने की वजह से. फिल्म *तनु वेड्स मनु रिटर्न्स* के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड से सम्मानित किए जाने के बाद कई इंटरव्यू में उन्होंने खुद से जुड़े कई विवादित मुद्दों पर खुल कर बात की.

कंगना ने रितिक रोशन, अध्ययन सुमन से जुड़े विवादित मुद्दों के साथ ही अपने बॉलीवुड सफर पर भी बात की. इनमें अब तक बॉलीवुड के किसी भी खान स्टार के साथ काम नहीं करने से जुड़ी बात भी शामिल है. मगर आप भी जानकर उनके हिम्मत की दाद देंगे. यह भी कहेंगे कि वो यूं ही बॉलीवुड क्वीन नहीं हैं. जबकि सालों से सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं और हर एक्ट्रेस का उनके साथ काम करने का सपना होता है. शुरुआत में कंगना भी इन तीनों खान के साथ फिल्में करना चाहती थीं, मगर कभी मौका नहीं मिला. कंगना को उस वक्त कहा गया था कि अगर आप न्यूकमर हो और आपको किसी सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिल जाए तो आप भी सुपरस्टार बन सकती हो. कंगना ने यह तरीका अपनाने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं रहीं.

इस बारे में कंगना ने कहा कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. अब मुझे खान्स स्टार्स के साथ काम करने के बहुत ऑफर मिलते हैं, जब मैंने शुरुआत की थी तब कोई खान स्टार मेरे साथ काम करना नहीं चाहता था. तो क्या मुझे अब उनके साथ काम करना चाहिए?

बॉलीवुड के किसी भी खान के साथ अब तक किसी भी फिल्म में काम न करने को लेकर जो बात उन्होंने कही वह शायद सभी को हैरान करने वाली है. कंगना ने साफ-साफ कहा कि उन्हें कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए बॉलीवुड के खान एक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ी. वो आज जिस मुकाम पर हैं, वो अपने दम और काबिलियत पर हैं. अब यह देखना होगा कि कंगना की इस बात पर सबसे पहले कौन सा खान एक्टर कैसा रिएक्ट करता है. फिलहाल कंगना, विशाल भारद्वाज की फिल्म *रंगून* की शूटिंग में व्यस्त हैं. कंगना को इससे पहले *फैशन* और *क्वीन* के लिए नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है.■

"सेट्स पर मैं खुद अपनी हीरो हूं, तो मुझे दूसरे किसी हीरो के साथ काम क्यों करना चाहिए?"

1 सलमान ने शाहरुख को पछाड़ा

बॉक्स ऑफिस पर सफलता के मामले में सलमान खान ने शाहरुख खान को पछाड़ रखा है और अब टैक्स के मामले में भी वे किंग खान से आगे निकल गए हैं. बात बॉलीवुड स्टार्स की हो रही है. सलमान ने वित्त वर्ष 2014-15 में 26 करोड़ रुपये एडवांस टैक्स भरा था, लेकिन वित्त वर्ष 2015-16 में उन्होंने 32 करोड़ रुपये एडवांस टैक्स के रूप में भरे हैं और वह बॉलीवुड स्टार्स में एडवांस टैक्स भरने वालों की सूची में पहले नंबर पर हैं.■

2 अक्षय कुमार

2014-15 में अक्षय कुमार ने 23 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में जमा किए थे और 2015-16 में एडवांस टैक्स के रूप में उन्होंने 30 करोड़ रुपये जमा किए हैं. ■

3 रणबीर कपूर

2015-16 में रणवीर कपूर ने एडवांस टैक्स के रूप में 22.30 करोड़ रुपये जमा किए हैं. 2014-15 में उन्होंने 19.70 करोड़ रुपये जमा किए थे.■

4 शाहरुख खान

2014-15 में शाहरुख एडवांस टैक्स के रूप में 32 करोड़ रुपये जमा कराने के साथ पहले स्थान पर थे. उन्होंने इस बार 20 करोड़ रुपये एडवांस टैक्स के रूप में जमा किए हैं.■

5 आमिर खान

2014-15 में आमिर ने 15.80 करोड़ रुपये एडवांस टैक्स के रूप में जमा किए थे और इस बार उन्होंने 19.60 करोड़ रुपये जमा किया है.■

6 अमिताभ बच्चन

पिछले वर्ष अमिताभ 29.2 करोड़ रुपये के साथ दूसरे नंबर पर थे, इस बार 17.50 करोड़ के साथ वह छठे नंबर पर हैं.■

7 अजय देवगन

पिछले वर्ष के समान इस वर्ष भी अजय देवगन ने 5 करोड़ रुपये एडवांस टैक्स के रूप में जमा किए हैं.■

8 प्रियंका चोपड़ा

हीरोइन को कितनी कम रकम मिलती है यह इस सूची से स्पष्ट होता है. प्रियंका चोपड़ा को इस सूची में आठवां नंबर मिला है. प्रियंका ने 1.45 करोड़ रुपये 2015-16 में एडवांस टैक्स के रूप में जमा किए.■